हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

8 मार्च, 2011

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 8 मार्च, 2011

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
वॉक–आऊट	(3)10
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(3)10
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)27
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)31
अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(3)49
सचिव द्वारा घोषणा	(3)50
एस.वाई.एल. तथा हांसी–बुटाना योजक नहर के मामले पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित करने का मामला उठाना	(3)50
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
मेवात जिले में राजकीय विद्यालयों में शिक्षण अमले की भारी कमी संबंधी	(3)51
वक्तव्य–	
शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(3)52
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई	(3)58
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(3)61

मूल्य : 289

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(3)62
वृद्धावस्था पेंशन में बड़ी संख्या में अनियमितताओं संबंधी वक्तव्य–	(3)62
शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान	(3)69
बैठक का समय बढ़ाना	(3)101
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(3)101
बैठक का समय बढ़ाना	(3)108
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(3)108
बैठक का समय बढ़ाना	(3)114
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(3)114
बैठक का समय बढ़ाना	(3)122
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(3)123
वॉक–आऊट	(3)129
बैठक का समय बढ़ाना	(3)132
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(3)132
बैठक का समय बढ़ाना	(3)141
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)	(3)142
वर्ष 2010–11 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना	(3)144
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(3)144
वर्ष 2010–11 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(3)144

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 8 मार्च, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में सुबह 10.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Question Hour.

Construction of Bus Stand at Satnali

***534. Rao Bahadur Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that Bus Stand for Satnali was sanctioned four years ago ; if so, the time by which the construction work will start thereon and the time within which aforesaid Bus Stand is likely to be completed ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) : नहीं, श्रीमान जी। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिसम्बर 2006 में घोषणा की हुई है। ग्राम पंचायत से परिवहन विभाग को भूमि हस्तांतरित करने का मामला विचाराधीन है। निर्माण कार्य तभी आरम्भ होगा जब भूमि हस्तांतरित करने की औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगी।

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे महेन्द्रगढ़ जिले से और नारनौल डिपो से एक भी बस चण्डीगढ़ के लिए वाया रोहतक से होकर नहीं आती है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे एक बस वहां से चलाने का काम करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ में मेरी नांगल चौधरी कांस्टीच्यूएंसी में नांगल चौधरी से निजामपुर और नारनौल के लिए किसी भी बस डिपो से एक भी बस नहीं चलती तो क्या वहां के लिए भी मंत्री जी बस चलाने का काम करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी जो भी लिखकर देंगे और जहां के लिए भी कहेंगे वहां के लिए हम बस चालू कर देंगे । मैं सतनाली बस अड्डे के बारे में उनको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा । सतनाली बस अड्डे के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8.12.2006 को लोहारू की जनसभा में एनाउंसमैन्ट की थी लेकिन इसके लिए भूमि परिवहन विभाग के नाम अभी तक हस्तांतरित न होने के कारण यह कार्य अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सका है । निदेशक, विकास एवं पंचायत, हरियाणा ने 2.7.2008 को सूचित किया था कि नवीनतम नीति की श्रेणी दो के तहत यह भूमि परिवहन विभाग को हस्तांतरित की जा सकती है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने

[श्री ओम प्रकाश जैन]

17.11.2009 को फैसला किया कि परिवहन विभाग पंचायत की यह भूमि बाजारी कीमत देकर प्राप्त करे । तदानुसार उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ ने अपने पत्र कमांक नं0 7441/पंचायत दिनांक 8.2.2010 के तहत मामला निदेशक, विकास एवं पंचायत, हरियाणा को भेज दिया । इसके बाद निदेशक, विकास एवं पंचायत, हरियाणा ने पुन: अपने पत्र क्रमांक 22475 दिनांक 12.5.2010 द्वारा सूचित किया कि पंचायत भूमि की बाजारी कीमत 77 लाख रुपये प्रति एकड़ है और इसके अतिरिक्त इसका सालाना भुगतान अलग से करना होगा । उपायुक्त, महेन्द्रगढ़ ने अपने पत्रांक नं0 11672 दिनांक 4.6.2010 के द्वारा अनुरोध किया कि उपरोक्त भूमि के वर्तमान भाव पुन: निर्धारित करें क्योंकि निर्धारित कीमत 77 लाख रुपये प्रति एकड़ बहुत ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, जो बात सदस्य जानना चाहते हैं आप केवल वही बता दें ।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, वह बात तो हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न तो मंत्री जी को मालूम है फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी । पहले तो इनका यह जबाव आता था कि करनाल के बस स्टैंड को बनाने के लिए कंसलटैन्ट के टैंडर नहीं हुए लेकिन अब तो कंसलटैन्ट के टैंडर भी हो गये हैं । मंत्री जी ने वायदा किया था कि दिसम्बर में यह काम शुरू हो जाएगा । अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस है इसलिए मैं महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देती हूं । मुझे उम्मीद है कि इस दिवस पर मंत्री जी जो भी वायदा करेंगे उसको जरूर पूरा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं ।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं का ध्यान तो सभी को करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ध्यान तो सभी कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सबसे पहले अपनी बहन महिलाओं को महिला दिवस पर मुबारिकवाद देता हूं । आज मैं जो वायदा करूंगा वह पक्का करूंगा । जहां तक इनके सवाल की बात है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमने इनसे वायदा किया था कि दिसम्बर के अंदर हम इनके यहां के बस स्टैंड का काम शुरू कर देंगे । लेकिन वह फाईल अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विंग में गयी हुई है बहुत जल्द वह वहां से आ जाएगी । अध्यक्ष महोदय, अढ़ाई महीने के अंदर टैंडर करके इनका यह काम हम चालू कर देंगे क्योंकि हम पी.पी.पी. मोड में बीस बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं और उनमें हम इनका बस स्टैंड भी बनाएंगे ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेवात जिले में बस डिपो या बस का सब-डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन नहीं है । अभी हम पलवल और चरखीदादरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ।

चौधरी मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दफा हमने अखबारों में पढ़ा था कि हरियाणा सरकार ने काफी सारी बसें खरीदी हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेवात डिपो में भी नयी बसें शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। हल्का पुन्हाना और मेरे हल्के के गांव पिनगआ के बस अड्डे में बसें नहीं हैं । इसके अलावा क्या नूंह के बस अड्डे में भी नई बसें देने का विचार है ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जहां तक बसों का ताल्लुक है। हमने अभी 700 बसें खरीदी हैं, और हर महीने हम 80-90 बसें तैयार करते हैं । मैं इनको कहना चाहूंगा कि यदि कहीं बसों की ज़रूरत है तो ये हमें लिखकर दें, हम बसों की कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जहां भी कहेंगे, बसें चालू करेंगे।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि नूंह के अंदर बसों के सैपरेट डिपो को चालू कर देंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसराना में पिछले 10-12 वर्षों से बस स्टैण्ड तो बना हुआ है, लेकिन आज तक वहां बसों का ठहराव नहीं हुआ है। क्या उस बस स्टैण्ड में बसों के ठहराव के लिए विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मेरी भी इच्छा है कि वह बस स्टैण्ड चालू होना चाहिए और इसके लिए मैंने अपने विभाग के जी.एम. को आदेश दिये हैं । बहुत जल्द ही उस बस स्टैण्ड को ठीक ठाक करके बसें उसमें पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

Repair of Road

***543. Shri Bishan Lal Saini :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged road from Uncha Chandana (Yamunanagar) to Radaur via Kheri Lakha Singh?

PWD (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिस सड़क की उन्होंने चर्चा की है उसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट बना लिया है और बहुत जल्द ही उसको अप्रूवल देकर काम शुरू कर देंगे । ये ठीक है कि उस सड़क की स्थिति ठीक नहीं है । हमारी पूरी कोशिश है कि इस पीरियड के दौरान 31 मार्च, 2011 तक इस पर पूरा पैच वर्क हो जाए और ऐस्टीमेट बनकर कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाए । सैनी साहब ने ऐतराज किया था। सरकार ने उनके हल्के की 18 सड़कों की स्पेशल रिपेयर के लिए मंजूरी दी है जिनकी कुल लम्बाई 32.9 किलोमीटर है और जिन पर लगभग 310 लाख रुपये खर्च आएगा, ये सड़कें हैं :- रादौर मुस्तफाबाद टू सिल्ली कलां, सिल्ली

[Shri Randeep Singh Surjewala]

खुर्द टू दौलत, सिल्ली खुर्द टू मग्गू माजरा, रादौर मुस्ताफाबाद टू मुसाना जटटा, रादौर मुस्तफाबाद टू शाहबपुर, लाडवा मुस्तफाबाद टू महमूदपुर जमालपुर, रादौर मुस्ताफाबाद टू सतगोली, हरनौलखेड़ी लाखा सिंह टू अकबरपुर, करेरा खुर्द टू टिगरी, खेड़ा खुर्द टू मिसरी की माजरी, यमुनानगर खजूरी टू नाहरपुर, रादौर जठलाना रोड टू एच.बी. भागवाली, घालोर टू शहजादपुर वाया जोगी माजरा, शादीपुर जयपुर टू बहादुरपुर, शादीपुर जयपुर टू सुखपुरा, खांडवा टू सुखपुरा,एस.के.रोड टू रतनगढ़। इन सभी सड़कों के टैंडर भी कॉल कर लिए हैं और इनका निर्माण भी जल्द ही कराएंगे।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र होडल में होडल से खामी तक की सड़क को पक्का करने के लिए मैंने एक क्वैश्चन भी दिया था लेकिन वह क्वैश्चन लगा नहीं। होडल से खामी की सड़क बहुत ज्यादा टूटी पड़ी है इसको ठीक किया जाए । हम बृजवासी हैं इस पर हमें गर्व है। अध्यक्ष महोदय, आप भी भगवान की पूजा करते हैं और सभी सदस्य करते हैं । हमारे क्षेत्र में बृज की परिक्रमा निकलती है और उस परिक्रमा में राजस्थान, यू.पी., हरियाणा और दिल्ली तक के आदमी शामिल होते हैं । लेकिन वहां पर जो हरियाणा के अन्दर उस सड़क का भाग है वह टूटा पड़ा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे होडल से खामी की इस सड़क को पक्का करने का काम करेंगे ?

Mr. Speaker : Mr. Nayar, this is a separate question which you are asking.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हालांकि आपकी बात वाजिब है कि यह पृथक प्रश्न है । मैं माननीय सदस्य जी की चिन्ता से अपने आपको भी जोड़ता हूं । यह एक महत्वपूर्ण आवागमन का रास्ता भक्तों के लिए भी और दूसरे साथियों के लिए भी है । इन्होंने इसके निर्माण के बारे में कहा है । हम इस बारे में जांच करवाकर इसका एस्टिमेट भी जल्दी बनवायेंगें ।

श्री शेरसिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले अधिवेशन में लाडवा से शाहाबाद के रोड़ को बनवाने के लिए भी एक प्रश्न पूछा था । माननीय मंत्री जी ने इतने ही विस्तार से उसका जवाब दिया था जितना श्री बिशनलाल सैनी के प्रश्न का जवाब विस्तार से दिया है और इन्होंने यह वायदा किया था कि 31.12.2010 तक इस रोड़ की रिपेयर और मरम्मत का काम पूरा हो जायेगा । लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तारीख को वे कब तक आगे एक्सटैंड करना चाहेंगे ताकि मैं इल्के के लोगों को बता सकूं कि यह सड़क इतनी अवधि तक पूरी हो जायेगी ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह पृथक प्रश्न है परन्तु यह बात वाजिब है कि श्री शेरसिंह बड़शामी जी ने पिछले अधिवेशन में इस बारे में प्रश्न पूछा था । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले मार्च से हरियाणा प्रदेश में माईनिंग बन्द हैं इसलिए कोई स्टोन मैटल अवेलेब्ल नहीं था । हमने यह कहा था कि हम इस सड़क का निर्माण करेंगे ।

लाडवा से शाहाबाद सड़क के लिए 26 करोड़ 42 लाख का एस्टिमेट मन्जूर किया हुआ है और इसका कान्ट्रैक्ट एवार्डिड है। अब दो दिन पहले माननीय हाईकोर्ट ने टैम्परेरिली रिलीफ माईनिंग पर स्टे हटा दिया है । कल ही बड़शामी जी ने सदन में यह मामला उठाया था और कल ही हमने दोबारा इसको रिव्यू किया है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस सड़क का निर्माण 31.12.2011 तक पूरा कर देंगे ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2700 किलोमीटर की सड़कें हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रान्सफर की गई थीं और उनका जिम्मा पी.डब्ल्यू.डी. ने लिया था कि हम इनकी रिपेयर कर देंगे । आज साल-डेढ़ साल का समय हो गया है लेकिन अभी तक इन सड़कों की रिपेयर का काम शुरू नहीं किया गया है । जबकि मार्केटिंग बोर्ड ने दस करोड़ रुपये पी.डब्ल्यू.डी. को इस काम के ऐवज में दिये थे, जबकि वह बजट थोड़ा था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2700 किलोमीटर की जो सड़कें हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रान्सफर की गई थीं, उन सड़कों की रिपेयर कब तक की जायेगी ।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, this is a separate question.

श्री देवेन्द्र कुमार बन्सल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंचकूला के अन्दर जो बरवाला ब्लॉक पड़ता है । बरवाला के आस-पास के 22 गाँव हैं वहां इन सवा साल में पी.डब्ल्यू.डी. ने कोई सड़क नहीं बनाई और जब भी हम पूछते हैं तो यह जवाब आता है कि बना रहे हैं । कहीं तो रोड़े डालकर छोड़ दिए जाते हैं और कहीं इन्होंने उसको डिग करके छोड़ दिया है। क्या ये सड़कें कभी बनाई जायेंगी क्योंकि ग्रान्ट आई हुई है। पैसा भी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ दिया हुआ है ।

Mr. Speaker : Mr. Bansal, this is a separate question.

Regularization of Colonies

***445. Shri Jagdish Nayar** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize Shyam Colony, Gaudota Road Fatak Colony, Ward No. 4 Adarsh Colony and Kunda Colony of Hodal city of Hodal constituency; and

(b) if so, the time by which the above said colonies are likely to regularize?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : (क एवं ख) होडल शहर की श्याम कालोनी, गौडोता रोड फाटक कालोनी, वार्ड नं. 4 आदर्श कालोनी तथा कुण्डा कालोनी को

[श्री गोपाल काण्डा]
नियमित करने हेतु नगरपालिका होडल द्वारा, मंत्री परिषद् की दिनांक 21.8.2009 को अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु स्वीकृत नीति के आधार पर विचार किया जा रहा है। उपायुक्त, पलवल से सिफारिश प्राप्त होने उपरान्त इन कालोनियों के नियमितीकरण पर सरकार द्वारा नीति मापदण्ड के अनुसार विचार किया जायेगा।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैने जिन कालोनियां का जिक्र किया है ये होडल की मुख्य कालोनियां हैं जो अभी तक अनियमित हैं। पिछले चुनावों में पार्टी के अध्यक्ष ने वायदा किया था कि हम शहरों को सुंदर बनाएंगें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है और सड़कें भी टूटी पड़ी हैं । लोग गांवों से भी बुरा जीवन बिता रहे हैं । वहां कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन कालोनियों को नियमित किया जाए और अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा। इस काम को डेट बाउंड किया जाए ।

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, शहरों को सुंदर बनाने का विचार हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी का सारे हरियाणा के लिए है न कि होडल के लिए । उसी वायदे के अनुसार जो अनअथोराइज्ड कालोनियां हैं उनको लीगलाइज ढंग से एप्रूव करेंगे । हमारे पास पूरे हरियाणा से 1320 कालोनियों की फाइल आई हुई है जोकि अनअथोराइज्ड हैं । उनमें सही कितनी हैं इसकी जांच करवाने के लिए हमने इन सभी कालोनियों की सैटेलाइट से इमेज और पिक्चर ली है ताकि बिना पक्षपात के सही कालोनियों को एप्रूव किया जा सके । नियमानुसार 50 परसैंट से ज्यादा जो कालोनियां बनी हुई हैं उन्ही को रैगुलराइज किया जा सकता है । अगर इनकी कालोनियां इन नियमों के अंतर्गत आएंगी तो उनको जल्दी से जल्दी नियमित किया जाएगा ।

Construction of Bus-Stands

***480. Shri Mamu Ram :** Will the Transport Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Bus-Stands in Nilokheri and Trawri; and

(b) if so, the time by which the abovesaid Bus-Stands are likely to be constructed ?

परिवहन मंत्री (श्री ओम प्रकाश जैन) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पहले से ही बने हुए बस अड्डे जैसे जुलाना का, उचाना का और चीका का तथा ऐसे 16-17 बस स्टैंड्स और हैं जहां पर बसों का आवागमन

नहीं है यानि ये बस स्टैंड्स फंक्शनल नहीं हैं । क्या मंत्री जी बताएंगें कि उनको कब तक फंक्शनल किया जाएगा ?

Mr. Speaker : Majra ji, I think it is a separate question.

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, हमारे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है और अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे साथी लिखकर दे दें हम इस बारे कार्यवाही कर लेंगें।

Mr. Speaker : Majra ji, give in writing in this regard, the Hon'ble Minister will take care of it.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे मोरनी शहर में 6 मिनी बसें चलाने का आश्वासन दिया गया था कि ये बसें शीघ्र चलाई जाएंगी लेकिन ये बसें अभी तक नहीं चलाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगर ये बसें चलाई जाएंगी तो कब तक चलाई जाएंगी ?

श्री ओम प्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने वायदा किया था उसके अनुसार ये बसें परचेज कर ली हैं और बहुत ही जल्दी ये बसें चालू कर दी जाएंगी।

Amount of Compensation

***553. Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the amount of compensation fixed by the Government in various Districts for acquiring the land together with the criteria thereof ?

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी कृष्ण पाल गुर्जर ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है । आज के दिन चारों तरफ हुड्डा सरकार की वाह-वाही हो रही है । मेरे साथी मेरे से पूछना चाहते हैं कि What is the rate? First of all, I want to tell him a good information. इनके यहां के 6 गांवों के जो किसान भूख हड़ताल पर बैठे थे उनमें से 95 परसैंट लोगों ने 25.05 लाख रुपये के हिसाब से कम्पनसेशन ले लिया है और वे भूख हड़ताल से उठ गए हैं । जहां तक फ्लोर रेट की बात है, Minimum Floor Rates were fixed by the Government. The amount of compensation has been distributed by considering the floor rates in five zones but not districtwise. In five zones (Interruption) अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित करने का क्राइटेरिया यह है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट की धारा 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना से एक वर्ष के दौरान रजिस्टर हुए बयनामों तथा उस क्षेत्र के लिए बयनामों पर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करने के उद्देश्य से कलैक्टर रेट्स और रिहैबिलिटेशन और रिसैटलमैंट नीति के तहत न्यूनतम फलोर रेट्स को ध्यान में रखा जाता है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 से पहले किसानों को जो मुआवजा दिया

[श्री सतपाल सांगवान]

जाता था उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि Minimum Floor Rate in Gurgaon for acquiring the land that was Rs.15 lac per acre. (Interruption) The Minimum Floor Rate in the NCR region and पंचकुला जो चण्डीगढ़ की पैरीफेरी है, उस समय 12.50 लाख रुपये प्रति एकड़ और दूसरी जगहों पर 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था । हमारी सरकार आने के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जो फलोर रेट्स रिवाईज किए, अब उन रेट्स की पूरे देश में वाह-वाही हो रही है । अब हमारे प्रदेश में किसानों को उनकी जमीन के उचित रेट दिए जा रहे हैं । (Interruption) The floor rate on 7.9.2010 of land situated in Gurgaon Municipal Corporation i.e. Rs. 40 lac per acre and the land situated in the limit of Faridabad Municipal Corporation, Panchkula Municipal Corporation, Gurgaon, Manaser Urban Complex, Municipal Corporation Sohna & Sonipat was Rs. 30 lac per acre. One more good information that I am going to give because you have put a question. The area which was outside the Municipal Corporation of Faridabad firstly, it was coming under Rs. 20 lac per acre but our worthy Chief Minister has considered it and now it has come under Rs. 30 lac per acre.

Mr. Speaker: He wants to ask a supplementary. (Interruption)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त मंत्री जी ने प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के रेट्स के बारे में बताया है । यह इनकी मजबूरी है कि जो सरकार कहेगी वही ये बतायेंगे लेकिन आज भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे प्रदेश के किसानों में रोष है ।

Mr. Speaker : Ask a specific question.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल केवल मेरा ही नहीं है बल्कि ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे सदस्यों का भी यही सवाल है ।

Mr. Speaker : You are asking a starred question. So, you can ask a supplementary but can't make a speech.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल दोस्त मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार मुआवजा तय करते समय कलैक्टर रेट, रजिस्ट्री रेट और कभी-कभी मार्केट रेट भी कंसीडर करती है । यह भी लिखा है कि उस एरिया में जो हाई रेट्स हैं . . . . . (विघ्न)

Mr. Speaker : That is a separate question.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं यह बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद, गुडगांव और पंचकूला में इससे एक साल पहले कितने रेटों पर रजिस्ट्रियां हुई । दूसरा मेरा सवाल यह है कि वहां स्टॉम्प ड्यूटी प्रति एकड़ कितनी थी और क्लैक्टर रेट क्या था ?

Mr. Speaker : No, this is a separate question.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां कितने रेटों में रजिस्ट्रियां हुई या मार्किट रेटों में कितनी रजिस्ट्रियां हुई और कलैक्टर रेटों में कितनी रजिस्ट्रियां हुई? इसके साथ ही यह भी बता दिया जाये कि उस समय स्टॉम्प ड्यूटी रेट क्या था ? तीसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन जिलों में मार्किट रेट और कलैक्टर रेट कम था क्या वहां पर ज्यादा मुआवज़ा दिया गया ?

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, हमारी सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी और इंसैंटिव किसानों को दिये जा रहे हैं उससे विपक्ष के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है । जो हमारी सरकार ने सबसे बढ़िया काम किया है वह यह है कि किसानों को एन्युटी देने का प्रावधान किया है जिसके तहत किसानों को 33 साल तक . . . . . (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

Shri Satpal Sangwan : Speaker Sir, when I am replying to question of Shri Gurjar then why he is interrupting between it. I am replying his question. (Interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री गुर्जर जी से प्रार्थना है कि वे मंत्री जी को उनके द्वारा पूछे गए सवाल का पूरा जवाब तो देने दें । वे कृपया बीच-बीच में इंटरप्ट न करें । Mr. Gurjar, you cannot interrupt the Minister.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, (विघ्न)

Mr. Speaker : I think they know each other well. Gurjar ji, I am happy with your question and also happy with the answer of the Hon'ble Minister. Now, next question please. (Interruption) Mr. Gurjar, when he is answering your question you got up and started talking. This is not fair. I will allow him to complete his answer but you would not allow him to complete his answer.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, बाकी सारी चीज़ें तो हमें मालूम है लेकिन जो हमारा सप्लीमैंट्री क्वैश्चन है हमें उसका रिप्लाई चाहिए ।

Mr. Speaker : Mr. Gurjar, when the Minister is answering your question you got up and started speaking. Now, Mr. Pardeep Chaudhary please put your question.

वॉक-आऊट

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं आया है इसलिए हम विरोधस्वरूप हाऊस से वॉक-आऊट करते हैं ।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से वॉक-आऊट कर गये ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

Upgradation of School

***557. Shri Pardeep Chaudhary :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Middle School of Village Dhaman of Morni Block being a hilly area ; if so, the time by which the aforesaid school is likely to be upgraded ?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदया जी को बताना चाहता हूं कि अपने क्वैश्चन में मैंने धामन स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बात की है । संयोग से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और माननीय मंत्री जी भी एक महिला हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो धामन स्कूल है . . . . . (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, हम यह चाहते हैं कि पहले श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सवाल का सही जवाब आना चाहिए ।

11.00 बजे

Mr. Speaker : Mr. Majra, I could have allowed him a number of supplementaries. But you have seen that when the Hon'ble Minister was answering, he started interrupting the Minister. Is it fair? (Interruption) You have been in this House more than anybody else. But you started surfing. Tell me is it fair?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ कि गुर्जर साहब को मंत्री का रिप्लाई पूरा होने के बाद ही सप्लीमैंट्री पूछनी चाहिए थी लेकिन उनको दो सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दिया जाना चाहिए था ।

Mr. Speaker : I could have allowed ten supplementaries. But when the Minister was answering, he started talking, which is not fair. Now, Mr. Pardeep Chaudhary may ask the supplementary.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता

हूँ कि मैंने मोरनी क्षेत्र के एक स्कूल धामन का दर्जा बढ़ाने की बात कही थी । वहाँ पर लड़के और लड़कियों को 20-25 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है । 2006 के अनुपात में लड़कियों की संख्या में बहुत कमी आई है । लड़कों की संख्या भी कम हो गई है । वहाँ पर जंगली एरिया होने के कारण मां-बाप लड़कियों को दूर भेजने से कतराते हैं । आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाये । साथ ही पिंजौर और कालका में भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाये जायें ।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं पूरे सदन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देना चाहती हूँ जिसका कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में भी जिक्र किया है । जहां तक उपरोक्त स्कूल की बात है तो हमने इसको नये नॉर्मस के अनुसार चैक करवाया है । नये नॉर्मस के मुताबिक बच्चों की संख्या 150 होनी चाहिए जो कि वहाँ पर पर्याप्त है। कमरों की संख्या 14 होनी चाहिए और 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए । वहाँ पर कमरों की संख्या 9 है और दूरी की बात ठीक है कि वह 20 किलोमीटर ही है । उसके लिए 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर 1 एकड़ ही जमीन है । इसलिए यह नये नॉर्मस में कवर नहीं होता ।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सैक्टर 19, 12 और 21 पंचकूला और बरवाला के कई गांवों के स्कूल हमने अपग्रेडेशन के लिए दिये थे लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उसमें कुछ नहीं हुआ है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगी कि उनका क्या हुआ है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि पंचकूला में हमने मिडल से हाई स्कूल 5 अपग्रेड किये हैं । हाई स्कूल से सीनियर सैकेण्ड्री 7 अपग्रेड किये हैं । हमने अपग्रेडेशन के नॉर्मस चेंज किये थे उसके बाद हमने सभी केसिज को चेंज नॉर्मस के मुताबिक टेकअप किया है । हमने तकरीबन 2005-06 से लेकर 2009-10 तक 1758 स्कूल अपग्रेड किये हैं । हमने जो हरियाणा के कुल स्कूल अपग्रेड किये हैं उनमें पंचकूला के 14 स्कूल अपग्रेड किये हैं ।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 17 अप्रैल, 2010 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पलवल में घोषणा की थी कि सैक्टर 12 में 10 एकड़ जमीन लेकर महाविद्यालय बनाया जायेगा, उसमें क्या प्रोग्रैस है और वह कब तक बन जायेगा ?

Mr. Speaker : It is a separate question. You are asking about the College and the main question was with regard to the schools.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सवाल तो शिक्षा से ही संबंधित है ।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है तथा इसके लिए हुडा के सैक्टर 12 में जमीन अलॉट हो गई है लेकिन इसकी पोजैशन नहीं हुई है । पोजैशन होने के एक साल के अन्दर-अन्दर इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा ।

Geeta Jayanti Utsav as National Festival

***511. Shri Ashok Kumar Arora :** Will the Chief Minister be pleased to state the efforts being made to declare Kurukshetra Festival (Geeta Jayanti Utsav) as a National Festival?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने पूछा है कि कुरुक्षेत्र में गीता जयन्ती उत्सव मनाते हैं उसको एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाये इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गीता जयन्ती उत्सव 1989 में शुरू हुआ था और इसकी अवधि 1991 में 2 दिन थी जिसको बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया है और 2002 से पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय इसमें सम्मिलित हो कर इस मेले को बढ़ावा देता है। प्रत्येक वर्ष मेले में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है । हरियाणा सरकार ने गीता जयन्ती समारोह के लिए, वित्त वर्ष 2011-12 में बजट 30 लाख रुपये से बढ़ा कर 100 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है जो कि बहुत ही सुन्दर काम है । यह राशि मेले के बेहतर आयोजन करने में सहायक होगी । राष्ट्रीय उत्सवों की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है । लेकिन इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वह हम जरूर करेंगे ।

Mr. Speaker : You please write to Government of India that it should be a national festival.

Shri Gopal Kanda : Yes, Sir.

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय अरोड़ा साहब को बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ही राष्ट्रीय पर्व हैं लेकिन इससे गीता जयन्ती उत्सव का महत्व भी कम नहीं होता है। जैसा मंत्री महोदय ने बताया है कि इसकी राशि 30 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये मुख्यमंत्री जी ने की है । ये वहां के प्रतिनिधि हैं इसलिए इसके अलावा भी यदि कोई और सुझाव अरोड़ा साहब देंगे तो उनके वह सुझाव भी हम इनकोरपोरेट करने को तैयार हैं । परन्तु राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी ही हैं ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है और गीता की जन्म भूमि है इसलिए गीता जयन्ती उत्सव को बढ़ावा देने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं वह कम हैं । अध्यक्ष महोदय, बार-बार कुरुक्षेत्र के इस उत्सव के बारे में यह कहा जाता है कि हम राष्ट्रीय उत्सव मानने के लिए प्रयास कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि इसमें क्या प्रयास हुए हैं ? मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि इसके लिए राशि 30 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गयी है । अध्यक्ष महोदय, जब एन.डी.ए. की सरकार थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपकी भी कुरुक्षेत्र कर्म भूमि है । मैं यह कहने जा रहा हूं कि उस समय गीता जयन्ती को विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए कभी देश के उपराष्ट्रपति और कभी देश के उप प्रधानमंत्री गीता जयन्ती पर आया करते थे । केन्द्र के मंत्री तो हर गीता जयन्ती पर आया करते थे । ये तीस लाख

रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये करने की बात कर रहे हैं लेकिन उस समय इस उत्सव पर दो-दो करोड़ रूपये तक खर्च किए गए थे इसलिए मुझे नहीं लगता अब इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । सरकार को पता नहीं कुरुक्षेत्र से प्रेम क्यों नहीं है । केन्द्र में भी ऐसा कोई मंत्री नहीं बैठा जो कुरुक्षेत्र में आकर कुरुक्षेत्र के विकास की या गीता जयन्ती उत्सव की बात करे। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आप केन्द्र सरकार को लिखेंगे कि कुरुक्षेत्र को एक राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाए ? जब 2003-04 में दो करोड़ रुपये इस उत्सव पर खर्च हो जाते थे तो अब कितना और बजट इस पर बढ़ाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी तो बैठे नहीं है लेकिन मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र के विकास के लिए कुरुक्षेत्र डिवैल्पमैंट बोर्ड का गठन तो हुआ है लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मीटिंग डेढ़-डेढ़ साल बाद भी नहीं होती । पिछली मीटिंग भी डेढ़ साल बाद हुई थी और अब भी एक साल हो गया है उसकी मीटिंग नहीं हुई है। मेरा मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया कुरुक्षेत्र के विकास के लिए गीता जयन्ती के उत्सव को और बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

Mr. Speaker : I share with your concern. मैं विश्वास दिलाता हूं कि सारे सदन की एक राय है । कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्थान है और गीता जयन्ती महत्वपूर्ण उत्सव बने इसके लिए मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि वह राष्ट्रीय सरकार को इस बारे में लिखेंगे because National Festival is declared by the Government of India.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : लेकिन अभी तक तो नहीं लिखा है ।

Mr. Speaker : He has already said, about it. इन्होंने कहा है कि आपके सुझाव पर ये भारत सरकार को लिख रहे हैं ।

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, गीता हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक पावन और पवित्र ग्रन्थ है इसलिए हम सब चाहते हैं कि इसके लिए जो भी इनके सुझाव हैं वह ये हमें लिखित रूप में बता दें हम उन पर जरूर कार्यवाही करेंगे । सरकार गीता जयन्ती के लिए जो भी मैक्सिमम कर सकती है उसके लिए मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि वह हम करेंगे । राष्ट्रीय उत्सव के लिए भी हम सैंट्रल गवर्नमैंट को लिखकर भेजेंगे ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : क्या आप बजट भी बढ़ाएंगे ?

श्री गोपाल कांडा : बजट भी बढ़ा देंगे ।

Proper Working of Sewerage System in Jind

***575. Shri Hari Chand Middha :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether the sewerage system of Jind city is not working properly ; if so, the steps being taken by the Govt. to resolve the aforesaid problem ?

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : No, Sir. The sewerage system of Jind is working very well except in some certain areas which is near Jain Nagar because it is a very low lying area and that is why sometimes, you know, there is a bad flow and because of the bad flow the sewerage gets blocked. But we are in a process of augmentation and there is going to be bigger diametre pipes are put in and at the end of the next month it will be completed.

श्री हरी चंद मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, हालात को मद्देनजर रखते हुए मंत्री महोदया ने कबूल किया है कि मेरे हल्के में जैन चौक, विश्वकर्मा कालोनी और उसके आस पास की वास्तव में स्थिति गंभीर है । उस स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है इसके बारे में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आप भी वहां जाते आते हैं क्योंकि वहां आपका एक ब्लड रिलेशन है लेकिन वहां जिस रास्ते से जाते हैं उससे आप वहां से दोबारा वापस नहीं आ सकते। अध्यक्ष महोदय, रोहतक हमारा बड़ा भाई है, कैथल छोटा भाई है और जींद बीच में बहन ब्याही है। ऐसी उसकी हालत है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वहां की समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए क्योंकि वहां की स्थिति बहुत गंभीर है ।

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, I have already assured the Hon'ble Member, I told him that by the end of the next month that means 30th April, 2011, this particular area which is Jain Chowk is gone to be completed because we are lying a 30" diameter pipe near Jain School situated near Vishwakarma Colony, which has sufficient depth and after the completion of this work the whole problem is going to be over. The problem, Mr. Speaker Sir, I would also like to put on record, is that there are lot of encroachments in Jind and there are people, who have laid down marble stones on the mainhole and they do not allow the mainholes to be opened to clean them. So, we have taken up this issue with the administration so that the administration can also find those people and put penalties on them so that this short up thing is not to be done. Apart from that, now, he has asked a question regarding expenditure incurred on augmentation of sewerage. So, as far as our Government is concerned, I would like to give these figures about the comparison between the expenditure that have been incurred in the augmentation of sewerage and water supply from July 1999 to February 2005. As far as urban water supply is concerned, it was ₹54.56 lac and till March 2005 ₹120.76 lac have been incurred. As far as urban sewerage disposal is concerned, from July 1999 to February

2005, ₹283.9 lacs expenditure was incurred. Now till March 2005, ₹2688.25 lacs have already been spent on it. So, the Government is already in the process of formulating it. STPs are being put in and all other measures are being taken up in this regard. Sir, if you permit me, I can tell the entire things to the Hon'ble Member.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि चंद शहरों की सीवरेज व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है और उसका मेन कारण इन्क्रोचमैंट को बताया है । सरकार ने राशि भी बढ़ाई है । वर्ष 2005 से आज तक काफी पैसा लगाया है, 2-3 परियोजनाएं शुरू की हैं। अध्यक्ष जी, वास्तविक स्थिति ये है कि जिस एरिया में इन्क्रोचमैंट नहीं है जिसको अर्बन इस्टेट का नाम दिया जाता है वहां भी पिछले 6 साल से लगातार सीवरेज लीक है। टोटली अर्बन इस्टेट के अंदर हर समय सीवरेज लीक है और उसके बारे में बार-बार लोगों ने प्रार्थना की है । यहां तक कि मंत्री महोदया से मिलकर भी प्रार्थना की है लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । जैन नगर और उसके आसपास की स्थिति के बारे में मंत्री महोदया ने जवाब में बता दिया है लेकिन वास्तव में टोटली अर्बन इस्टेट, जींद का डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है । आज भी वास्तविक स्थिति ये है कि जो मेन सीवरेज सिस्टम जींद का है, वह काम नहीं कर रहा है । नया अर्बन इस्टेट जो बनाया जा रहा है उसके अंदर ओपन नाले छोड़ दिये गये हैं । वह ओपन सीवरेज चल रहा है। वह भी टोटली ब्लॉक है ।

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Member here that sewerage of various sizes of zone 'A' has already been laid down in old city like Jind and against an estimate of ₹3608.10 lacs, 15 MLD main pumping station and sewerage treatment plant have already been started functioning. About laying of the sewerage in the remaining part of the city, because 80% of the cities were covered by the sewerage, is in progress and is near to completion. At present 135 Kilometres of sewer line of various sizes already exist in the town. There is a move for acquisition of land for another 5 MLD sewerage treatment plant. For Zone 'B' which is a Patiala Chowk area, is under process and the award has already been announced. It is awaited the work of construction of sewerage treatment plant and it shall be taken in hand in the next financial year. We are already trying to do whatever we can do as far as the area of Jain Chowk is concerned. For which a specific question was asked, that is going to be completed by the end of next month. But this is all will be taking in the next financial year. And another 1.5 MLD sewerage treatment plant for Zone 'C', will be

[Smt. Kiran Chaudhary]

constructed after proper development of the area. I would also like to add that from time to time cleaning is also being done on a regular basis and it is being cleaned regularly and manually by hydraulic sewerage cleaning machines. Recently, during the month of December 2010, one Kilometre long sewer line has already been cleaned by the bucket sewer cleaning machine system.

श्री कृष्ण लाल कम्बोज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रानिया एक छोटा सा कस्बा है वहां की सीवर व्यवस्था इतनी बुरी है कि जिसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । शहर में मेन रोड से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है ।

Mr. Speaker : Mr. Kamboj, this was a specific question on Jind. If you want to ask something else, you can send a separate question. This specific question has been asked about a particular Mohalla. I think you send a separate question for this. Thank you.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जो सीवर साफ करने की मशीन है उसका क्या नाम है क्योंकि मुझे उस मशीन का नाम मालूम नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश की बात है और मैं स्पैसिफक क्वैश्चन पूछ रही हूं । ये जो मशीनें हैं वे खराब पड़ी हुई हैं जैसे कि करनाल में एक मशीन ही चलती है और करनाल बड़ा शहर है । क्या सरकार इस बारे में कोई ऐसा प्रोविजन करने जा रही है कि वह ऐसी नई मशीनें खरीदेगी ?

Smt. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, I have understood what she is saying. I realize that there is a paucity of machines.

Mr. Speaker : She wants to know the name of the machine.

Smt. Kiran Chaudhary : Bucket supersonic cleaning machine and lot of other technology whatever it is coming in, we will definitely try to adopt it so that at least the problem may be taken care of.

Number of Stadiums

***441. Shri Abhey Singh Chautala :** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state :

(a) the number of stadiums constructed during the period from 01/04/2005 to till date ;

(b) the number of Coaches, discipline-wise posted in each stadium ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to recruit or post Coaches in the stadiums where Coaches have not been posted during the current financial year 2010-11 or 2011-12?

कृषि राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) : रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी हुई है।

(क) 1.4.2005 से आज तक 180 स्टेडियमों का निर्माण हो चुका है। 80 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर (ब्लाक स्तरीय ग्रामीण स्टेडियम) तथा 55 मिनी स्टेडियम वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।

(ख) इन स्टेडियमों में 234 खेल प्रशिक्षक नियुक्त किये हुए हैं। प्रत्येक स्टेडियम में खेल अनुसार नियुक्त प्रशिक्षकों का विवरण अनुलग्नक 'क' पर दिया हुआ है।

(ग) ब्लाक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसरों के रख–रखाव के लिए 168 मैदान प्रबन्धक एवं 168 मैदानकर्मियों को अनुबन्ध आधार पर रखे जाने बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अनुलग्नक–क

खेल स्टेडियम में खेलवार नियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या

जिला रोहतक

क्र.सं.	स्टेडियम का नाम	प्रशिक्षकों की संख्या	खेलवार
1	2	3	4
1.	सर छोटूराम स्टेडियम	2	कुश्ती
		1	एथलैटिक्स
		1	जिम्नास्टिक
		1	बॉक्सिंग
		1	बास्केटबाल
2.	राजीव गांधी खेल काम्पलैक्स	2	हाकी
		1	कबड्डी
		1	एथलैटिक्स
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, जसिया	1	हैण्डबाल
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मकडौली कलां	1	कुश्ती
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मदीना	1	एथलैटिक्स
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, लाखनमाजरा	1	हाकी
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सांगाहेड़ा	1	एथलैटिक्स

[श्री सुखबीर कटारिया]

1	2	3	4
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सुंडाना	1	कुश्ती
9.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, नौनन्द	1	कबड्डी
10.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सांपला	1	बास्केटबाल
11.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, ईस्माईला	1	हैण्डबाल
जिला कुरुक्षेत्र			
1.	द्रोणाचार्य स्टेडियम	1	जुडो
		1	हैण्डबाल
		1	बास्केटबाल
		1	तैराकी
		1	एथलैटिक्स
		1	क्रिकेट
		1	कुश्ती
		1	साईक्लिंग
		1	योगा
2.	मार्कण्डेश्वर हॉकी स्टेडियम, शाहबाद	2	हॉकी
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, अमीन	1	वालीवाल
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बाखली	1	हैण्डबाल
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सुड़पुर	1	हॉकी
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बीड़कालवां	1	जिम्नास्टिक
जिला नारनौल			
1.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम	1	एथलैटिक्स
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, डोहर कलां	1	वालीवाल
जिला यमुनानगर			
1.	तेजली खेल कॉम्पलैक्स	1	कुश्ती
		1	हैण्डबाल
		1	बॉक्सिंग
		1	क्रिकेट
		1	लॉन टैनिस
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गोलनी	1	कुश्ती
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, नग्गल	1	योगा
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कोटरा खास	1	भारत्तोलन
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, लाहरपुर	1	बास्केटबाल
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बरसान	1	हैण्डबाल
जिला पानीपत			
1.	शिवाजी स्टेडियम	1	बास्केटबाल
		1	हैण्डबाल

1	2	3	4
		1	एथलैटिक्स
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सिवाह	1	कबड्डी
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, इसराना	1	हॉकी
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बबैल	1	बास्केटबाल
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बापौली	1	एथलैटिक्स
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मलौडा	1	हैण्डबाल
जिला रेवाड़ी			
1.	राव तुलाराव स्टेडियम	1	क्रिकेट
		1	एथलैटिक्स
		1	योगा
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, धारुहेड़ा	1	एथलैटिक्स
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मनेठी	1	बॉक्सिंग
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गुरावड़ा	1	योगा
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कोसली	1	वालीवाल
जिला सोनीपत			
1.	सुभाष स्टेडियम	1	कुश्ती
2.	मिनी स्टेडियम, गोहाना	1	कुश्ती
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, भटगांव	1	कुश्ती
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गांव सिसाना	1	कुश्ती
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, पुरखास	1	कबड्डी
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कपूरा	1	कुश्ती
जिला गुड़गांव			
1.	नेहरु स्टेडियम	1	हॉकी
		1	भारत्तोलन
		2	हैण्डबाल
		1	वालीवाल
		1	कोर्फवाल
		1	जिम्नास्टिक
		1	कुश्ती
2.	ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सैक्टर 38, गुड़गांव	1	फुटबाल
		1	क्रिकेट
		1	एथलैटिक्स
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, दौलताबाद	1	क्रिकेट
जिला भिवानी			
1.	भीम स्टेडियम	1	जिम्नास्टिक
		1	बास्केटबाल

[श्री सुखबीर कटारिया]

1	2	3	4
		1	वालीवाल
		1	कबड्डी
		2	कुश्ती
		1	हॉकी
		2	क्रिकेट
		3	एथलैटिक्स
		1	तैराकी
		2	बॉक्सिंग
2.	चौ. देवीलाल स्टेडियम, लोहारू	1	एथलैटिक्स
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, तिगड़ाना	1	हॉकी
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, चांदवास	1	वालीवाल
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मकड़ाना	1	कबड्डी
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, झोझूकलां	1	वालीवाल
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बड़वा	1	तैराकी
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, लेंघा हेतबान	1	बास्केटबाल
9.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, तौशाम	1	क्रिकेट
10.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मित्ताथल	1	कुश्ती
11.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बहल	1	कुश्ती
12.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, ढिगांवाजाटान	1	एथलैटिक्स
13.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, धारेडू	1	एथलैटिक्स
14.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, हालूवास	1	एथलैटिक्स
15.	बिरहींकलां	1	कुश्ती
16.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, छप्पर	1	कुश्ती
17.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, अचीना	1	बास्केटबाल
18.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कादमा	1	क्रिकेट
जिला करनाल			
1.	कर्ण स्टेडियम	1	कबड्डी
		1	तैराकी
		1	फुटबाल
		1	भारतोलन
		1	वालीवाल
		1	बास्केटबाल
		1	जिम्नास्टिक
		1	योगा
		1	साईक्लिंग
		1	बॉक्सिंग

1	2	3	4
		1	स्केटिंग
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, पूण्डरक	1	फुटबाल
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कालरी जागीर	1	तैराकी
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गगसीना	1	कबड्डी
जिला फतेहाबाद			
1.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, धारनियां	1	बॉक्सिंग
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, भट्टूकलां	1	फुटबाल
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, समैन	1	बॉक्सिंग
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, नथुवाल	1	हॉकी
जिला फरीदाबाद			
1.	खेल कॉम्पलैक्स, सैक्टर 12	1	जिम्नास्टिक
		1	बास्केटबाल
		1	योगा
		1	स्केटिंग
		1	बैडमिंटन
		1	वालीवाल
		1	फैन्सिंग
2.	नाहर सिंह स्टेडियम	1	एथलैटिक्स
		1	क्रिकेट
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, तिगांव	1	स्केटिंग
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, फतेहपुर बिल्लौच	1	एथलैटिक्स
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, करनेरा	1	बॉक्सिंग
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, अटाली	1	क्रिकेट
जिला पलवल			
1.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम	1	वालीबाल
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, खेडला	1	बालीवाल
जिला कैथल			
1.	पट्टी अफगान, स्टेडियम	1	एथलैटिक्स
		1	बॉक्सिंग
		1	वालीवाल
		1	कबड्डी
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, भाना	1	वालीवाल
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, फतेहपुर	1	एथलैटिक्स
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, भागल	1	बॉक्सिंग
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मलिकपुर	1	एथलैटिक्स
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बाता	1	कबड्डी

[श्री सुखबीर कटारिया]

1	2	3	4
जिला सिरसा			
1.	शहीद भगत सिंह स्टेडियम	1	एथलैटिक्स
		2	बास्केटबाल
		1	वालीवाल
		1	हॉकी
		1	बॉक्सिंग
		1	तीरान्दाजी
		1	जुड़ो
2.	चौ. दलबीर सिंह स्टेडियम	1	हैण्डबाल
		1	जिम्नास्टिक
3.	साहिब राम स्टेडियम चौटाला	1	कबड्डी
		1	वालीवाल
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गंगा	1	हैण्डबाल
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गोदिकां	1	बास्केटबाल
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सुखचैन	1	बास्केटबाल
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, धोलपालिया	1	एथलैटिक्स
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बालासर	1	बास्केटबाल
9.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कंवरपुरा	1	वालीवाल
10.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, जमाल	1	फुटबाल
जिला जीन्द			
1.	नवदीप स्टेडियम, नरवाना	1	कुश्ती
		1	हैण्डबाल
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, ईगराह	1	कुश्ती
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, नंदगढ़	1	हॉकी
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, अलेवा	1	कबड्डी
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, हमीरगढ़	1	हैण्डबाल
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, करसिन्धु	1	तैराकी
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, खरकबूरा	1	कबड्डी
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, शिल्ला खेड़ी	1	कबड्डी
9.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, गांगोली	1	फुटबाल
जिला झज्जर			
1.	बाग जहाआरा स्टेडियम, झज्जर	1	हॉकी
		1	जिम्नास्टिक
2.	ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़	1	कबड्डी
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मातनहेल	1	कबड्डी
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, तलाव	1	जिम्नास्टिक

1	2	3	4
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सुहरा	1	कबड्डी
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सिलानी	1	हॉकी
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, दुबलधन	1	एथलैटिक्स
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बाढ़सा	1	जुडो
9.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, खेड़का गुज्जर	1	वालीवाल
10.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, दुल्हेड़ा	1	योगा
11.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, कबलाना	1	कुश्ती
जिला पंचकूला			
1.	ताऊ देवीलाल खेल कॅम्पलैक्स, सैक्टर 3	1	बास्केटबाल
		2	बैडमिन्टन
		2	क्रिकेट
		1	हैण्डबाल
		2	एथलैटिक्स
		1	बॉक्सिंग
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, नटवाल	1	बॉक्सिंग
	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, नग्गल	1	जिम्नास्टिक
	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, पपलोहा	1	फुटबाल
जिला हिसार			
1.	महाबीर स्टेडियम	1	कुश्ती
		1	एथलैटिक्स
		2	बॉक्सिंग
		1	जुडो
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सिसाय कालीरावण	1	कुश्ती
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सुलचाणी	1	बॉक्सिंग
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, आदमपुर	1	बॉक्सिंग
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बालसमंद	1	हॉकी
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, लान्धड़ी	1	कुश्ती
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, प्रभुवाला	1	हैण्डबाल
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, जुगलान	1	फुटबाल
जिला अम्बाला			
1.	वार हीरोज मैमोरियल स्टेडियम	2	फुटबाल
		3	जिम्नास्टिक
		1	बॉक्सिंग
		1	बैडमिन्टन
		1	योगा

[श्री सुखबीर कटारिया]

1	2	3	4
2.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, मोहड़ा	1	जिम्नास्टिक
3.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, खतौली	1	हॉकी
4.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, साहा	1	जिम्नास्टिक
5.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, निन्यौला	1	कबड्डी
6.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, सरकपुर	1	बास्केटबाल
7.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, लाहा	1	बॉक्सिंग
8.	श्री राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, बिचपड़ी	1	हैण्डबाल

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, यह सब तो मंत्री जी को बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यह सब तो पहले ही जवाब में दिया हुआ है । ये इतना कह देते कि जवाब में लिखा है यह बात मैंने पढ़ ही रखी है । मंत्री जी खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और मेरे साथ स्पोर्ट्स कालेज में पढ़े हैं । पिछले छः साल से स्पोर्ट्स के नाम से प्रदेश में राजनीति हो रही है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में जो 180 स्टेडियम बने हैं ये कौन-कौन से जिलों में बने हैं, किस सब-डिवीजन में बने हैं, किस ब्लॉक में बने हैं । कोचिज की नियुक्ति कौन-कौन से गेम के लिए हुई है । इन कोचिज की नियुक्ति के लिए सरकार ने कब एडवर्टाईजमैंट निकाली ?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट लगी हुई है, मैं इसको पढ़ देता हूं । रोहतक में 18 कोचिज लगे हुए हैं । सर छोटू राम स्टेडियम में 2 कोचिज रैस्लिंग के, एक कोच एथलैटिक, एक कोच जिम्नास्टिक और एक कोच बॉक्सिंग का है । कुरुक्षेत्र जिले में टोटल 15 कोचिज, नारनौल में 2 कोचिज, यमुनानगर में 10 कोचिज, पानीपत में 8 कोचिज, रिवाड़ी में 7 कोचिज, सोनीपत में 6 कोचिज, गुड़गांव में 12 कोचिज और भिवानी में 32 कोचिज लगे हुए हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन कोचिज की नियुक्ति कौन से साल में हुई है और ये सारे स्टेडियम कौन से साल में बने हैं ?

Mr. Speaker: After 2005, Mr. Chautala.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि मंत्री जी यह बताएं कि ये जो कोचिज लगाएं हैं यह कौन से वर्ष की भर्ती है । इन्होंने तो यह कहा है कि हमने नए इतने भर्ती कर लिए । ये नए भर्ती किए हैं तो कौन से वर्ष में भर्ती किए हैं ?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 2005 तक मात्र 56 स्टेडियम बने थे और हमारी सरकार के अंदर अब तक ग्रामीण स्तर पर 257 स्टेडियम, ब्लाक लैवल पर 108, उपमंडल स्तर पर 9 और जिला स्तर पर 19 स्टेडियम बन चुके हैं । ये 2005 तक का और उसके बाद का कम्पैरीजन कर सकते हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जवाब में कोचिज की लिस्ट तो यहां पर है

लेकिन इन कोचिज की भर्त्ती कब हुई ?

श्री अध्यक्ष : क्या लिस्ट में डिस्ट्रिक्टस मैंशन नहीं हैं ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लिस्ट यहां पर रखी हुई है उन कोचिज की भर्त्ती कब हुई है ? मैं यह नहीं पूछ रहा कि आपने कहां-कहां किस किस कोच की नियुक्ति कर रखी है। ये बार-बार एक ही बात कहते हैं कि हमने इतने स्टेडियम बना दिए । उन स्टेडियमों में कौन-कौन से कोचिज आपने लगाए और कब उनकी भर्त्ती की ? कोचिज की तो पहले से ही कमी है । अगर स्टेडियम बना दिए और कोचिज भर्त्ती नहीं होंगें तो कैसे बात बनेगी । यहां खेलों पर राजनीति हो रही है । यह कोरी खेलों पर राजनीति है, खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं है।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पैसीफिक जवाब एनैक्सर्ज के साथ दे दिया है । अगर मुझे सही समझ में आया है तो अभय सिंह चौटाला जी ने 2 प्रश्न पूछे हैं ।

Mr. Speaker : Mr. Chautala, do you want to know when the coaches were appointed?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहली बार उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम किस-किस जिले में बनाए गए । दूसरा, इन्होंने यह पूछा है कि इन कोचिज की नियुक्ति कब हुई? These are two specific questions which he had asked for. The answer that the Minister has placed on the Table of the House is very specific. Annexure 'A' gives a detailed list of each stadium that has been constructed in each district alongwith the name of place where the stadium is situated and number of coaches who are posted in each stadium. Sir, the Minister has stated in his reply to part 'C' that there is a proposal under consideration of the Government to recruit 168 Ground Managers and Ground Men on contract basis. Process for recruitment is going on. I think the answer is very precise and details have been specified.

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की जो खेल नीति आई है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए । इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है । एशियन गेम्ज, कोमनवैल्थ गेम्ज के अंदर जो हरियाणा की परफोरमैंस रही है वह वंडरफुल और कमेंडेबल है । खेल नीति को पिछले 6 सालों से बढ़ावा दिया गया है । इससे पहले खेल नीति को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया ।

Mr. Speaker : Mr. Batra ask the question. (Interruption)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि रांची में जो नैशनल गेम्ज हुए हैं उसमें हरियाणा की परफोरमैंस क्या रही है? SPAT (Sports & Physical Aptitude Test) में सरकार कितना आगे बढ़ रही है और उसमें कितना पैसा खर्च कर रही है ?

श्री सुखबीर कटारिया : रांची के खेलों में हम पूरे देश में तीसरे नम्बर पर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी जो स्पोर्ट्स की स्पैट नीति है वह बड़ी कारगर सिद्ध हुई है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि बाहर देशों में और प्रदेश में भी इसके बारे में बड़ी इन्कवायरीज हो रही हैं । हालैंड और पाकिस्तान ने भी हमारे से हमारी स्पैट नीति के बारे में इन्क्वायरी की है । हमारी स्पैट नीति बहुत ही अच्छी है इससे आने वाले दिनों में बच्चों को बहुत फायदा पहुंचेगा और हमारा प्रदेश स्पोर्ट्स में काफी आगे बढ़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : कटारिया जी, इस नीति के तहत कितने बच्चों को लिया गया है माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं ?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसके तहत 4991 बच्चों को लिया गया है और करीबन 10 करोड़ रुपये स्कोलरशिप के रूप में दिये जायेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्पोर्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि हमने इतने मैडल जीत लिये और सरकार की स्पोर्ट्स नीति बहुत बढ़िया है । मेरा सप्लीमैंटरी क्वैश्चन है कि जो स्पोर्ट्स नर्सरी और विंग हरियाणा में चला करती थी अब वे चल रही हैं या बंद कर दी गई हैं । यदि बंद कर दी गई हैं तो क्यों की गई हैं ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह आपके साथ भी जुड़ा हुआ प्रश्न है । उन नर्सरीज को बंद किया गया है तो क्यों किया गया है इस बारे में मंत्री जी बतायें ?

श्री सुखबीर कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सैप्रेट क्वैश्चन है माननीय साथी इस बारे में लिखकर भिजवा दें इनको जवाब दे दिया जायेगा ।

Construction of ROB

***573. Shri Narender Sangwan :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct ROB at the railway crossing on Delhi-Ambala line on Rakhsina to Gharaunda road; and

(b) If so, the time by which the construction of the ROB is likely to be started and completed ?

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने

अपने सवाल में जो रखसीना गांव लिखा है वह रखसीना नहीं है । इसको हमने दुरूस्त कर लिया है यह गगसीना गांव है । इन्होंने रखसीना लिख दिया इसलिए जवाब में नहीं, श्रीमान जी लिखना आवश्यक हो गया है।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह मेरी मिस्टेक नहीं है, यह इन्हीं के लैवल पर हुई है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें यदि विधान सभा सक्रेटेरियट लैवल पर कोई मिस्टेक हुई है तो उसको मैं चैक करवा लूंगा । मैं माननीय साथी को गगसीना के बारे में बताना चाहूंगा कि घरौंडा रोड पर घरौंडा शहर में लैवल क्रोसिंग नम्बर 63 पड़ती है । अध्यक्ष महोदय, यह आपके भी पड़ोस का क्षेत्र है । आपने भी देखा है और सांगवान साहब वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं । हमने वहां की फीजिबिलिटी आर.ओ.बी. की चैक करवाई है । वहां रैगुलर ट्रैफिक चलता रहता है और हर रोज जाम लगते हैं । वहां के जो लोकल रैजीडैंट्स हैं और जो लोकल चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी हमने 73वें और 74वें संशोधन में चर्चा की है तथा जनता से भी सलाह ली है । यदि वहां पर आर.ओ.बी. बनाते हैं तो पूरी मार्किट और रैजीडैंशियल एरिया दोनों को डैमोलिश करना पड़ेगा । मार्किट और रैजीडैंशियल एरिया को डैमोलिश करके वहां आर.ओ.बी. बनाना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से वहां के लोगों के व्यवसाय और रिहायश का नुक्सान होगा, इससे माननीय साथी भी सहमत होंगे । इसलिए वहां पर आर.ओ.बी. की परपोजल को ड्रोप कर दिया । यदि माननीय सदस्य वहां के सभी लोगों से लिखवाकर दे दें कि उन्हें वहां आर.ओ.बी. बनवाने में कोई एतराज नहीं है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे ।

श्री नरेन्द्र सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो जवाब दिया है उसके अलावा वहां एक रास्ता और बनता है । वहां पर मण्डी के साथ में खाली जगह है जहां पर ओवर ब्रिज बनाया जा सकता है । यदि वहां पर ओवर ब्रिज भी नहीं बनाया जा सकता तो वहां पहले से ही एक अंडर पास बना हुआ है जो किसी कारणवश बंद पड़ा है उसे भी चालू करवाया जा सकता है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरा सुझाव दिया है इस बारे में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये मुझे लिखकर भिजवा दें हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे ।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Sub-way at Barara

***522. Shri Rajbir Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sub-way under Railway Line near Railway Station connecting main bazar of Barara City ; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं श्रीमान् जी।

Upgradation of CHC

***530. Shri Rameshwar Dayal :** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Community Health Centre, Bawal from 25 beds to 100 beds; if so, the time likely to be taken to upgrade the aforesaid CHC ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

Construction of Damaged Roads in Indri Constituency

***504. Shri Ashok Kashyap :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-construct/repair the following damaged roads in Indri constituency :

(i) Indri to Garhi Birbal;

(ii) Indri to Byana ;

(iii) Indri to Bara Gaon via Rindal-Laudora;

(iv) Butan Kheri to Garhi Jatan via Panjokhash ; and

(v) Khanpur to Dhanaura Jagir via Jainpur ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं श्रीमान् जी।

Compensation to Farmers

***540. Master Dharam Pal Obra :** Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Rabi crops could not be sown in villages namely Dhanana, Jatai, Talu etc. of Bawani Khera Sub-Division and twenty five other villages including Imlota, Bigova, Bhagvi, Samaspur, Birhi Kalan etc. of Sub-Division Charkhi Dadri in Bhiwani due to accumulation of rain water in the fields ;

(b) whether it is also a fact that no compensation has been given to the farmers for the damage of their crops after the year 2008; and

(c) if so, the time by which the water is likely to be drained from the fields of the abovesaid villages and financial assistance would be given to the affected farmers.

राजस्व मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) :

(क) जी हां, भिवानी उपमण्डल के गांव धनाना के कुछ हिस्सों में रबी की फसल की बिजाई नहीं की जा सकी तथापि गांव तालू व जतई के समस्त क्षेत्र में बिजाई हो चुकी है। भिवानी के उपमण्डल चरखी दादरी के 26 गांवों जिनमें इमलोटा, बिगोवा, भागवी, समसपुर, बिरहीकलां आदि शामिल हैं, के हिस्सों में भी खेतों में पानी होने तथा वाटर लोगिंग के कारण बिजाई नहीं हो सकी है।

(ख) गांव धनाना, तालू और जतई के किसानों को जिनकी खरीफ 2008 की फसलें क्षतिग्रस्त हुई थी राहत राशि प्रदान की जा चुकी है तथा इस सम्बन्ध में तहसील दादरी के प्रभावित गांवों में राहत राशि बांटी जा रही है। खरीफ 2009 की फसल को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त 2009 में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों की राहत राशि प्रभावित किसानों में बांटी जा चुकी है।

(ग) इस समय बाढ़ के पानी की निकासी कर दी गई है। निचले इलाकों में जो पानी खड़ा है वह केवल सब सोईल वाटर तल के उच्च होने के कारण है। वर्ष 2010 में फसलों को हुए नुकसान के कारण उपायुक्त भिवानी को राहत राशि स्वीकृत कर दी गई है तथा वह जल्दी ही बांटे जाने की आशा है।

Canal Water for Drinking Water Supply

***513. Shri Anand Kaushik :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply canal water for drinking purpose in Faridabad city; if so, the time by which the canal water is likely to be supplied for the aforesaid purpose ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : नहीं श्रीमान जी।

Construction of Road

***539. Shri Charanjit Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from Kalanwali Mandi to Bara Gudha in Kalanwali Constituency; if so, the time by which the aforesaid road is likely to be constructed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सिरसा जिले में कालांवाली से बड़ा गुढ़ा साहुवाला होते हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग–10 तक सड़क पहले ही मौजूद है।

मौजूदा 21.43 कि.मी. लम्बी सड़क नीची है और इसकी चौड़ाई 3.66 मीटर है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 5.5 मीटर करने और इसकी ऊंचाई भिन्न–भिन्न खंडों में 60 सैंटीमीटर से 90 सैंटीमीटर तक उठाने की स्वीकृति

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
दी गई है। इसके लिए सड़क की मौजूदा संरचना को इसकी पूरी गहराई तक उखाड़ा जाना है। इस कार्य को 1401 लाख रुपये की लागत से शुरू किया गया है और यह सड़क 31 दिसम्बर, 2011 तक बनकर तैयार हो जाएगी।

Express Highway from Yamunanagar to Delhi

***581. Shri Dharam Singh Chhoker :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an Express Highway from Yamunanagar to Delhi ; if so, the time by which the construction work of the aforesaid Express Highway is likely to be completed ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हां, श्रीमान् जी।

Construction of Solid Waste Management Project

***491. Smt. Sumita Singh :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state whether it is a fact that the construction work of the Solid Waste Management Project on the Meerut road of Karnal, is lying incomplete for the last so many months ; if so, the time by which the construction work of the said project is likely to be completed ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : हां, श्रीमान् जी। करनाल की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना (सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्रोजैक्ट) का कार्य शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लघु तथा माध्यमिक कस्बों के लिए शहरी संरचना विकास (यू.आई.डी.एस.एस.एम. टी.) स्कीम के अन्तर्गत राशि प्राप्त न होने के कारण रुका हुआ है। मंत्रालय द्वारा लघु तथा माध्यमिक कस्बों के लिए शहरी संरचना विकास स्कीम के तहत अप्रैल, 2009 से राशि इसलिए नहीं जारी की गई क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध सभी सुधार निर्धारित समय अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं किए गए। मंत्रालय से राशि को जारी करवाने के विषय को सुलझाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस परियोजना को भारत सरकार से वित्तीय राशि प्राप्त होने के छः मास के अन्दर–2 पूर्ण कर लिया जायेगा।

Post-mortem of Dead Body

***391. Shri Aftab Ahmed :** Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that no post-mortem is conducted after sun-set by the Doctor in accident cases ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct post-mortem after sun-set in cases of death due to road accidents ?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Grants to the Municipalities

***502. Shri Sher Singh Barshami :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state the details of grants given/released by the Government to the Municipalities in the State, during the period from 1.4.2005 till date ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) : श्रीमान जी, सरकार ने पालिकाओं को 1.4.2005 से अब तक निम्न अनुसार राशि अनुदान के रूप में वितरित की है :—

क्र.सं.	वर्ष	वितरित की गई राशि (लाखों में)
1.	2005–06	17405.97
2.	2006–07	21593.90
3.	2007–08	34086.87
4.	2008–09	53751.13
5.	2009–10	25778.73
6.	2010–11	17266.44
	कुल	169883.04

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Dilapidated Buildings of Schools

Shri Parminder Singh Dhull : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) the time by which the dilapidated buildings of the schools of Julana Constituency are likely to be repaired ;

(b) the number of such schools of Julana Constituency whose information regarding dilapidated condition of the buildings has been sent to the Department and

(c) the total number of the Senior Secondary Schools, High Schools and Middle Schools separately in Julana Constituency ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) श्रीमान् जी, जुलाना निर्वाचनक्षेत्र में 6 विद्यालयों की इमारतें जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। इन इमारतों की आवश्यक मरम्मत/पुनः निर्माण अगले वित्तीय वर्ष 2011–2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विद्यालय का नाम	इन विद्यालयों की इमारतों की मरम्मत/पुनः निर्माण के लिए वर्ष 2010–2011 में जारी राशि	विशेष कथन
1.	रा.क.व.मा.वि. लाजवाना कलां	3,51,000	मरम्मत कार्य प्रगति पर है।
2.	रा.व.मा.वि. धिमाना	9,55,000	मरम्मत कार्य प्रगति पर है।
3.	रा.व.मा.वि. ढिगाना	19,50,000	मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
4.	रा.व.मा.वि. शामलों कलां	19,98,000	पुनः निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
5.	रा.उ.वि. सिवाहा	16,32,000	मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।
6.	रा.क.प्रा. पाठशाला लाजवाना खुर्द	5,40,000	मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

(ख) जुलाना निर्वाचनक्षेत्र के उपरोक्त 6 विद्यालयों की जीर्ण–शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में सूचना विभाग में प्राप्त हुई है।

(ग) जुलाना निर्वाचनक्षेत्र में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, उच्च विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों की पृथक–पृथक कुल संख्या इस प्रकार है :–

(1)	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	–	21
(2)	उच्च विद्यालय	–	16
(3)	माध्यमिक विद्यालय	–	18

Allotment of Land to Social Institutions

79. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any scheme of the Haryana Urban Development Authority to allot land to Social Institutions/Trusts etc. in the State ;

(b) if so, the details of land allotted by HUDA since 2005 togetherwith the purpose of allotment ; and

(c) the details of land being used for the purpose other than the purpose for which it had been allotted ?

Chief Minister (Sh. Bhupinder Singh Hooda) :

(a) Yes Sir.

(b) 20 sites have been allotted for Social and Charitable Institutions since 2005 in various Urban Estates developed by HUDA, as per the details placed at Annexure-'A'.

(c) Sir, the information is nil.

Annexure - 'A'

Unstarred Question No. 79 raised by Sh. Anil Vij, M.L.A.

Urban Estate, Panchkula

Sr. No.	Name of the Institution & Trust	Sector	Year of allotment	Whether site is being used for the purpose other than the purpose of allotment, if yes, give detail.
1	2	3	4	5
1	Chinmaya Tapovan Trust, Panchkula	20	05-04-2006	No Misuse
2.	Gurjar Samaj Kalyan Parishad, Panchkula	10	20-09-2007	No. Misuse
3.	Swami Rama Foundation Trust, Panchkula	10	20-09-2007	No Misuse
4	Digamber Jain Trust Panchkula	18	09-01-2008	No Misuse
5.	Satya Sai Trust, Panchkula	12-A	09-01-2008	No Misuse
6	Dr. B.R. Ambedkar Mahasabha, Panchkula	12-A	09-01-2008	No Misuse
7	All India Foundation for Peace, Panchkula	12-A	09-01-2008	No Misuse
8	Saini Welfare Association, Panchkula	12-A	10-11-2009	No Misuse

[Shri Bhupinder Singh Hooda]

Urban Estate, Kurukshetra

9	Senior Citizen Forum (Regd.) Kurukshetra	13	25-07-2008	No Misuse

Urban Estate, Gurgaon

10	Sawami Kirpal Ruhani Mission, Gurgaon	Block No. J Palam Vihar	11-03-2005	Not constructed

Urban Estate, Narnaul

11.	Samvedna Charitable Foundation (Regd.), Narnaul	1	08-03-2010	No Misuse

Urban Estate Faridabad

12	Punjabi Sabha Faridabad	16	17-04-2007	No Misuse
13	Gurjar Sabha, Faridabad	16	17-04-2007	Building is under construction
14	Priyash Social Welfare Society Faridabad	64	27-05-2008	Building is under construction
15	Khema Trust Mandi Township, Ballabgarh Distt. Faridabad	Mandi Township Ballabgarh	27-05-2008	Building is under construction
16	Dr. Bhim Rao Ambedkar Welfare Society, Faridabad	3	27-05-2008	Building is under construction
17	Jat Sabha/Kishan Bhawan, Faridabad	16	26-05-2008	Site is lying vacant

Urban Estate Panipat

18	Gurudwara Nawakot Biradri, Panipat	12	20-09-2007	Under construction

Urban Estate, Jind

19	Resident Jind Central Jaycees Educational and Charitable Trust	11 Block D	31-01-2008	Building under construction
20	Dr. B.R. Ambedkar Welfare Society Jind	10 Block-B	31-01-2008	Building under construction

Interim Reply

Subject : **Unstarred Question No. 79 raised by Sh. Anil Vij, MLA regarding allotment of land to social institutions.**

The captioned question has been received by the Department of Urban Estate (Haryana Urban Development Authority) Haryana and is listed for hearing on 8-3-2011. In this regard, it is informed that the information asked by Hon'ble Member requires survey by the field staff. It will, therefore, take time to compile information, not less than two months. It is, therefore, requested that appropriate time may kindly be given to furnish reply.

Principal Secretary, Town & Country Planning, has already written to Secretary Vidhan Sabha Vide Memo No. 5/22/2011-2TCP, dated 04-03-2011.

Yours Sincerely
Sd/-
(Randeep Singh Surjewala)

Upgradation of School

71. Master Dharam Pal Obra : Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the Govt. Primary School of Village Dhani Sheelawali, Block Siwani fulfills all the requisite norms for up-gradation as Middle School, if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the aforesaid school from the Primary School to Middle School from the next academic session ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : हां, श्रीमान जी। उक्त विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय स्तरोन्नत करने हेतु प्रस्ताव पर आगामी शैक्षिक सत्र में विचार किया जाएगा।

Arrangement of Drinking Water

55. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) the time by which the arrangements for drinking water will be made and the work of sewerage system will be completed in Julana ; and

(b) whether the facilities referred to in part (a) above will also be provided to the colonies situated across the railway line ; if so, the time by which above referred facilities are likely to be provided ?

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) पूरे जुलाना शहर में पेयजल वितरण तथा सीवरेज व्यवस्था 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

[श्रीमती किरण चौधरी]

(ख) हां श्रीमान जी, रेलवे लाईन के पार स्थित अधिकृत कालोनियों में भी उक्त सुविधा 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

Number of National Highways

80. Shri Anil Vij : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) the Names/Numbers and the length of the National Highways in the State ; and

(b) the roadwise details of the Financial Assistance, if any, received from the Central Government for the maintenance of the above said Highways from the year 2005 till date yearwise ?

लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (क) व (ख) श्रीमान जी, स्टेटमैंट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(क) हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का नाम नं. व लम्बाई कि.मी. में

क्रमांक	सड़क का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग नं.	राष्ट्रीय राजमार्गों के नये नं.	लम्बाई (कि.मी. में)
1.	दिल्ली–अम्बाला (शेरशाह सूरी मार्ग)	1	44	182.866
2.	दिल्ली–मथुरा	2	22	75.030
3.	दिल्ली–जयपुर	8	48	83.215
4.	दिल्ली–हिसार–सुलेमंकी	10	9	285.850
5.	पिंजौर–बद्दी–नालागढ़	21–ए	105	17.500
6.	अम्बाला–कालका	22	5	28.300
7.	भटिंडा–डबवाली	64	54	0.480
8.	अम्बाला–हिसार–राजगढ़	65	52,152	241.560
9.	नरवाना–रोहतक–बावल	71	352	210.875
10.	रोहतक–पानीपत	71ए	709	73.290
11.	रिवाड़ी–सोहना–पलवल	71बी	919	67.900
12.	अम्बाला–काला अम्ब	72	7	40.525
13.	यमुनानगर–पंचकूला	73	344	108.445
14.	जगाधरी–पौंटा साहिब	73ए	907	45.880
			कुल लम्बाई	**1461.716**

(ख) वर्ष 2005 से आज तक सुधारीकरण व रखरखाव के लिए ₹ 674.19 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

Consolidation of Land Holdings

72. Master Dharam Pal : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state—

(a) the time by which the consolidation work is likely to be started in villages namely Pahari, Singhani and Gokalpur and the sufficient staff will be provided to carry out the aforesaid consolidation work ; and

(b) the time by which the orders to carry out consolidation in Chaihad Kalan village are likely to be issued by the Government.

राजस्व मंत्री (श्री सतपाल सांगवान) :

(क) गांव पहाड़ी में चकबन्दी कार्य प्रगति पर है। जहां तक गांव सिंघानी का सम्बन्ध है इस गांव में वर्ष 1979 में चकबन्दी कार्य शुरू किया गया था तथा धारा 21(1) के अधीन कार्य जून 1980 में पूर्ण कर लिया गया था। यदि भू–स्वामी सहयोग करेंगे तो विभाग चकबन्दी कार्य को पुनः आरम्भ कर देगा। जहां तक गांव गोकलपुरा का सम्बन्ध है, इस गांव का चकबन्दी कार्य प्रगति पर है। दो पटवारी, दो कानूनगो, दो सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा एक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की टीम बनाकर गांव पहाड़ी तथा गोकुलपुरा का चकबन्दी कार्य पूर्ण करने हेतु उन्हें सौंपा गया है।

(ख) यदि भू–स्वामियों का सहयोग प्राप्त हुआ तो चकबन्दी विभाग चकबन्दी कार्य पुनः आरम्भ कर देगा।

Basis of Authorised Colonies

56. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) the basis for declaring a colony authorized which falls within the area of the Municipal Committee ;

(b) the total number of colonies declared authorized in Julana town ; and

(c) the time by which the other colonies of Julana Town declared unauthorized are likely to be regularized ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोपाल काण्डा) :

(क) एक अधिकृत कालोनी हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 एवं अधिनियम 8 आफ 1975 के धारा 3 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करके स्थापित की जा सकती है।

(ख) शहरी क्षेत्रीय अधिनियम 8 आफ 1975 के गठन से पूर्व काटी गई कालोनियों के अलावा जुलाना कस्बे में कोई अन्य कालोनी अधिकृत घोषित नहीं की गई है।

[श्री गोपाल काण्डा]

(ग) नगरपालिका जुलाना द्वारा कालोनियों के नियमितिकरण के पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सम्बन्धित प्रक्रिया सरकार द्वारा राज्य सरकार के नीति मापदण्ड के अनुरूप विचारी जायेगी।

Cases of Rape, Kidnapping Etc.

81. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the District-wise and year-wise number of cases of rape, kidnapping, abduction, dowry, theft, dacoity and murder registered in the State from the year 2005 till date ; and

(b) the number of cases out of those referred to in part (a) above in which the accused have been arrested ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

बिन्दु क

वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले

अपराध का शीर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
बलात्कार	461	607	485	634	612	717	85
अपहरण/भगा ले जाना	493	633	809	857	895	950	116
दहेज	2285	2505	2681	2736	2893	3002	284
चोरी	8649	10489	11003	12666	12834	16234	1913
डकैती	88	104	137	121	153	146	19
हत्या	782	873	913	921	950	1005	104

बिन्दु ख

वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) उन मामलों का विवरण जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।

अपराध का नाम	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
बलात्कार	422	534	433	552	543	586	64
अपहरण/भगा ले जाना	324	390	509	537	538	568	52
दहेज	1547	1695	1791	1862	1821	1966	163
चोरी	3597	4047	4437	4341	4181	4723	449
डकैती	62	84	109	103	109	109	13
हत्या	606	680	718	713	694	750	74

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
बलात्कार वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले)							
पंचकूला	8	10	11	15	21	10	3
अम्बाला	19	19	23	35	28	30	2
यमुनानगर	14	28	25	28	27	32	6
कुरुक्षेत्र	24	34	21	41	43	36	3
कैथल	19	25	14	14	24	28	2
हिसार	25	23	21	23	33	25	2
सिरसा	15	18	23	31	23	40	0
भिवानी	18	35	17	33	37	30	5
जीन्द	14	32	20	38	36	29	4
फतेहबाद	10	18	7	12	9	21	4
गुड़गांव	17	30	40	35	33	45	11
फरीदाबाद	39	40	37	46	35	46	3
रिवाड़ी	13	21	22	23	19	25	0
पलवल	—	29	15	29	34	42	4
नारनौल	15	17	10	21	10	28	6
मेवात	34	35	45	31	16	28	4
रोहतक	29	34	18	39	36	51	8
सोनीपत	28	31	24	36	32	27	3
करनाल	49	51	45	50	51	52	7
पानीपत	56	61	31	30	42	55	6
झज्जर	13	15	14	22	20	36	2
रेलवे	2	1	2	2	3	1	0
कुल	461	607	485	634	612	717	85
अपहरण/भगा ले जाना वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले							
पंचकूला	15	15	25	26	16	13	1
अम्बाला	24	22	15	55	20	33	5
यमुनानगर	25	28	35	43	57	42	4
कुरुक्षेत्र	15	24	18	31	55	33	6
कैथल	12	14	16	16	19	27	2
हिसार	22	31	47	43	42	84	11
सिरसा	16	11	21	25	43	47	3
भिवानी	24	34	32	47	74	51	5

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
जीन्द	12	15	24	29	45	33	5
फतेहबाद	19	20	25	25	47	33	3
गुड़गांव	38	70	112	89	56	57	6
फरीदाबाद	91	86	154	109	79	102	15
रिवाड़ी	20	15	35	27	36	33	2
पलवल	—	16	22	32	34	39	6
नारनौल	13	26	25	26	21	40	10
मेवात	9	14	30	23	22	36	5
रोहतक	16	23	30	32	43	29	7
सोनीपत	39	67	42	59	56	75	5
करनाल	32	40	28	35	49	33	6
पानीपत	35	51	36	53	53	64	5
झज्जर	14	10	30	26	25	43	4
रेलवे	2	1	7	6	3	3	0
कुल	493	633	809	857	895	950	116

दहेज वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले)

पंचकूला	67	65	70	77	73	99	11
अम्बाला	139	183	170	183	169	229	23
यमुनानगर	131	118	82	110	191	161	12
कुरुक्षेत्र	104	121	110	84	106	92	14
कैथल	121	158	192	163	195	123	8
हिसार	158	175	164	233	223	274	29
सिरसा	129	133	159	136	103	133	14
भिवानी	106	119	145	125	105	86	12
जीन्द	49	59	106	91	108	105	10
फतेहबाद	71	89	124	147	92	84	11
गुड़गांव	81	109	139	142	152	106	8
फरीदाबाद	206	160	187	194	198	248	21
रिवाड़ी	59	55	88	85	69	85	11
पलवल	—	49	63	104	99	103	10
नारनौल	26	51	61	89	68	93	7

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
मेवात	120	132	166	121	186	155	7
रोहतक	88	102	123	123	131	104	8
सोनीपत	138	191	165	173	146	149	9
करनाल	250	233	182	141	242	252	20
पानीपत	138	123	74	75	136	187	21
झज्जर	97	74	106	135	91	129	18
रेलवे	7	6	5	5	10	5	0
कुल	2285	2505	2681	2736	2893	3002	284

चोरी वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले

पंचकूला	224	222	216	427	379	323	54
अम्बाला	267	431	361	415	421	652	69
यमुनानगर	330	380	371	514	492	478	71
कुरुक्षेत्र	412	533	630	565	584	724	82
कैथल	196	279	239	192	283	304	43
हिसार	526	517	494	560	590	829	118
सिरसा	251	257	351	334	313	383	53
भिवानी	376	398	384	554	451	523	90
जीन्द	210	255	259	296	428	560	66
फतेहबाद	157	171	256	298	272	241	37
गुड़गांव	1462	2083	2232	2843	2429	3116	392
फरीदाबाद	1130	1241	1268	945	1132	1671	218
रिवाड़ी	253	278	333	428	379	533	60
पलवल	—	232	254	354	558	617	43
नारनौल	125	176	187	193	160	339	32
मेवात	220	191	200	211	264	407	36
रोहतक	425	471	472	596	685	855	87
सोनीपत	464	546	454	659	774	984	77
करनाल	640	703	695	681	661	836	102
पानीपत	583	667	664	839	752	859	83

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
झज्जर	203	185	260	268	357	527	59
रेलवे	195	273	423	494	470	473	41
कुल	8649	10489	11003	12666	12834	16234	1913

डकैती वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले

पंचकूला	0	1	1	6	8	4	0
अम्बाला	1	7	5	2	5	4	0
यमुनानगर	3	0	1	4	5	6	1
कुरुक्षेत्र	16	4	4	2	13	2	0
कैथल	1	4	6	5	4	6	0
हिसार	3	1	0	1	7	5	0
सिरसा	3	4	3	3	1	3	1
भिवानी	3	9	6	12	5	7	1
जीन्द	1	2	1	0	7	0	0
फतेहबाद	0	0	1	1	1	1	2
गुड़गांव	8	22	32	36	17	5	1
फरीदाबाद	2	7	11	4	5	9	3
रिवाड़ी	10	6	7	4	4	24	1
पलवल	—	3	7	5	10	11	0
नारनौल	2	7	3	2	7	9	4
मेवात	14	4	19	4	9	13	1
रोहतक	3	3	7	4	8	7	2
सोनीपत	2	7	8	11	12	9	0
करनाल	5	6	4	6	11	5	0
पानीपत	9	4	4	3	2	7	1
झज्जर	1	0	4	5	7	7	1
रेलवे	1	3	3	1	5	2	0
कुल	88	104	137	121	153	146	19

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
हत्या वर्ष 2005 से 2011 (15.2.2011 तक) दर्ज मामले							
पंचकूला	9	14	19	17	14	84	0
अम्बाला	24	39	39	31	35	69	4
यमुनानगर	29	27	32	41	36	20	9
कुरुक्षेत्र	25	24	27	20	29	35	0
कैथल	22	24	32	22	21	28	2
हिसार	51	58	55	52	57	34	7
सिरसा	31	37	29	48	36	31	1
भिवानी	47	45	62	56	48	91	9
जीन्द	37	42	34	39	47	45	5
फतेहबाद	21	23	25	20	30	61	0
गुड़गांव	65	93	93	80	84	53	11
फरीदाबाद	76	58	65	59	61	27	9
रिवाड़ी	32	33	18	27	34	29	5
पलवल	—	28	26	33	39	34	6
नारनौल	12	32	28	31	28	31	4
मेवात	19	16	35	19	20	26	0
रोहतक	48	62	56	67	65	72	7
सोनीपत	73	69	75	84	83	81	8
करनाल	46	32	53	40	27	49	7
पानीपत	42	46	36	46	65	32	3
झज्जर	60	51	55	62	66	51	6
रेलवे	13	20	19	27	25	22	1
कुल	782	873	913	921	950	1005	104
बलात्कार के उन मामलों का विवरण जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।							
पंचकूला	8	9	10	10	14	8	2
अम्बाला	19	19	23	35	28	17	2
यमुनानगर	11	23	19	26	21	26	5
कुरुक्षेत्र	20	32	21	31	43	27	3
कैथल	18	23	8	14	22	26	2

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
हिसार	25	20	20	20	32	22	2
सिरसा	15	16	21	26	21	34	0
भिवानी	13	32	16	29	34	25	5
जीन्द	8	30	19	38	35	28	2
फतेहबाद	9	14	6	9	8	20	3
गुड़गांव	31	27	37	30	27	42	8
फरीदाबाद	30	35	32	39	31	36	2
रिवाड़ी	13	18	17	21	15	21	0
पलवल	—	20	7	23	23	28	0
नारनौल	11	13	10	18	9	19	0
मेवात	32	34	42	29	16	28	4
रोहतक	24	33	18	34	31	48	7
सोनीपत	26	24	24	30	29	21	3
करनाल	49	45	41	47	47	41	7
पानीपत	46	52	27	22	35	41	4
झज्जर	13	14	14	20	19	27	3
रेलवे	1	1	1	1	3	1	0
कुल	422	534	433	552	543	586	64
अपहरण / भगा ले जाने के उन मामलों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।							
पंचकूला	8	6	4	9	2	6	0
अम्बाला	24	17	13	35	15	13	2
यमुनानगर	17	20	29	41	31	17	1
कुरुक्षेत्र	8	4	8	11	13	19	0
कैथल	4	6	4	8	5	4	0
हिसार	14	28	34	26	32	57	7
सिरसा	9	6	9	14	23	24	2
भिवानी	18	19	21	35	46	34	4
जीन्द	7	15	22	26	42	31	2
फतेहबाद	11	15	19	17	38	20	4

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
गुड़गांव	32	52	87	57	37	39	2
फरीदाबाद	67	58	93	68	54	61	6
रिवाड़ी	11	10	24	14	19	17	0
पलवल	—	15	13	15	15	24	0
नारनौल	10	17	15	15	9	16	1
मेवात	9	14	28	22	22	34	5
रोहतक	8	11	14	13	13	21	2
सोनीपत	30	49	31	35	38	51	2
करनाल	12	5	10	22	34	8	6
पानीपत	16	19	11	38	26	47	4
झज्जर	8	4	16	14	23	24	2
रेलवे	1	0	4	2	1	1	0
कुल	324	390	509	537	538	568	52
दहेज के उन मामलों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।							
पंचकूला	40	32	36	40	28	33	4
अम्बाला	127	166	168	183	156	202	8
यमुनानगर	115	105	74	97	154	126	8
कुरुक्षेत्र	63	69	63	50	68	73	1
कैथल	62	78	93	69	81	64	2
हिसार	83	98	87	158	141	151	14
सिरसा	61	72	85	78	51	63	4
भिवानी	72	81	89	93	77	65	4
जीन्द	46	56	74	60	84	87	5
फतेहबाद	36	57	78	83	58	48	7
गुड़गांव	63	83	111	110	125	86	5
फरीदाबाद	177	115	156	162	137	185	18
रिवाड़ी	43	38	70	57	44	43	7
पलवल	—	23	32	42	37	70	0
नारनौल	11	28	32	45	48	32	1

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
मेवात	99	103	74	61	50	75	6
रोहतक	55	69	92	89	104	84	7
सोनीपत	93	136	127	134	110	110	9
करनाल	156	153	111	90	83	98	20
पानीपत	66	66	52	58	104	155	16
झज्जर	72	61	84	100	73	112	17
रेलवे	7	6	3	3	8	4	0
कुल	1547	1695	1791	1862	1821	1966	163
चोरी के उन मामलों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।							
पंचकूला	79	106	65	118	89	76	4
अम्बाला	147	191	167	177	152	156	12
यमुनानगर	247	185	237	283	200	164	15
कुरुक्षेत्र	189	225	273	160	136	236	7
कैथल	105	156	104	85	148	187	14
हिसार	282	291	238	272	281	421	43
सिरसा	141	152	175	150	120	126	9
भिवानी	164	172	166	169	177	103	13
जीन्द	75	139	144	137	249	134	7
फतेहबाद	82	97	136	140	112	92	6
गुड़गांव	253	345	558	515	683	643	49
फरीदाबाद	445	424	491	299	323	541	42
रिवाड़ी	108	121	155	149	109	84	11
पलवल	—	47	90	98	70	94	0
नारनौल	76	65	56	89	42	152	9
मेवात	85	45	49	67	42	69	5
रोहतक	194	234	210	218	213	224	23
सोनीपत	201	210	261	297	348	465	19
करनाल	330	307	213	264	138	239	102
पानीपत	211	277	318	312	220	233	34

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
झज्जर	93	109	105	83	99	93	10
रेलवे	90	149	226	259	230	191	15
कुल	3597	4047	4437	4341	4181	4723	449
डकैती के उन मामलों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।							
पंचकूला	0	1	1	3	8	18	0
अम्बाला	1	5	4	2	5	4	0
यमुनानगर	3	0	1	4	2	3	1
कुरुक्षेत्र	3	1	4	1	7	2	0
कैथल	1	3	6	5	3	4	0
हिसार	3	1	0	1	6	3	0
सिरसा	2	5	3	3	1	2	1
भिवानी	3	6	5	10	4	7	1
जीन्द	1	2	1	1	5	0	0
फतेहबाद	0	0	1	1	1	1	2
गुड़गांव	6	17	19	26	11	2	1
फरीदाबाद	2	5	8	3	5	7	2
रिवाड़ी	8	5	5	4	2	12	0
पलवल	—	3	6	3	6	8	0
नारनौल	2	7	3	2	5	4	0
मेवात	13	2	12	4	7	6	1
रोहतक	3	3	6	3	6	5	2
सोनीपत	0	7	7	9	10	5	0
करनाल	2	5	6	6	3	3	0
पानीपत	7	3	4	3	2	5	1
झज्जर	1	0	4	8	6	6	1
रेलवे	1	3	3	1	4	2	0
कुल	62	84	109	103	109	109	13
हत्या के उन मामलों की संख्या जिनमें दोषी गिरफ्तार हुए।							
पंचकूला	7	8	11	14	10	12	0

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

जिला	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 (15.2.11)
अम्बाला	17	31	27	23	27	23	2
यमुनानगर	24	23	26	37	33	23	8
कुरुक्षेत्र	19	21	22	16	16	29	0
कैथल	18	19	22	23	16	22	1
हिसार	40	52	43	41	45	71	5
सिरसा	24	34	23	35	21	33	1
भिवानी	39	35	55	36	31	42	11
जीन्द	32	38	31	29	45	49	5
फतेहबाद	17	17	23	18	22	21	0
गुड़गांव	53	81	71	62	65	60	7
फरीदाबाद	54	45	49	48	43	56	5
रिवाड़ी	26	25	12	16	26	19	3
पलवल	—	15	18	20	27	25	0
नारनौल	10	16	18	20	19	10	1
मेवात	17	10	26	14	13	23	0
रोहतक	37	42	49	58	47	59	4
सोनीपत	49	51	56	66	57	65	5
करनाल	31	23	46	26	20	32	7
पानीपत	35	36	35	39	50	23	2
झज्जर	50	48	48	55	53	43	6
रेलवे	7	10	7	17	8	10	1
कुल	606	680	718	713	694	750	74

Separate Panchayat for Village Khera Ramrai

57. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether the Government is considering to constitute a separate Panchayat for the village Khera Ramrai ;

(b) if so, the time by which above stated Panchayat is likely to be constituted;

(c) the criteria to constitute the new Panchayat ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to include the village Banganwala into the new Panchayat of village Ramrai-Khera ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) व (ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 व 8 के अन्तर्गत सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या ग्राम के किसी भाग अथवा मिलते हुए ग्राम समूह की कम से कम 500 की जनसंख्या से या अधिक को सभा क्षेत्र घोषित करने व सभा क्षेत्र को किसी नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करने में सक्षम है।

(घ) नहीं, श्रीमान जी।

List of CLU

82. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state the District-wise list of CLU (Change of Land Use) issued from the year 2005 till-date alongwith the names, address of parties, area and location ?

Interim Reply

Subject : Unstarred Question No. 82 raised by Sh. Anil Vij, MLA— Budget Session - 2011-12.

The captioned question which has been referred to the Department of Town and Country Planning, Haryana is listed for reply on 8-3-2011. In this regard, it is informed that the information asked by Hon'ble Member is quite voluminous and cannot be compiled in the manner desired by the Hon'ble Member. It will take atleast one month to compile the information. It is, therefore, requested that appropriate time may kindly be given to furnish the required information.

Regards,

Yours Sincerely,
Sd/-
(Randeep Singh Surjewala)

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received an intimation from Shri Sampat Singh, MLA which reads as under :

> "I am unable to attend the sitting of this House from 08th to 10th March, 2011 due to some unavoidable circumstances, therefore, humbly requested the necessary exemption may kindly be granted in this regard".

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave of absence be granted to Shri Sampat Singh, MLA to remain absent from the sitting of the House from 08th to 10th March, 2011?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The leave is granted.

सचिव द्वारा घोषणा

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

Mr. Secretary : Sir, I have to inform the House that the Haryana Dohildar, Butimar, Bhondedar and Muqararidar (Vesting of Proprietary Rights) Bill, 2010, which was passed by the Haryana Legislative Assembly during its Session held in March, 2010, has been assented to by the President.

एस.वाई.एल. तथा हांसी-बुटाना योजक नहर के मामले पर सर्व-सम्मति से संकल्प पारित करने का मामला उठाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention motion notice given of by Shri Aftab Ahmed, MLA regarding acute shortage of teaching staff in the Government Schools in Mewat District. I have admitted it. Shri Aftab Ahmed may read his notice. (Interruption)

Shri Rampal Majra : Speaker Sir, (Interruption)

Mr. Speaker : Mr. Rampal ji, it is a very serious question regarding education in Mewat, which is educationally backward. So, it is a very serious matter.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, कल जब यहां पर हांसी-बुटाना की बात चल रही थी उस समय आपने कहा था कि सारे हाऊस को इस मामले में एकजुट होना चाहिए इसलिए हम इस पर पूरी तरह से तैयार हैं कि इस बारे में एक प्रस्ताव लाया जाये ।

Mr. Speaker : Mr. Arora, are you not concern regarding education in Mewat, which is a part of Haryana?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम तो यह चाहते हैं कि सरकार हांसी-बुटाना के साथ-साथ एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा में लाने के लिए प्रस्ताव लाये। हम इन दोनों प्रस्तावों पर सहमत होंगे । (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है 'देर आयद दुरुस्त आयद।' कल सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को यह कहा था कि क्यों न हरियाणा के हितों पर हम आपस की राजनीति छोड़कर इक्ट्ठे हो जायें । कल तो इन्होंने यह ऑफर नहीं मानी । कल तो ये बिल्कुल मना कर गये । उन्होंने कहा कि टैक्नीकली तौर पर हांसी-बुटाना नहर वॉयेबल नहीं है । सर, आपने भी इस बात को सुना था । आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए । (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने क्लीयर कर दिया है परन्तु फिर भी कोई बात नहीं अगर आज ये सहमत हैं तो आप इनको अपने चैम्बर में बुला लें और बात कर लें । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I will look into the record. (Interruption) आप गवर्नर एड्रैस पर बोलना । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम कल भी इसके लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं।

Mr. Speaker : I would like to see the record in this regard. (Interruption) Let me see the record. (interruption)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मेरा यह सुझाव है कि रिकॉर्ड निकाल कर हॉफ एन आवर डिस्कशन रख दें हम रैजोल्यूशन को तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let me see the record. (Interruption) Members may resume their seats please. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : हम दोनों ही रैजोल्यूशन पर तैयार हैं । आप दोनों रैजोल्यूशन ले आओ हम तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Let me see the record please. Members may resume their seats, please. (Interruption)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

मेवात जिले में राजकीय विद्यालयों में शिक्षण अमले की भारी कमी संबंधी

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेवात जिले में राजकीय विद्यालयों में शिक्षण अमले की भारी कमी है । कई विद्यालयों में बहुत समय से +2 स्तर पर विज्ञान संकाय क्रियात्मक नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I want to know, who does not want to have good education in Mewat? If you want to then please sit down because it is a calling attention notice on this subject.

श्री आफताब अहमत : शिक्षा विभाग इस विषय पर सो रहा है तथा इसके कारण छात्रों का भविष्य नष्ट होने जा रहा है । इस समस्या के तुरन्त समाधान की आवश्यकता है । सरकार को इस मामले को उच्च प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। इस प्रकार, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सदन के पटल पर इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे तथा समस्या को तुरन्त निपटाया जाए । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mewat is a backward area and education is a great concern for them. Now, Education Minister will give reply on it. (Interruption) Let her speak.

वक्तव्य-

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : Speaker Sir, Education Sector is a priority area of focus for the State. State has taken several steps to correct regional imbalances, improve gender parity in education and raise learning achievement levels. State shall provide basic facilities like uniforms, schoolbags, textbooks, dual-desks, class-rooms, playgrounds etc. to all the children in the age group of 6-14 years. The state budget for education in 2005-06 was 1804-83 crores ; in 2010-11 it is 5741.97 crores — thus state investment in education has witnessed a threefold increase over 5 years.

It is submitted that School Education in Mewat district is a priority of the Department of School Education, Haryana. There are 867 Govt. Schools (Primary-527, Middle-272, High-44, Sr. Secondary-24) In Mewat district. The enrolment in these schools is around 2-00 lakhs.

1. Shortage of teaching staff : Presently there is no vacancy of JBT teachers in Mewat. As regards other category vacancies i.e. Masters, Lecturers etc., it is submitted that the counselling process pertaining to the appointment of Mathematics and Science Teachers has begun and the effort of the Department is to fill up the said vacancies of Maths and Science teachers in Mewat district on top priority. As regards vacancies of lecturers, requisition was sent to HPSC in 2009 for 67 maths and 45 chemistry lecturers. Efforts are also being made by the Department to fill up the vacancies through promotion/transfer etc.

2. Science faculty : There are 29 senior secondary schools in Mewat of which 9 schools have science streams. Five of these schools are run by Government and four are run by Mewat Development Authority. Science faculty is provided in the five Govt. Senior Secondary Schools of the district. In all 21 posts are sanctioned for science stream of which 12 are filled and 9 are vacant. The gaps shall be filled within a few months through promotions/ rationalisation. Apart from the above, 5 proposed EBB Schools shall also

have science streams and a special Science School shall be established in Mewat under the MSDP (Multi Sectoral Development Programme) scheme of Ministry of Minority Affairs, Government of India.

3. Promotion of science : In this repidly changing technological world, the role of science education is of vital importance. The development of critical thinking and communication skill is an important by-product of science education. The challenge before us is to find a platform for developing scientific temper in the students specially those who come from the rural background. Hence, following steps are being taken to promote science education.

3.1 Setting up of Science Museums : Science Museum will provide an experiment based learning opportunity to inculcate a spirit of inquiry, foster creative talent and create scientific temper among students. In these museums thematic galleries, fun science, temporary exhibition hall, outdoor science park, tara mandal, educational and training programmes hall and exhibit development lab will be developed. There is a proposal to set up a large Science Museum at a place close to Mewat.

3.2 Science workshops : In order to promote interest in science, lectures on emerging fields of science and technology will be organized in different districts of Haryana. These will be delivered by eminent scientists in their respective fields.

3.3 Haryana Science Talent Search Scheme : In Haryana there is decline in the students opting for subjects of science stream after class X. A science talent search scheme has been introduced from 2010-11. The objective of the scheme is to identify and nurture talented science students in order to attract and create enthusiasm in students for science subjects. The science promotion scholarships to 1000 students (500 rural and 500 urban) shall be distributed on the basis of weightage of marks obtained in science in the written examination conducted by SCERT, Gurgaon. These children will be given scholarship @ Rs. 500/- per month for class IX-X. If they take up science stream in Class XI-XII, the scholarship will continue for two more years.

3.4 Telescope for all districts of Haryana : In order to popularize astronomy and to create awareness among the school students about the basic facts of astronomy, the department will procure large 11 inch telescopes for all twenty one districts of Haryana.

3.5 Exposure visits : In order to promote interest of the students towards science, one of the methods to be adopted is to send children on exposure visits to places of scientific importance, like Kalpana Chawla Memorial Planetarium, Kurukshetra, Bhakra Dam ; visit to Thermal Power Plants at Panipat/Hisar/Yamunanagar; Science City in Kapurthala etc.

3.6 Imparting knowledge of plant Bio-Technology : Centre for Plant Bio-technology Hisar, will impart training to school students in thrust areas of bio-technology. The main activity of the CPB, Hisar is mass

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]
multiplication of elite planting material of crops and plants like medicinal, ornamental, bio-fuel etc.

3.7 Organization of Geo-informatics awareness workshops for school children : India has emerged as one of the leading nations in the world in the field of Space Technology. As this emerging technology provides challenging opportunities to develop a career, the school students are required to be made aware about it and its applications for the society. Therefore, it is proposed to organize awareness workshops on geo-informatics in each district for school children.

3.8 Creation of HARSAC corner in one school at each District : HARSAC (Haryana Remote Sensing Applications Centre, Hisar) has satellite images and maps on natural resources, environment and infrastructure of each district. These shall be put in the HARSAC corner in the selected school. The corner shall have Metallic satellite models of Remote sensing satellites and launch vehicles, High resolution satellite image of district headquarter town, district base maps indicating including road, rail, canals, habitations, including schools, colleges, ITIs, medical hospitals, veterinary hospitals, water works, PO, Banks etc, in each village.

All the above mentioned schemes will benefit children of Mewat and ensure promotion and popularization of science education in the area.

4. Addressing regional disparity in Mewat :

State is committed to ensure holistic development of the special area of Mewat. State is investing heavily in the region to bring it at par with the development indices of the rest of the State.

4.1 Higher budget allocations : There is a total allocation of Rs. 117.53 crores for Mewat district in the SSA (Sarv Shiksha Abhiyan) 2010-11 Plan. Thus, around 14.16% of the total allocation under SSA (2010-11) has been earmarked for Mewat where 19 primary schools have been added and 77 have been upgraded to upper primary level. Under SSA 2351 classrooms have been sanctioned since 2003-04. 625 classrooms were sanctioned under SSA in 2010-11 itself. In RMSA (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan) 13 additional class rooms, 18 science labs and 19 computer labs, 15 headmaster rooms, 22 girls' activity rooms, 23 arts & crafts rooms and 22 EDUSAT/ Library rooms have been got sanctioned for FY 2011-12. A Math lab will also be established in each secondary school to support math education. Computer education will also be provided in all secondary schools of Mewat.

4.2 विशिष्ट स्कूल : राज्य में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 36 खण्डों में मॉडल विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मेवात के प्रत्येक खण्ड में एक–एक मॉडल स्कूल की स्थापना की जायेगी।

4.3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

कन्याओं के लिए एक आवासीय शिक्षा की योजना है, प्रत्येक छात्रावास में 150 छात्राओं की व्यवस्था है, यह विद्यालय अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन छात्राओं के लिए हैं जो विद्यालयों से ड्राप आउट है। यह विद्यालय मेवात के सभी खण्डों में 2005–06 में स्थापित किए गए थे। यह विद्यालय मेवात में काफी प्रसिद्ध हैं। इन विद्यालयों में और अधिक सीटों की मांग की गई है, इन विद्यालयों को उच्च विद्यालय के स्तर तक स्तरोन्नत करने की भी मांग की गई है। अब सरकार द्वारा इस शैक्षणिक स्तर से इन विद्यालयों को उच्च विद्यालय तक स्तरोन्नत कर दिया है।

इस प्रकार पांच ई.बी.बी. मॉडल स्कूल (वरिष्ठ माध्यमिक) पांच कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नूंह में एक कन्या मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है और यह सभी विद्यालय उच्च शिक्षा के स्तर में शैक्षणिक सुविधाओं की कमी को पूरा करेंगे। यह मॉडल विद्यालय सोसायटी के माध्यम से चलाये जायेंगे तथा सोसायटी ही इन विद्यालयों में स्टाफ की भर्ती करेंगे। यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इन विद्यालयों में अध्यापकों के सभी पद भरे रहें।

4.4 विशेष यातायात योजना : मेवात जिले में विद्यार्थियों के लिए यातायात सुविधा का भी प्रावधान किया गया है ताकि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति और उनके ठहराव अवधि में सुधार लाया जा सके।

4.5 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान : मेवात जिले में दो जे.बी.टी. प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। जिनमें सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान फिरोजपुर नमक और निजी सरस्वती प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान फिरोजपुर झिरका में है। जो हर वर्ष 300 अध्यापक तैयार करते हैं। जिले में उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो निजी बी.एड. प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थापित हैं।

4.6 उर्दू को प्राथमिकता : मेवात जिले में पर्याप्त संख्या में उर्दू अध्यापक प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 270 विद्यालयों के लिए 687 उर्दू अध्यापक और 54 उर्दू मास्टर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम उर्दू को प्राथमिकता दें।

4.7 मेवात के अध्यापकों के लिए विशेष कॉडर : राज्य ने मेवात जिले की आर्थिक पिछड़ेपन व भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने अलग शिक्षा कॉडर बनाने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। मेवात में शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्तावित है कि इस कॉडर में सीधी भर्ती के लिए अधिक महत्व दिया जाये ताकि अध्यापकों के पद जल्दी भरें। अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रावधान किया जाये ताकि अचानक हुई रिक्ति को जो कि उन अध्यापकों के स्थानान्तरण के कारण हो सकती है जो इस जिले से बाहर जाना चाहते हैं, शीघ्र भरा जा सके। उर्दू अध्यापकों का प्रावधान यह आश्वस्त करने के लिए किया गया ताकि जिले में सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और पाठ्यक्रम उन्हीं के अनुरूप हो। इन नियमों की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जायेगी।

उपरलिखित सभी बातें सरकार की गम्भीरता को दर्शाती हैं सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रही है कि सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य हो।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में अगर स्कूली बच्चों का ड्राप आऊट रेट देखा जाये तो हमारे जिले मेवात में सबसे चिन्ताजनक और सबसे सर्वाधिक है क्योंकि लोग अपनी बच्चियों को अपने घरों से दूर नहीं भेजते और दसवीं और बाहरवीं के स्कूल घर से दूर हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए मेवात के लिए अपने नार्म्स में रिलैक्सेशन देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि मेवात की overall development is the priority of the Government. माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से मेवात के लिए स्कूलों का अलग से कैडर बनाने की बात की है । दूसरा हमने अभी वर्ष 2010-2011 में 177 स्कूलों को सारे हरियाणा में प्राईमरी से मिडल तक अपग्रेड किए हैं उनमें से अकेले मेवात जिले में 77 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है । अगर माननीय सदस्य इन स्कूलों की सूची चाहते हैं तो मैं वह सूची सदन के पटल पर पढ़कर सुना देती हूं । मेवात जिला बैकवर्ड होने की वजह से वहां पर रिलैक्सेशन देने की बात की है माननीय सदस्य ने जैसा बच्चियों के ड्राप आऊट की चिन्ता की बात है । वाकई वहां पर हमारे स्कूलों की कमी थी। हमने मेवात जिले में जो हमारे मॉडल स्कूल हैं वहां पर बनाये हैं । इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय है वह मेवात जिले के हर ब्लॉक में एक-एक बनाया गया है । सरकार की यह प्राथमिकता रही है । मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ड्राप आऊट का एक कारण अध्यापकों की कमी हो सकता है । इसके लिए हम ने विशेष तौर से मेवात के लिए अलग से कैडर बनाने की बात की है । माननीय सदस्य और इस सदन की जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगी कि इस समय मेवात में 3320 जे.बी.टी. अध्यापकों की पोस्ट्स हैं जिनमें से 2308 पोस्ट्स तो रेगूलर अध्यापकों से भरी हुई हैं और 1012 पोस्ट्स गैस्ट फैकल्टी से भरी हुई हैं । वहां पर जे.बी.टी. की जीरो वेकेन्सी हैं, सभी सीटें हमारी भरी हुई हैं । इसी प्रकार से सी.एन.वी. की 718 पोस्ट्स हैं उनमें से 363 पोस्ट्स भरी हुई हैं और 77 पोस्ट्स गैस्ट फैकल्टी की हैं । इसी प्रकार मास्टर्ज की 1012 पोस्ट्स में से 365 भरी हुई हैं और गैस्ट फैकल्टी वहां लगी हुई हैं। सर, 494 पोस्ट्स खाली हैं। इसी प्रकार लैक्चर्रस हैं उनकी सभी पोस्ट्स के लिए उसकी रिक्वीजीशन एच.पी.एस.सी. को भेजी हुई हैं और अतिशीघ्र इनको भर लिया जायेगा।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आठवीं से दसवीं और दसवीं से 12वीं के स्कूल अपग्रेडेशन के लिए मेवात जिले के लिए नार्म्स में रिलैक्सेशन के बारे में सरकार ने कोई प्रावधान किया है या नहीं ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेवात जिला ऐजूकेशनली बैकवर्ड एरिया है । हमने भारत सरकार को अपग्रेडेशन की जो लिस्ट भेजी है उसमें सबसे ज्यादा मेवात के स्कूल अपग्रेड होकर आये हैं । जो 10वीं से 12वीं के स्कूल अपग्रेड करने की बात की जा रही है । विशेष तौर से जैसा कि संख्या हमने बतायी हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि यह बैकवर्ड एरिया है और वहां पर रिलैक्सेशन की जरूरत रहेगी । हम जरूर वहां रिलैक्सेशन करने के बाद स्कूलों को अपग्रेड करेंगे । लेकिन बच्चों की संख्या के हिसाब से जरूर अपग्रेड करेंगे ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेवात को बार- बार बैकवर्ड क्यों कहा जा रहा है ।

Mr. Speaker : But I am still allowing you because you belong to Mewat and very important matter is discussing.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि हर क्षेत्र में खास तौर से ऐजूकेशन में मेवात पिछड़ा हुआ है ।

Mr. Speaker : I think there is a detailed reply given by the Hon'ble Minister in this regard. The reasons have also been enumerated.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, बार बार मेवात को पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाता है ? हमें बेचारा क्यों बनाया जाता है । सरकार क्यों नहीं इस तरह के कदम उठाती कि मेवात का पिछड़ापन दूर हो सके ?

Mr. Speaker : Hon'ble Member, it shows the concern in regard to Mewat.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, इतने साल हो गए, क्या मेवात अभी भी पिछड़ा हुआ रहेगा ? अभी यहां खेल नीति का जिक्र आया था इसमें कहीं मेवात का जिक्र नहीं है कि मेवात के लिए सरकार क्या कर रही है । हमारा मानना यह है कि मेवात के लिए अलग से खेल नीति बनाई जाए, अलग से एजूकेशन नीति बनाई जाए । अभी एक प्रश्न आया था उसमें कहीं मेवात का जिक्र नहीं है । मेवात के बच्चों के लिए ये क्या नई एजूकेशन नीति ला रहे हैं ?

Mr. Speaker : Exhaustive reply has given by the Hon'ble Minister in this regard. .

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि हमने डिटेल में जवाब दिया है । मेवात में मुख्यमंत्री महोदय और सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister may reply please.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने मेवात में स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात की तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि बाकी एरियाज में अपग्रेडेशन के लिए स्कूल में बच्चों की संख्या 210 होनी चाहिए जबकि मेवात में बच्चों की संख्या हमने 150 रखी हुई है । छात्रों के लिए विशेष तौर पर बसों की फैसिलिटीज दी गई हैं । दूसरा इन्होंने कहा कि मेवात को बार-बार बैकवर्ड कहा जाता है तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हम मेवात को बहुत आगे ले जा रहे हैं । आई.टी.आई. डिपार्टमैंट मेवात में फिरोजपुर झिरका, नगीना और उजीना में नई आई.टी.आईज. बनाने जा रहा है जिनका 70 परसैंट काम पूरा हो चुका है । 13वें फाईनांस कमीशन की ग्रांट आ गई है A grant of 100 crore have been recommended by

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]

the 13th Finance Commission for the development of infrastructure for ITIs in Mewat और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी स्वयं मेवात में गए थे और उन्होंने कई ब्लाक्स में नई आई.टी.आईज. खोलने की घोषणा की थी । वहां पर इस समय पुन्हानां, तावडू और उजीना वूमैन आई.टी.आईज. हैं । पिनागांवा में भी वूमैन आई.टी.आई. है । फिरोजपुर झिरका में भी अलग से वूमैन आई.टी.आई. और पुन्हानां में भी अलग से वूमैन आई.टी.आई. का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा 7 और नई आई.टी.आईज. का प्रावधान करने जा रहे हैं। फिरोजपुर झिरका, उजीना और नगीना आई.टी.आईज. का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। आई.टी.आईज. के साथ साथ उच्च शिक्षा की बात करें तो इस समय गवर्नमैंट कालेज नगीना को गवर्नमैंट ने टेक ओवर किया है वहां आर्टस, कॉमर्स के कोर्सिस चल रहे हैं । इस कालेज में बच्चों की संख्या 665 है । गवर्नमैंट कालेज तावडू में भी आर्टस, कॉमर्स और दूसरे जॉब ओरियंटिड कोर्सिज शुरू हैं । इस कालेज में बच्चों की संख्या करीब 621 है । सैंटर आफ एक्सीलैंसी कालेज के लिए पूरे हरियाणा में 25 कालेज चुने गए हैं उनमें तावडू के कालेज को भी लिया गया है । मेवात में प्राइवेट एडिड कालेज, स्कूल भी हैं और सैल्फ फाइनांस के भी काफी स्कूल हैं । इस समय प्रायरिटी सैक्टर की बात करें तो मेवात को जो बैकवर्ड कहा जाता है उसको आगे ले जाने में हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह प्रयासरत हैं ।

Mr. Speaker : Thank you. I think enough has been said.

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Hon'ble Chief Minister will make a statement on International Women's day.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है । इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं प्रदेश की सभी महिलाओं को शुभ कामनाएं देता हूं । हमारी संस्कृति में महिलाओं का विशेष स्थान रहा है । मातृ शक्ति की हमेशा पूजा की जाती है । हमारे वेदों में वर्णित है कि मातृ और मातृ भूमि की जो भी सेवा करता है वह सीधा स्वर्ग जाता है यानि जननी और जन्मभूमि का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं जिससे बहुत सी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं । बिगड़े हुए लिंगानुपात को सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं जिसके अच्छे परिणाम निकले हैं। इस दिवस के अवसर पर भी हमने कुछ प्रगतिशील फैसले लिए हैं जिनसे मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा । लाडली सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत जिन माता पिता की 2 लड़कियां हैं यानि उनका लड़का नहीं है उनको 45 वर्ष की आयु में 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देते हैं ताकि लड़की को बोझ न माना जाए । अब हमने यह निर्णय लिया है कि यह राशि भविष्य में माता के खाते में ही दी जाएगी क्योंकि माता के पास पहुंची

12.00 बजे

हुई रकम परिवार के कल्याण और विशेष कर लड़कियों की शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी। इसी प्रकार महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत बी.पी.एल.,

एस.सीज. और बी.सी. 'ए' कैटेगरी के परिवारों को 100-100 गज के रिहायशी प्लाट मुफ्त में दिए गए हैं। उसमें अब हमने यह फैसला किया है कि उन प्लाटों की रजिस्ट्री माता-पिता दोनों के नाम संयुक्त रूप से होगी । इसी तरह से जो आंगनवाड़ी वर्कर्ज ग्राउंड लैवल पर काम करती हैं उनको पहले 3000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे । उसमें कुछ बढ़ोत्तरी केंद्र सरकार ने की है और आज महिला दिवस के अवसर पर कुछ बढ़ोत्तरी करके अब उनको 5000 रुपये प्रति माह दिए जायेंगे । इन्हीं के साथ-साथ जो आंगनवाड़ी हैल्पर्ज हैं उनको जहां पहले 1500 रुपये प्रति माह मिलते थे उनके लिए भी केन्द्र सरकार ने कुछ बढ़ोत्तरी की है और कुछ बढ़ोत्तरी हमने की है अब उनको 2500 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे । (इस समय मेजें थपथपाई गई।) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिला उत्थान नीति के प्रति कटिबद्ध है और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि आज महिला दिवस के उपलक्ष में सभी ऐसा कार्य करें ताकि महिलाओं को अपने समाज में उचित स्थान मिले और उनका वही सम्मान हो जो हमारी पुरानी संस्कृति में होता था । धन्यवाद ।

Mr. Speaker : Kavita ji, are you want to speak on Mahila Divas?

Smt. Kavita Jain : Yes, Sir.

Mr. Speaker : O.K.

श्रीमती कविता जैन (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महिला दिवस पर सभी को बधाई देना चाहूंगी । आज पूरा संसार इस बात को मान चुका है कि महिलाएं हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का, विज्ञान का, राजनीति का, अंतरिक्ष में जाने का या मल्टी नैशनल कंपनीज में जाने का यानि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपना नाम न कमाया हो । आज के युग में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है । इसी तरह से हमारी हरियाणा सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध है जैसा अभी बताया गया है और अभी मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमैंट भी की है । इसके अतिरिक्त पंचकूला में भी जो महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 26 दिस्मबर, 2010 को स्कूल लैक्चरार्ज की 1317 पदों को भरने के लिए एक स्क्रीनिंग टैस्ट का आयोजन किया गया था । जिसके इन्टरव्यू के लिए जब रिजल्ट घोषित किया गया उसके अंदर महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन पर सीमित कर दिया गया और 67 प्रतिशत के लिए पुरुषों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अशोभनीय है और यह हरियाणा सरकार के इस दावे को झूठा साबित करता है कि ये महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कंसर्न है ।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन एक इनडिपैंडैंट स्टेच्यूटरी बॉडी है जिनके द्वारा सिलैक्शंज की गई हैं । पब्लिक सर्विस कमीशन भी इनडिपैंडैंट कांस्टीच्यूशनल बॉडी है । मैं माननीय सदस्या जी से अनुरोध करूंगा कि एक ऐतिहासिक फैसला आंगनवाड़ी वर्कर्ज, आंगनवाड़ी हैल्पर्ज और हमारी माताओं के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है बजाय उसकी तारीफ करने के विपक्ष को भी यह

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
सोचना पड़ेगा कि महिला दिवस पर भी हम केवल अपने आपको आलोचना तक सीमित रखें यह ठीक नहीं है ।

Mr. Speaker : I think there should be no controversial speech.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने प्वायंट रेज किया है यह बहुत उचित है और इस बारे में पूरा सदन और सरकार भी इस बात के पक्ष में थी । जो एच.पी.एस.सी. का इन्होंने जिक्र किया है यह तथ्य है । उन्होंने जो कट ऑफ मार्क रखे हैं वे महिलाओं के ज्यादा और पुरुषों के कम रखे हैं । लेकिन इसमें सरकार ने अपनी कंसर्न शो की है और एच.पी.एस.सी. को भी लिखा है कि उनको एट पार करें । अभी इसमें नियुक्तियां नहीं हुई हैं। उन्होंने केवल कट ऑफ लाईन डिक्लेयर की है हमने इस बारे में एच.पी.एस.सी. से निवेदन कर दिया है कि वे इस बात को रैक्टीफाई करें हालांकि वे अपना फैसला खुद लेते हैं ।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने आज महिला दिवस के अवसर पर जो यह अनाऊंसमैंट की है कि लाडली पैंशन है यह महिलाओं को मिलनी चाहिए । यह एक बहुत ही सराहनीय बात है । इसके अलावा जो हमारे प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट्स दिये जाते थे पहले उनकी रजिस्ट्री पुरुषों के नाम होती थी जिसे वे बेच देते थे । अब इन प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां महिला और पुरुष दोनों के नाम होंगी जिससे पुरुष अपनी मर्जी से प्लॉट्स को नहीं बेच सकेंगे। यह भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जनहित में लिया गया बहुत ही अच्छा फैसला है क्योंकि इससे हमारे प्रदेश की महिलायें अपने आप में सिक्योर फील करेंगी। अभी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी करके उसे 5000/- रुपये मासिक किया गया है और आंगनवाड़ी हैल्पर के मानदेय को भी बढ़ाकर 2500/- रुपये प्रति मास किया गया है । इसके लिए भी मैं प्रदेश की सभी महिलाओं और विशेष आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हैल्पर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । इसके अलावा जो अभी हमारी एक बहन ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि कम से कम इतनी महिलायें तो मिलें (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है ।

Mr. Speaker : Mr. Arora, please take your seat. Sumita Ji, please continue. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिए वे एक महिला साथी को सदन में अपने विचार प्रकट करते समय डिस्टर्ब न करें ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब किसी विषय पर खड़े होकर स्थिति को स्पष्ट कर दिया है तो फिर माननीय सदस्या क्यों उसी विषय को दोबारा दोहरा रही हैं ।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, महिलाओं के बारे में जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा और महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं बनाकर उनको सच्चे अर्थों में अमलीजामा पहनाया इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं । सर, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक क्रांतिकारी सोच थी कि जो हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां को-एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती उनके लिए खानपुर कलां (सोनीपत) में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके साथ-साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे करनाल की बेटी कल्पना चावला, जिसने पूरे विश्व में करनाल और हरियाणा का नाम रोशन किया, के नाम पर करनाल में एक मैडीकल कालेज का निर्माण शुरू करने की घोषणा की है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं । इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक छोटी सी मांग लाना चाहती हूं । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के नाम किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री करवाने पर स्टॉम्प ड्यूटी में 2 परसैंट की छूट दी गई है यह एक बहुत ही अच्छी बात है । इससे पहले ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। इस प्रावधान के कारण प्रदेश के पुरूष ज्यादा से ज्यादा घर, जमीन और दूसरी प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम करवाने लगे हैं । मैं यह चाहती हूं कि स्टॉम्प ड्यूटी में इस 2 परसैंट की छूट को बढ़ाकर अगर 3 परसैंट कर दिया जाता है तो इससे इसका और ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद ।

Mr. Speaker : Is there any Member who wants to speak positively?

Dr. Ajay Singh Chautala : Sir, I want to speak.

Mr. Speaker : O.K. Mr. Chautala, you may speak, please.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो घोषणा की है उसके लिए तो मैं उनकी भी सराहना करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं । यह उन्होंने एक अच्छा काम किया है और साथ में जो भेदभाव खत्म करने की बात की गई है वह भी बहुत अच्छा कदम है । आंगनवाड़ी हैल्पर का मानदेय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मास किया है मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि आज महंगाई का युग है इसलिए ऐसे में कम से कम मिनीमम वेज़िज तो आंगनवाड़ी हैल्पर को दिये ही जाने चाहिएं । अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं तो उससे सारे का सारा सदन एकमत से सहमत होगा ।

Mr. Speaker : I think the suggestion has come.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक कालिंग अटैंशन मोशन महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारण्टी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर गम्भीर अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार सम्बंधी था । कृपया उसके बारे में भी बता दें ।

Mr. Speaker : Vij Sahib, with a great smile, I have received your calling attention notice this morning. Let me at least consider it.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरे तारांकित प्रश्नों के जवाब नहीं आये । वर्ष 2005 से लेकर सरकार ने कितने सी.एल.यू. जारी किये हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

वृद्धावस्था पेंशन में बड़ी संख्या में अनियमितताओं संबंधी

Mr. Speaker : A calling attention motion notice has been received from Shri Ashok Kumar Arora and two other MLAs regarding large number of irregularities in old-age pension. I have admitted it. Shri Raghbir Singh Badhra, MLA and Shri Rameshwar Dayal, MLA, who are also signatories, can also ask supplementaries on this. (Interruption) Mr. Arora is a former Speaker as well as a senior member and he is raising a very important issue. So, let him speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं और कर्नल रघबीर सिंह बाढड़ा तथा रामेश्वर दयाल, एम.एल.एज. इस महान सदन का ध्यान एक आवश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि राज्य में वृद्धावस्था पैंशनर्ज की सूची में बहुत बड़ी अनियमितताएं होने के कारण राज्य के लोगों में बहुत भारी रोष तथा निराशा है । पात्र व्यक्तियों का बहुत बड़ी संख्या में विरोध है । जिन पात्र व्यक्तियों के नाम सूचियों में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, उन के साथ बहुत बड़ा अन्याय एवं भेदभाव है । यह सरकार की लापरवाही, अनुत्तरदायित्व तथा दयनीय कार्य प्रणाली को चित्रित करता है । इस भारी चूक के दृष्टिगत सरकार को सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए ।

वक्तव्य –

शिक्षा मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, राज्य के 65 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1.4.1964 को संयुक्त पंजाब के समय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें मासिक पेंशन 15/– रुपये तथा लाभपात्रों की संख्या 2362 थी। यह योजना इसी प्रकार जारी रही, जिसमें समय–2 पर बढ़ौतरी की जाती रही तथा वर्ष 1987 में पेंशन की दर बढ़ाकर 100/– रुपये मासिक कर दी गई। इस क्रम में वर्ष 2005 उल्लेखनीय रहा, जिसमें पेंशन की दर बढ़ाकर 300/– रुपये मासिक कर दी गई।

पेंशन वितरण में पेश आ रही कमियों तथा समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा

सरकार ने वर्ष 2006 में पेंशन वितरण कार्य राजस्व विभाग से लेकर सही प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया। 1 मार्च, 2009 से पेंशन 300/– से बढ़ाकर 500/– रुपये मासिक करते हुए 200/– रुपये की भारी वृद्धि की गई। इसके साथ ही जो पेंशनधारक 1 मार्च, 2009 को गत 10 वर्ष से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 700/– रुपये मासिक दर से अधिक पेंशन दी गई। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान स्वरूप एक मुश्त 501/– रुपये की सहायता पुरुषों को डोगा तथा महिलाओं को शॉल की ऐवज में दी गई। सरकार ने अब इस योजना के तहत 1.3.1999 से 1.4.2010 के बीच पंजीकृत सभी पेंशनधारकों की पेंशन 500/– रुपये से बढ़ाकर 550/– रुपये मासिक करने का निर्णय लिया है, यह वृद्धि अप्रैल, 2011 (मई, 2011 में देय) से प्रभावी होगी।

इस समय 10,88,438 व्यक्ति 500/– रुपये मासिक की दर से तथा 3,14,871 लाभपात्र 700/– रुपये मासिक दर से बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान तथा योगदान को ध्यान में रखते हुए इस योजना को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के रूप में पहचान दी है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत लाभपात्रों की बढ़ी हुई संख्या निम्न तालिका से स्पष्ट होती है :

क्रम सं.	अवधि	पहचान किये गये व्यक्तियों की संख्या
1.	अप्रैल 1993	80,224
2.	अप्रैल 1995	94,368
3.	फरवरी–मार्च 1997	83,564
4.	फरवरी–मार्च 1999	98,846
5.	दिसम्बर 1999	2,56,956
6.	जनवरी व फरवरी 2000	69,977
7.	मई व जून 2002	1,10,900
8.	जुलाई–अक्तूबर 2004	1,51,475
9.	अगस्त–अक्तूबर, 2005	1,73,291
10.	नवम्बर व दिसम्बर, 2007	1,97,274
11.	नवम्बर व दिसम्बर, 2008	1,90,586
12.	नवम्बर व दिसम्बर, 2009	1,94,394

वर्तमान सरकार ने योग्य लाभपात्रों की पहचान के लिये सक्रिय प्रक्रिया अपनाई है। इससे पूर्व नये लाभपात्रों की पहचान के लिये कोई निर्धारित रूपरेखा नहीं थी। नये योग्य लाभपात्रों को योजना में शामिल करने के लिये केवल तदर्थ आधार पर नया सर्वेक्षण करवाया जाता था। अब सरकार ने वर्ष 2007 से नियमित वार्षिक सर्वेक्षण का प्रावधान किया है, ताकि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है या 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी कारणवश पहले सर्वेक्षण में छूट गये थे, के नाम इस योजना में जोड़े जा सकें। इस प्रक्रिया में और सुधार लाते हुए 1 अप्रैल, 2011 से नाम जोड़ने की सतत् प्रक्रिया के रूप में लागू किया जा रहा है। अब वरिष्ठ नागरिकों को सर्वेक्षण टीम के गांव में आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनकी आयु 60 वर्ष होने पर वे साल के दौरान किसी भी समय

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]
आवेदन कर सकते हैं इससे योग्य लाभपात्रों का किसी कारणवश योजना में नाम छूटने की शिकायत काफी हद तक कम हो सकेगी।

वर्तमान पात्रता मानदण्ड विस्तृत होने के बावजूद भी उसमें कुछ खामियां थीं, जो जनसाधारण के लिये सुगमता से समझने योग्य नहीं थी। इसलिये योजना के नाम, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के सही अनुरूप ऐसा हर वरिष्ठ नागरिक जो कोई सरकारी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है अथवा जिनकी पति/पत्नी सहित अपनी वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्ति का हकदार होगा।

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े जो वर्तमान वर्ष 2010–11 में प्रोजैक्ट किये गये हैं, अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वर्ग का है। 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या वर्ग के 75 प्रतिशत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं तथा अन्य 20 प्रतिशत विधवा व बेसहारा पैंशन के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं। इसलिये यह कहना गलत होगा कि कोई योग्य लाभपात्र वृद्धावस्था भत्ता योजना से छूट गया है तथा अयोग्य व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत लाभपात्रों की अत्याधिक संख्या होने के कारण अपवाद स्वरूप कुछ मामले हो सकते हैं, जिनमें अयोग्य लाभपात्रों के नाम जुड़ गये हों या योग्य लाभपात्रों के नाम छूट गये हों। जब कभी भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो इसकी पूर्ण जांच करवाई जाती है तथा उम्मीदवार अयोग्य पाये जाने की स्थिति में उसकी पेंशन रोक दी जाती है तथा भूतकाल में प्राप्त की गई गलत पेंशन की वसूली भी की जाती है। सरकार का मुख्य ध्यान इस बिन्दु पर है कि कोई भी योग्य लाभपात्र छूट नहीं पाये। इसके साथ ही सरकार का यह भी प्रयास है कि अयोग्य व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त न कर सके। नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखे जाने से कम आयु के व्यक्तियों की शिकायत काफी हद तक कम होगी क्योंकि अब हर व्यक्ति को यह विश्वास है कि उसकी आयु 60 वर्ष होने पर उसे पैंशन का लाभ अवश्यक मिलेगा। पेंशन धारकों की सूची में कथित अनियमितताओं के कारण राज्य के लोगों में निराशा तथा नाराजगी का आरोप केवल कपोल कल्पना है।

भावी सुधार

लाभपात्रों की पहचान तथा मानवीय पैंशन वितरण प्रणाली में कई खामियां सरकार के ध्यान में आई हैं, जिनके लिये निम्न प्रभावी उपाय किये गये हैं :

1. वृद्धावस्था पैंशन, विधवा पैंशन, विकलांग पैंशन तथा लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभपात्रों की पूरी सूची विभाग की वैबसाईट www.socialjusticehry.gov.in पर डाल दी गई है। आज की तारीख में कुल 21,22,467 पैंशनधारकों के आंकड़े विभाग की वैबसाईट www.socialjusticehry.gov.in पर डाल दी गई है, जो खोलकर देखे जा सकते हैं इससे विभाग की कार्य प्रणाली में काफी पारदर्शिता आयेगी। वैबसाईट से लाभपात्रों की सूची सम्बन्धित खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी द्वारा नियमित समय अनुसार गांव वाईज छापी जायेगी तथा ऐसे स्थानों, जहां इंटरनेट की पहुंच कम है, पर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से खण्ड/गांव

स्तर पर प्रदर्शित की जायेगी। नगरपालिकाओं के वार्ड बाईज इसी प्रकार के उपाय शहरी क्षेत्रों में भी किये जायेंगे।

2. वास्तविक प्राप्ति रसीदों (ए.पी.आरस.) में वितरित की गई राशियों में हाथ से परिवर्तन करने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी मैनुअल करप्शन इसमें नहीं होगी।

3. वास्तविक प्राप्ति रसीदों (ए.सी.आरस.) में हाथ से नाम जोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

4. आवश्यकता अनुसार आंकड़ों के नवीनीकरण की सुविधा सहित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित वैबसाईट पर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपडेट किये गये आंकड़ों के आधार पर वास्तविक प्राप्ति रसीदों (ए.पी. आरस.) की छपाई की जाती है।

विभाग के पत्र दिनांक 04.03.2011 द्वारा प्रधान महालेखाकार, हरियाणा से अनुरोध किया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय की दो महीने की वास्तविक प्राप्ति रसीदों (ए.पी.आरस.) का आकस्मिक लेखा परीक्षा करें, जिससे वर्तमान पैंशन वितरण प्रणाली की खामियों का पता लग सके तथा उन्हें दूर करने के प्रभावी उपाय किये जा सकें।

भौतिक रूप में पैंशन वितरण तथा राशि जारी करने व लाभपात्रों द्वारा राशि की वास्तविक प्राप्ति के बीच लगने वाले समय संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार द्वारा पूरे राज्य में वित्त मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक की योजना अनुसार स्मार्ट कार्ड्स के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक बैंकिंग ट्रांसफर स्कीम अपनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि पैंशन का वितरण सीधा लाभपात्रों के बैंक खातों में हो सके। प्रयोग किये जाने वाले बायो–मीट्रिक्स लाभपात्रों के चेहरे तथा 10 उंगलियों के निशान होंगे, जिनकी डाटाबेस–सिस्टम में बैंकों द्वारा पकड़ की जायेगी। पैंशन वितरण की ई.बी.टी. प्रणाली अनुसार पेंशन राशि बैंकों को निर्देश देने के 24 घंटे के भीतर सीधी पेंशनधारक के बैंक खाते में जमा हो जायेगी। इससे लाभपात्र की पहचान, प्राप्त की गई राशि तथा राशि प्राप्ति में लगे समय सम्बन्धी शिकायतें कम हो सकेंगी। इससे लेखों का मिलान करना भी आसान होगा। यह वर्तमान पैंशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा। अब उसी अथवा पड़ौसी गांव का व्यवसाय सहकारी युवक स्वयं गांव में पैंशन वितरण करेगा। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा मनमानी किये जाने की शिकायतों का उन्मूलन हो सकेगा।

पेंशनधारकों के आंकड़ों का सैंट्रल डाटाबेस पेंशनधारकों की उंगलियों के 4 सर्वोत्तम निशानों के आधार पर तैयार किया जायेगा। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी लाभपात्र इस प्रणाली में दोबारा पंजीकृत नहीं होगा तथा आधुनिक तकनीक के प्रयोग से एक ही व्यक्ति द्वारा योजना का बहु–लाभ लेना पूर्णतया रोका जा सकेगा। आगामी चरण में बैंकों द्वारा निर्मित केन्द्रीय सुरक्षा कोष को पूर्ण करते हुए लाभपात्र की फोटो वैबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी, जिससे वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। सरकार ई.बी.टी. स्कीम के माध्यम से इस वितरण प्रणाली को अप्रैल, 2011 (मई, 2011 में देय) से अनिवार्य

[श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल]
करना चाहती है, ताकि पेंशन का वितरण शीघ्रता से सीधा लाभपात्रों के बैंक खातों में पहुंच सके तथा जाली पहचानों का पता लग सके। ई.बी.टी. वितरण प्रणाली सही लाभपात्रों के लिये भी सुविधाजनक होगी, जो समय पर उनके बैंक खातों में पैंशन जमा होने की गारन्टी देगी। ई.बी.टी. प्रणाली के तहत लाभपात्रों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भविष्य में लगातार जारी रहेगी।

वर्तमान प्रणाली में असन्दिग्ध लाभपात्रों द्वारा गलत पैंशन प्राप्त किये जाने की स्थिति में जुर्माना किये जाने का प्रावधान भी नहीं था। सरकार द्वारा अब गलत रूप से पैंशन लाभ लिये जाने की स्थिति में 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति द्वारा दूसरी पेंशन योजना के तहत यदि कोई लाभ प्राप्त किया गया है, तो वह भी वापिस ले लिया जायेगा। वृद्धावस्था पैंशन योजना के तरीकों व प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा कई उपाय किये जा रहे हैं।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मंत्री महोदया ने जो आज सदन में बयान दिया, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कल ही मंत्री महोदया ने इस हाउस में यह माना था कि अनियमितताएं पाई गई हैं और आज ये कह रही हैं कि ये आरोप निराधार हैं। मैं सवाल पूछने से पहले आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप कल की कार्यवाही का रिकार्ड निकलवा कर मंत्री महोदया को दिखा दें। (विघ्न) ये कल के अपने बयान से आज ही बदल गई हैं । आज महिला दिवस है । आज के दिन तो आप सच बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि इसके अलावा यह भी पढ़ लो। मैंने यह भी कहा था कि कुछ अपवाद हैं। आज भी यह बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अरोड़ा जी, ऐसी बात आप न कहें। महिलाएं हमेशा ही सच बोलती हैं, आज के दिन की क्या बात है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, कोई भी झूठी और गलत स्टेटमैंट हमने सदन के पटल पर नहीं दी न तो कल दी थी और न ही आज दी है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि जो रिप्लाई टेबल पर रखी है उसको ध्यान से पढ़े हमने यह कहा है कि आज भी कहीं न कहीं अपवाद है । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि माननीय सदस्य की कान्सटीच्यूएंसी की टोटल लिस्ट जोकि वैबसाईट पर अवेलेबल है उसमें कुछ ऐसे पैंशनर्ज थे जो पैंशन गलत ले रहे थे । न केवल आपकी कान्सटीच्यूएंसी में बल्कि पूरे हरियाणा में जो भी गलत पैंशन ले रहा है उनसे 12 प्रतिशत ब्याज समेत वह राशि वापस लेंगे ऐसी हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां कहीं भी पैंशन योजना में अनियमितताएं पाई गई हैं वहां के अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि जहां कहीं भी पैंशन वितरण में चाहे वह बुजुर्गों की पैंशन हो या कोई दूसरी पैंशन हो जहां कहीं से भी शिकायत आई हैं हमने उन सब जगहों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की है । यह सारा डेटा हमने वैबसाईट पर दिया हुआ है ताकि हर व्यक्ति इसको देख सके । अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंच के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगी कि चाहे कैथल जिला हो, चाहे झज्जर जिला हो, चाहे करनाल हो, चाहे रोहतक हो और चाहे सिरसा हो जहां कहीं से भी शिकायत आई है हमने सभी जगह पर आफिसर्ज को चार्जशीट किया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही भी की है ।

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो महिला दिवस पर मैं महिलाओं को मुबारिकबाद देता हूं । साथ ही मैं प्रश्न करता हूं कि मैंने पिछले सदन में भी वृद्धावस्था पैंशन के बारे में बोला था कि यह सम्मान भत्ता है । इसको 500 और 700 रुपये अलग-अलग करने की क्या जरूरत पड़ गई । उसके लिए मंत्री जी का जवाब था कि बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया है । माननीय मंत्री जी को एक उदाहरण देकर बताया था कि 80 साल के बुजुर्ग तो 500 रुपये ले रहे हैं और 65 साल के बुजुर्ग 700 रुपये ले रहे हैं । उन्होंने यह कहा था कि इसके लिए आप इन्क्वायरी करेंगे लेकिन आज तक इस बारे में भिवानी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां इन्वेस्टिगेशन की गई हो ?

Mr. Speaker : What is your question?

कर्नल रघबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 65 और 70 साल के लोग तो 700 रुपये पैंशन ले रहे हैं और 80 साल के 500 रुपये ले रहे हैं इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है क्या इस बारे में कोई इन्क्वायरी की गई है । आज जो लिस्ट आई है उसमें 50 वर्ष के लोग तो पैंशन ले रहे हैं और 65 और 70 साल के लोग पीछे रह गये हैं जिनको पैंशन नहीं मिली है इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : माननीय स्पीकर सर, मैं हमारे सदस्य को बताना चाहती हूं कि काल एटैंशन मोशन में भी इनका खुद का भी नाम था । अगर कोई गलत ढंग से पैंशन ले रहा है और आप हमें उसकी सूचना देंगें तो हम ब्याज सहित उससे वापिसी लेंगे और साथ ही साथ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बाढड़ा की बात कही है तो मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि ऐसे लाभार्थी जो 60 साल से नीचे हैं और वे पैंशन ले रहे हैं तो उनकी सूची हमें जरूर दे दें ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि जिनकी पैंशन बन नहीं पाई और वे इसके पात्र हैं तो उनकी भी सूची ये ले लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने एजैंट छोड़ रखे हैं । ये इन एजैंटों के मार्फत पैंशन बनाते हैं । 40

[श्री रामेश्वर दयाल]
साल की उम्र के और 50 साल की उम्र के लोग पैंशन ले रहे हैं जबकि 65 साल के बुजुर्गों को पैंशन नहीं मिल रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर कोई रोक टोक लगाई है ?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister has already replied to that.

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारा कालिंग अटैंशन मोशन यहां आया । काबिल साथी को उसको वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनना चाहिए था । उसमें ये सारी बातें कही गई हैं । इस तरह की शिकायतें अकसर हमारे पास आ रही थी इसलिए हमने सारे का सारा पैंशन बनाने और बांटने का काम बैंको के माध्यम से कर दिया है । हमारे कोर्डीनेटर गांव गांव जाकर बायो मैट्रिक कार्ड देंगें । पैंशनर्स के बैंकों में खाते खुल रहे हैं । हमने सभी जिलों में बैंकों के माध्यम से पैंशन देने का प्रावधान किया है ताकि कोई दोबारा पैंशन न ले सके । हर व्यक्ति का रिकार्ड अब बैंक में रहेगा । उंगलियों के निशान और फेस के फोटो लिए जाएंगें । यह अगला स्टैप हमारी सरकार माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में लेने जा रही है । सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत सभी को मान सम्मान दिया जा रहा है। हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे सही लामपात्र हैं उनको इसका लाभ मिलें और जो अपात्र हैं उनका नाम सूची से कट जाए । इसके इलावा सभी पैंशनर्स के फिंगर प्रिंट और फोटो लेने के बाद हमारी वैबसाइट पर अगली सूची डाल दी जाएगी । यह सूची फोटोयुक्त डाली जाएगी ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम की पैंशन न ले सके । जिला वाईज जो हमारे जिला कल्याण अधिकारी हैं वे समय-समय पर सूची अपडेट करते रहेंगें । डैथ केसिज में नाम कटेगा और जो नए नाम ऐड होगें, उनको ऐड भी किया जाएगा ।

Mr.Speaker : Five supplementaries have already been asked and this is the last one that can be asked.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओल्ड एज पैंशन के बारे में कहना चाहूंगा कि बुढ़ापा 60 साल का भी वही है, 65 साल का भी वही है और 70 साल का भी वही है । जो 10 सालों से पैंशन ले रहे होगें उनकी पैंशन 700 रुपये होगी । इस प्रोसैस में सबसे ज्यादा अनियमितताएं हैं । अध्यक्ष महोदय, आप भी गांव में जाते हैं, हम भी शहरों में जाते हैं । इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि किसी के पास 10 सालों की रसीद नहीं मिलती और किसी का नाम सूची में से कट गया होता है । क्या मंत्री जी इस पैंशन का स्लैब एक ही करेंगें और सभी को 700 रुपये पैंशन देने का प्रावधान करेंगें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अभी हमारे किसी सदस्य को कह रही थीं कि उनके नाम दिए जाएं जो गलत जुड़ गए हैं और उनसे ब्याज सहित वापिस लिया जाएगा । जिनके नाम रह गए हैं क्या उनको भी ब्याज समेत पैंशन देने का काम करेंगें ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि पैंशन बनाने की टीम जब गांव में जाती है उस समय जो भी व्यक्ति उस टीम के समक्ष पेश होता है . . . . .

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे मंत्री महोदया से दो ही सवाल हैं कि ये पैंशन का स्लैब एक ही करके सबको 700 रुपये पैंशन देने का प्रावधान करेंगें तथा दूसरा जिनके नाम रह गए हैं क्या उनको ब्याज समेत पैंशन दी जाएगी ?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि 1 मार्च, 1999 को जिस किसी को दस साल बुढ़ापा पैंशन लेते हुए हो गये हैं उनको पैंशन 700 रुपये प्रति माह दी जायेगी । अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि 60 साल के बुजर्ग में, 70 साल के बुजर्ग में, 80 साल के बुजर्ग में, 90 साल के बुजर्ग में और 100 साल के बुजर्ग में वाकई में अंतर होता है । उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी मैडीकल और दूसरी चीजों की जरूरत बढ़ जाती है । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिनको दस साल पैंशन लेते हो गये उनको 700 रुपये प्रति माह बुढ़ापा पैंशन दी जायेगी । अध्यक्ष महोदय, अब जहां 500 रुपये बुढ़ापा पैंशन दी जा रही है यह मई महीने से 550 रुपये प्रति माह हो जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion on Governor's Address will resume. Since, lot of members would like to participate in this discussion, the time limit of 10 minutes is fixed to speak.

श्रीमती सावित्री जिंदल (हिसार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले महिला दिवस पर मैं सबको बधाई देती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करती हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण में कहे गये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और ऐसे मुद्दे उठाना चाहूंगी जो हरियाणा के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं । हरियाणा में इस दशक में खाद्यान उत्पादन लगभग स्थिर ही रहा है इसलिए दूसरी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता है । वैसे तो कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग गठित किया गया है जो राज्य में मुख्य कृषि पद्धतियों की उत्पादकता आदि के बारे में अपने सुझाव देगा। यह आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी उपाय सुझाएगा । सरकार ने खाद्यान उत्पादन बढ़ाने के लिए 30 सोयल टेस्टिंग की मुफ्त सुविधाएं किसानों को मुहैया कराई हैं । इस वर्ष में पांच ऐसी प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा 4 नई प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं । किसानों के घर-द्वार पर ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3 नई मोबाइल सोयल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है । **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।)** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि सरकार के द्वारा की जा रही इन कोशिशों से हरियाणा में खाद्यान उत्पादन में आशा से बढ़कर वृद्धि होगी तथा हरियाणा देश में अनाज पैदा करने वाला प्रथम राज्य बनेगा । इंडो-इजराइल परियोजना के अंतर्गत

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]

फूलों के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एक केंद्र स्थापित करने के लिए और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तथा हिसार में ही डी.एन.ए. टेस्टिंग तथा निदान सुविधा केंद्र के निर्माण की योजना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह गर्व का विषय है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां अनुसूचित जातियों के परिवारों के दुधारू पशुओं का बीमा मुफ्त में किया जा रहा है ।

हरियाणा में गऊ सेवा आयोग गठित कर सरकार ने देश को एक संदेश दिया है कि दुधारू पशुओं की उचित देख-रेख के लिए वह अत्यंत प्रयत्नशील हैं । हरियाणा में वर्ष 2010 में फसलें खराब होने पर किसानों को राहत के रूप में 257.60 करोड़ रुपये दिए गए हैं मगर अभी भी अनेक व्यक्ति जिनके मकानों आदि को क्षति पहुंची थी इस लाभ से वंचित रह गए हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तथ्यों की जानकारी लेकर इन लोगों को भी उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सिंचाई के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह भी अत्यंत सराहनीय हैं । इस वर्ष में कौशल्या डैम, शाहबाद-दादूपुर नलवी नहर के पूरा होने पर इस इलाके में अनाज की भरपूर फसल ही नहीं होगी बल्कि इससे भूमिगत जल का पुनर्भरण भी होगा । इसके साथ ही सभी परियोजनाओं में जल संरक्षण उपाय लागू करने, वर्षा जल संग्रहण और पानी की पुन: रिसाईक्लिंग करने तथा राज्य के मुख्य जलाशयों के जीर्णोद्धार आदि से हरियाणा में भू-जल का स्तर बढ़ जाएगा जो पैदावार बढ़ाने में सहायक होगा । डिप्टी स्पीकर सर, इसी प्रकार से पावर प्लांट, खेदड (हिसार) में विद्युत उत्पादन शुरू होने के बाद झज्जर में दिल्ली सरकार और एन.टी.पी.सी. के सहयोग से 1500 मैगावाट की सुपर थर्मल पॉवर परियोजना लगाई जा रही है, उसका मैं स्वागत करती हूं तथा हरियाणा सरकार को बधाई देती हूं कि इस इकाई के चालू होने से हरियाणा व उसके आस-पास के इलाकों की बिजली की समस्या दूर हो जायेगी । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सभी विद्युत परियोजनाओं में बेहतरीन प्रगति हो रही है । बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सौर उर्जा परियोजनाएं भी स्थापित की जाएं तथा जिस प्रकार से भारत सरकार की सहायता से जिला सिरसा के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाई गई हैं उसी प्रकार से दूसरे जिलों में भी और विशेष तौर पर हिसार में भी ऐसी ही व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए । इसके साथ-साथ वर्ष 2009-10 के दौरान उर्जा बचत उपायों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को जो पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं । इसी प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 2,366,913 परिवारों में से अभी तक 1.77 लाख परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली के कनैक्शन दिये जा चुके हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाकी के परिवारों को भी जल्दी से जल्दी बिजली कनैक्शन दिये जायें जिससे वे लोग भी अपना जीवन निर्वाह सुविधापूर्वक कर सकें। अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगी । सर, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2017 तक शत-प्रतिशत दाखिले और वर्ष 2020 तक छात्रों

का बीच में ही पढ़ाई न छोड़ना भी सुनिश्चित करना सरकार द्वारा उठाया गया अत्यंत सराहनीय कदम है । इससे निश्चित रूप से जन-साधारण के रहन-सहन में और जीवनयापन के ढंग में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आयेगा । मगर मैं यह कहना अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता तथा बच्चों के लिये दिये जा रहे मिड-डे मील की गुणवत्ता को भी सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त यहां यह जिक्र करना भी बेहद जरूरी है कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमण्डल खेलों और चीन में आयोजित एशियाई खेलों में हरियाणा राज्य के जिन खिलाड़ियों ने पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है वे सब बधाई के पात्र है । राज्य में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बेची गई शराब की बोतल पर 50 पैसे आबंटित करने का जो निर्णय लिया गया है यह भी एक अत्यन्त प्रशंसनीय कदम है । मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि खेलों को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित खेल स्टेडियम हर जिले में बनाये जायें । इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को दी गई हैं, वह पूर्ण रूप से सराहनीय हैं । मगर मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मेरा यह मानना है कि इनमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है और प्रदेश का एक वर्ग इन सेवाओं का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहा है । हालांकि करनाल, मेवात में नल्हड़ और सोनीपत में खानपुर कलां में तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित होने से इस दिशा में कुछ सुधार होने की आशा है । मेरा सुझाव है कि सभी डिसपैंसरीज़ और अस्पतालों में सभी रिक्त पदों, विशेषकर डॉक्टरों के पदों को, सर्वोच्च वरीयता के आधार पर भरा जाए। सरकार का महिलाओं के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन स्थापित करने का जो प्रस्ताव है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं । अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे अनेक परिवारों को बहुत राहत मिली है। बी.पी.एल. योजना के अंतर्गत बनाई गई लिस्ट अभी अधूरी है। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि जो परिवार इस सूची में आने से रह गए हैं, उन्हें भी बी.पी.एल. लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि वे भी सरकार की नीतियों का लाभ उठा सकें । मेरा सरकार को एक सुझाव यह भी है कि बी.पी.एल. लिस्ट का फिर से निरीक्षण किया जाए ताकि जो परिवार वास्तव में इन सुविधाओं के अधिकारी हैं वे ही इसका लाभ उठा सकें। आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम आय वर्गों के लिए सुलभ आवास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें अभी और ध्यान देने की जरूरत है । हरियाणा में दिन-प्रतिदिन लिंगानुपात में बढ़ता हुआ अंतर एक अत्यन्त चिंता का विषय है । यह केवल आधिकारिक प्रयासों द्वारा ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए सामाजिक स्तर पर जनता के सहयोग की भी अत्यन्त आवश्यकता है। इस सदन के माध्यम से मैं हरियाणा की जनता से यह प्रार्थना करती हूं कि अपना सहयोग देकर कोई ऐसी स्थिति बनाएं जिससे आगे से कोई भी भ्रूण हत्या न हो । डिप्टी स्पीकर सर, मैं अत्यन्त विश्वास के साथ कह सकती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा आने वाले वर्षों में हर क्षेत्र में नये आयाम हासिल करेगा । इन शब्दों के साथ ही मैं अपना व्यक्तव्य समाप्त करती हूं । अन्त में, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन करती

[श्रीमती सावित्री जिन्दल]
हूं व विपक्ष से भी अनुरोध करती हूं कि वह सरकार द्वारा लाये गये इस धन्यवाद प्रस्ताव का एक मत से पूर्ण समर्थन करें । धन्यवाद ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, 04 मार्च, 2011 को दिये गये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । महामहिम के अभिभाषण पर प्रस्तावक के रूप में माननीय सदस्य श्री विनोद शर्मा जी ने और अनुमोदक के रूप में माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी ने सरकार का बहुत-बहुत गुणगान किया और मैं समझता हूं कि उन्हें सरकार का गुणगान करना भी चाहिए था । हरियाणा की तरक्की और प्रगति के लिए जो सुझाव उनकी तरफ से आने चाहिएं थे और जहां-जहां सरकार की कमजोरियां हैं, उनकी तरफ भी वे सरकार का ध्यान दिलाते तो बेहतर होता लेकिन यह उनकी मजबूरी हो सकती है या लाचारी हो सकती है लेकिन जो काम उन्होंने नहीं किया वह काम हम शुरू करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, धरती, धानी और धरोहर ये किसी भी सभ्य समाज की प्रगति के प्रतीक होते हैं लेकिन आज तीनों का हरियाणा में अपमान हो रहा है । यह मेरा कहना नहीं है यह योजना आयोग की जो रिपोर्ट है यह उसका कहना है । योजना आयोग ने जो हरियाणा का ध्यान आकर्षित किया है, उनका कहना है । ट्रैजरी बैंचिज पर बैठे हुए मेरे साथी सरकार का नम्बर एक का गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं । क्या उन्होंने कभी उन क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दिया है जहाँ हरियाणा नम्बर एक के आसपास भी नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूँ कि कमजोर धरती, कमजोर जननी और कमजोर शिशु जहाँ हों फिर कैसा हरियाणा नम्बर वन। इन तीनों के बारे में तो आँकड़े कुछ और कह रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में भूमि की उर्वरता लगातार घट रही है । धरती का पानी लगातार 0.33 फीसदी यानि कि एक फुट प्रति वर्ष नीचे जा रहा है जिसके कारण जो हमारी परम्परागत फसलें हैं जैसे गेहूं, जीरी और गन्ना, उस पर पानी की उपलब्धता घट रही है । स्त्री-पुरुष लिंगानुपात लगातार घट रहा है और हरियाणा की तरक्की का आंकलन आप खुद करें। योजना आयोग की रिपोर्ट जो दर्शाती है उसमें आप देखेंगे कि हरियाणा कहाँ खड़ा है ? मैं अपने दोस्तों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे भी यह रिपोर्ट लेकर पढ़ लें। जो शिशु मृत्यु दर है इसकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वह 1000 पर 53 है और हरियाणा में यह दर 54 है । इस मामले में हरियाणा बॉटम से यानि कि नीचे से 9वें नम्बर पर है । इसी तरह से जो मातृत्व मृत्यु दर है जो पहले 162 थी इस सरकार के रहते हुए वह यथास्थिति भी नहीं रही और वह बढ़कर 186 हो गई है । यानि बॉटम से 10वें नम्बर पर हरियाणा खड़ा है । इसी तरह से जो शिशु कुपोषण है जहाँ पहले 34.6 प्रतिशत था वह आज बढ़कर 38.2 प्रतिशत हो गया है, यानि हरियाणा नीचे से 10वें नम्बर पर है । इसी तरह से रक्त अल्पता की बात की जाये तो ऑल इंडिया रैंक 55.3 प्रतिशत है लेकिन हरियाणा में वह 56.1 प्रतिशत है और यहाँ भी हरियाणा नीचे से 10वें नम्बर पर खड़ा है । यह योजना आयोग ने बताया है । यह मेरा कहना नहीं है । इसी तरह से लिंगानुपात जो 816 था, वह आज भी वहीं पर खड़ा है । जिसकी वजह से हरियाणा के कुंवारे आज केरल, असम और पश्चिम बंगाल से दुल्हनें ला रहे हैं ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती अनिता यादव) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष

होने के नाते इस बारे में कितना ध्यान दिया है ?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार को जगाता रहता हूं, सरकार को सजग करता रहता हूं । सरकार को ही ये काम करने चाहिएं । हमारा काम तो सरकार को जगाते रहना है । उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से शिक्षा का खूब ढिंढौरा पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए उनको जमीनें दी गयी हैं लेकिन शिक्षा के स्तर में जितना गैप है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । नेशनल लेवल पर यह गैप 22.8 परसैंट का है जबकि हरियाणा में यह गैप 20.2 परसैंट है। यहां पर हरियाणा आठवें नम्बर पर खड़ा है । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुड़गांव से 22 मिनट्स की दूरी पर ही मेवात है । गुड़गांव तो साईबर सिटी है लेकिन गुड़गांव की बगल में ही मेवात में आज भी पचास फीसदी बालिकाएं प्राईमरी स्कूल नहीं जा पाती हैं , फिर हम किस विकास की बात कर रहे हैं, किस उन्नति की बात कर रहे हैं ? एक तरफ गुड़गांव और दूसरी तरफ मेवात । इसी तरह से शिक्षा में जो जैंडर गैप है वह भी बहुत खराब है । महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, नारनौल और रिवाड़ी में सिर्फ तीस परसैंट महिलाएं ही शिक्षा ग्रहण कर रही हैं । वहां पर पुरुष भी तीस परसैंट ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । फिर विकास किसका हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है ? आज पिछड़े पिछड़ते जा रहे हैं और आर्थिक एवं सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है । मेवात, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और गुड़गांव शैक्षणिक असमानता के शिकार हैं । आज भी पूरे मेवात में साक्षरता का स्तर 44.9 परसैंट है। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं और सीवरेज आदि की व्यवस्था भी वहां पर न के बराबर है । फिर कैसे होगा हरियाणा नम्बर वन ? (विघ्न) मैं तो सुझाव दे रहा हूं आप सुन लें आपके काम आएंगे । उपाध्यक्ष महोदय, जो महामहिम जी ने कहा है मैं तो उसके बारे में ही सरकार को सुझाव दे रहा हूं । अगर सरकार को अच्छे लगें तो मान लें और अगर अच्छे न लगें तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दें। मैं तो हरियाणा की जनता की भलाई के लिए कह रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विकास की आज बात की जा रही है । 5 मार्च, 2004 को जब हरियाणा की यह सरकार बनी तो उस समय हरियाणा पर कर्जा लगभग 26 हजार करोड़ रुपये था लेकिन आज यह कर्जा बढ़कर 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है। हमारे काबिल वित्त मंत्री जी ने भी यह बात मानी है । अमर उजाला अखबार में 25 फरवरी को छपा है कि हरियाणा का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है । क्यों ? अपने रिसोर्सिज कहां गए ? उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मुझे आज हरियाणा किसी भी क्षेत्र में नम्बर वन नजर नहीं आता । भूमि अधिग्रहण नीति के बारे में मैं समझता हूं कि कई घंटे इस पर हाउस में चर्चा होनी चाहिए थी । भूमि अधिग्रहण नीति के बारे में आज बड़ा ढोल पीटा जा रहा है । यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि वास्तव में आज हरियाणा का किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है । (विघ्न) आप सुन लें, ये आपके फायदे की ही बात है । यहां पर ज्यादातर किसानों के बेटे और बेटियां बैठे हुए हैं । अगर किसानों के दुख दर्द को यहां पर नहीं कहा जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारा विधान सभा में चुनकर आने का जो मकसद है वह गौण हो जाएगा । मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप भी नहीं लगा रहा हूं, कोई घोटाले या भ्रष्टाचार की बात भी नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है और भी काफी सारे मैम्बर्ज ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात कहनी है इसलिए आप जल्दी कंक्लूड कीजिए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण को लेकर हरियाणा प्रदेश के किसानों में असंतोष है। जिलों में जो प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं। ये असंतोष किसानों में ही नहीं है, विपक्ष के लोगों में ही नहीं है अपितु उधर बैठे लोगों में भी है और इसलिए कभी वे चिट्ठी लिखते हैं कभी अखबारों के माध्यम से कहते हैं, कभी टी.वी. पर बोलते हैं । वे कहते हैं कि हम सुझाव दे रहे हैं, अंतर्विरोध तो कहीं भी नहीं है । मेरे काबिल मंत्री सुरजेवाला जी बैठे हैं । ये भी खुद भी चाहते हैं कि अच्छे सुझाव सरकार को दिये जाएं । हमारा ये सुझाव है कि उस जमीन अधिग्रहण में किसानों की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए ।

श्री नरेश कुमार बादली : उपाध्यक्ष महोदय, इनका टाइम पूरा हो गया है। हमको भी बोलना है ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी सुझाव है कि भूमि अधिग्रहण करते समय उसमें किसान की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए ।

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुर्जर साहब से पूछना चाहता हूं कि छह साल तक इनकी गठबंधन सरकार चली, उस समय इन्होंने कितनी हिस्सेदारी दी थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में मुझे भी बोलने का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कंक्लूड गुर्जर साहब।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि हमारे साथ लगती मोहाली है । मोहाली की जमीन का पंजाब की सरकार ने मुआवजा रेट 1.5 करोड़ रुपये तय कर दिया है और इधर हमारा पंचकूला भी किसी भी मामले में मोहाली से कम नहीं है उसके बारे में मंत्री जी जवाब में बता रहे थे कि हमने उसका मुआवजा रेट 30 लाख रुपये तय किया है ।

आवाजें : 42 लाख रुपये किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : उपाध्यक्ष महोदय, हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब इनकी सांझा सरकार थी, तब ये कितना मुआवजा देते थे । गुड़गांव में ये केसिनो बनाना चाहते थे, दुनियां के जुए का सबसे बड़ा अड्डा गुड़गांव में बनाना चाहते थे लेकिन हमारे गरिमा युक्त एम.पी. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से आज यहां दुनिया का सबसे बड़ा आल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडीकल बनने जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब भी बोलता हूं, तथ्यों के आधार पर ही बोलता हूं। तथ्यों के बगैर मैं नहीं बोलता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया है आप एक मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : किसानों की जो अनदेखी आज हो रही है इस बारे में मैंने सप्लीमैंट्री में भी पूछा था । कलैक्टर रेट 55 लाख है जमीनें 42 लाख रुपये में जाती हैं, तीन करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये प्राइवेट बिल्डर ले रहे हैं और वहां ये 30 लाख या 42 लाख रुपये दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये बातें आप पहले ही बोल चुके हैं । कृप्या रिपीटीशन न करें। आपका समय समाप्त हो गया है। आप कृप्या बैठ जाएं ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

13.00 बजे **श्री अनिता यादव :** उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 से 2004 तक इनकी सरकार के समय में इन्होंने किसानों को भूमि अधिग्रहण का कितना पैसा दिया । कितने-कितने जमीन के रेट इन्होंने दिए यह आपके सामने हैं । ये कहीं तो कैसीनों खोलना चाहते थे । किसानों को डेढ़ लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आप देते थे और आज किसानों की भूमि के क्या भाव हैं और साढे छः साल पहले आपने किसानो को क्या भाव दिए । फिर ये क्यों चले गये थे यह बता दें ।

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी श्री कृष्णपाल गुर्जर जो इनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पार्टी का नेता होने के कारण इनको कुछ न कुछ तो कहना भी चाहिए । इन्होंने एक बात कही की मंत्री शायद बैठे नहीं हैं इस बात का जिक्र किया । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** इन्होंने यह भी कहा कि पब्लिक में, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में सब में चिन्ता का विषय है, सब में रिजैंटमेंट है इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया । मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूं । 9 साल का समय आप लोगों के पास रहा । 9 साल में किसानों के लिए कितना कुछ किया या भूमि अधिग्रहण पॉलिसी आपकी क्या थी उसका मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता । मुझे अच्छी तरह से याद है जब श्री गुर्जर जी ट्रान्सपोर्ट मंत्री थे उस समय पब्लिक रिलेशन की विज्ञप्ति स्टेट लैवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये अनाऊंस करते थे उस समय का मुझे याद है कि बसें पांच रुपये प्रति माह कमाती थीं नहीं तो घाटे ही घाटे में जाती थी । (विघ्न) जो क्यू शैल्टर जिन पर करोड़ों रूपये खर्च हुए आज वे पिगरी फार्म की तरह पड़े हैं उनमें गधे खड़े हैं, टूटे पड़े हैं उनकी जांच कराने वाला कोई नहीं है । (विघ्न) यह उस समय जांच इनकी सरकार द्वारा करनी चाहिए थी यह आपने करनी चाहिए थी । तीसरी बात मैं भूमि अधिग्रहण पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है। (विघ्न) देखिए यह तो आपको खुशी होनी चाहिए कि पार्टी के अन्दर चाहे सत्ता में हैं या विपक्ष में प्रजातंत्र में हम पारदर्शिता की बात कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण पॉलिसी बनाई है वह अपने आप में एक मिसाल है । हमने जो कुछ कहा है वह सुझाव दिए हैं कोई रिजैंटमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम डैफरिंग पॉलिसी देश में पहली बार लाये हैं और उसमें जो सुधार करने हैं उन पर भी हम सुधार कर रहे हैं जो जनहित में होगा हम उनको लागू करेंगे । उस पर भी सरकार विचार कर रही है । (विघ्न)

Mr. Speaker : Madam Kavita, you do not want to speak. (Interruption)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलने दें । मैं असली सुझाव दे रहा हूँ ।

Mr. Speaker : Kindly bear with me. Many young members want to speak. I have the list given by your party and I want Madam Kavita Jain to speak.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, अभी सर्राफ साहब ने बोलना है ।

Mr. Speaker : Kavita ji, please speak in two minutes.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बताया जाए कि कौन सी लिस्ट दी है ।

Mr. Speaker : I have a list. Let her proceed to speak.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मैं तो किसानों के बारे में कह रहा था । मेरे सत्ता पक्ष के भाइयों को मेरी बात अच्छी न लगती हो तो मैं बोलना बन्द कर देता हूं। ये यहां कुछ कहते हैं और चिट्ठियों में कुछ लिखते हैं । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । ग्रामीण विकास की यहां खूब चर्चा हुई । अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च, 2005 को यह सरकार बनी उस समय जो बी.पी.एल. परिवार थे वे आज भी वहीं पर खड़े हैं । विकास किसका हो रहा है । पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है । 2009 के सर्वे के अनुसार यदि आप ध्यान देंगें तो अर्बन एरियाज में कुल 19.02 लाख परिवार हैं जिनमें से बी.पी.एल. परिवार 5.7 लाख हैं यानि 25 परसैंट से ज्यादा बी.पी.एल. परिवार आज शहरों में रहते हैं । इसी तरह रूरल एरियाज में 31.58 लाख परिवार हैं लेकिन वहां भी बी.पी.एल. परिवार 8.58 लाख हैं यानि वहां पर भी 25 परसैंट से ज्यादा आज बी.पी.एल. परिवार हैं । तब से लेकर आज तक गरीब आदमी वहीं खड़ा है तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 6 सालों से विकास किसका हुआ । जिसका विकास होना चाहिए था उसका विकास नहीं हुआ । 100-100 गज के प्लाट देने की बात यहां की गई । कितनी पंचायतों और कितने बी.पी.एल. परिवारों को ये प्लाट दिए गए । जहां पंचायतों के पास जमीन नहीं है वहां सरकार उन बी.पी.एल. परिवारों के लिए क्या अल्टरनेट निकाल रही है । शहरों में 25 परसैंट से ज्यादा बी.पी.एल. परिवार हैं । एक भी परिवार को आज तक 100 गज का प्लाट नहीं मिला । उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? यह तो बिजली के बिलों की माफी की तरह हुआ। (शोर एवं व्यवधान) सरकार ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए थे। शहरों में 25 परसैंट से ज्यादा बी.पी.एल. परिवारों को बिजली माफी का कोई लाभ नहीं हुआ । इसी तरह आज शहर में भी रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों को 100-100 गज के प्लाट का कोई फायदा नहीं हो रहा । बिजली के बिलों के जो 1600 करोड़ रुपये माफ किए गए थे आज वे बढ़कर कितने हो गए हैं? आज वे बढ़कर 3200 करोड़ के करीब हो गए हैं ।

Mr. Speaker : I want one of your members to speak. So, your time is over. Please sit down.

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । अभी गुर्जर जी ने बिजली के बिलों की माफी के बारे में कहा तो मैं इनसे कहना चाहूंगी कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किए । इससे पहले जब इनकी सरकार लगातार 5 साल से थी तो इन्होंने क्या क्या किया और कितना कितना किया। ये इस बारे में आंकड़े बता दें कि इन्होंने क्या किया और जो हमने किया वे भी ये बता दें । दूसरी बात इन्होंने कितने पावर प्लांटस लगाए और हमने कितने लगाए, इन्होंने कितना फायदा लोगों को दिया और हमारी सरकार ने कितना फायदा किया, ये इस बारे में भी बता दें ।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : He is not supposed to answer any question that you raise. Krishan Pal ji, I requested you to please wind up in two minutes but you have already used almost 6 minutes.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे 10 मिनट का समय और दे दो । मैं अच्छे सुझाव दे रहा हूं ।

Mr.Speaker : I want to hear members of your party who have not spoken as yet. अब कविता जी सोनीपत के बारे में बोलना चाह रही हैं।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, वे भी बोलेंगी । हमने आपको बहुत उम्मीदों के साथ सर्वसम्मति के साथ यहां बिठाया था । मैं अच्छे सुझाव दे रहा हूं । मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा ।

Mr. Speaker : I know that you are a wonderful speaker. So, you will wind up in two minutes only. (Interruption)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अभी बहन अनीता जी ने, अपने ऑनरेबल मिनिस्टर ने, अपने ऑनरेबल भाई नरेश जी ने कहा (विघ्न) मैं तो यही कहूंगा क्योंकि हमारा आदरणीय सदस्य है । इनको गुस्सा आ जाता है लेकिन हमको गुस्सा नहीं आएगा ।

Mr. Speaker : You are a happy man, I know.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमारे राज में जमीनें कैसे ऐक्वायर हुई और कैसे अर्जित की गई इस बारे में इन्होंने जिक्र किया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ईमानदारी के साथ रिकार्ड मंगवाकर देख लें कि जब हम सहयोगी सरकार के साथ थे उस समय तमाम जिलों में कलैक्टर रेट भी होंगे, रजिस्ट्रियां भी हुई होंगी इसलिए उस समय की रजिस्ट्रियां निकाल लें और ओपन मार्केट रेट निकाल लें तथा आज के भी निकाल लें फिर जो बात होगी उसको सब मान लेंगे (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, उस समय किसान 5 लाख रुपये मुआवजा लेकर भी खुश होते थे और आज दो करोड़ रुपये लेकर भी खुश नहीं हैं यह रिकार्ड की बात है ।

Mr. Speaker : Please Mr. Gurjar wind up.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं। मैं कोई घोटालों की और भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान) मैं तो साफ-साफ कह रहा हूं ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । इन्होंने मेरा नाम लिया है । मेरे काबिल दोस्त ने मुझे गुस्से में बताया है । मै इनको बताना चाहूंगा कि यह मेरा गुस्सा नहीं है बल्कि ऐसे बोलने की तो मेरी आदत है । सम्मानित साथी मेरे बड़े भाई हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि ये ईमानदारी का ढिंढौरा पीट रहे हैं लेकिन जिस समय ये सत्तासीन होना चाहते थे उस समय गली-गली और गांव-गांव जाकर ये झूठ बोलते थे कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे और न मीटर होगा, न मीटर रीडर होगा । इनकी सरकार बनी और लोगों ने जब वह बात याद दिलाई तो इन्होंने कण्डेला के अंदर किसानों पर क्या जुर्म किया इस बारे में ये ईमानदारी से बतायें । इन्होंने कण्डेला में जो जुर्म किसानों पर किया ऐसा हिन्दुस्तान में किसानों पर कहीं नहीं हुआ और आज ये ईमानदारी का ढिंढौरा पीट रहे हैं । इनको तो शर्म नहीं आती । अध्यक्ष महोदय, गुर्जर साहब मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं । (हंसी)

Mr. Speaker : Everybody respect seniors.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं । मैं तो यह इसलिए कह रहा हूं कि सदन में ज्यादातर किसानों के बेटे बैठे हैं और सबको किसानों के हित की बात पर सर्वसम्मति से समर्थन करना चाहिए । अगर कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे सुझाव देने की बात कही थी इसलिए मैं अच्छे सुझाव दे रहा हूं । अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मैं सुझाव न दूं तो बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमने तो सदा कहा है कि अच्छे सुझाव दो लेकिन ये सच्चाई के साथ बतायें कि जिस समय इनके सहयोगियों की सरकार थी और हम विपक्ष में बैठते थे क्या उस समय इनको कभी बोलने दिया गया। ये सच्चाई बता दें । (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उस समय मुख्यमंत्री जी ने अपने समय में से मुझे समय दिलवाया था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने समय में से समय दिलवाता था और अपना समय कटवाता था । (हंसी)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पूरा समय दिया जाता था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये तो उस समय सदन के मैंबर ही नहीं थे, इनको नहीं मालूम ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ... (विघ्न)

Mr. Speaker : The Hon'ble Chief Minister wants to give his reply at 2.00 P.M and the House will adjourn at 2.30 P.M. Lot of members would like to speak. So, you may please wind up.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उस समय का रिकार्ड उठवाकर देख लें जब ये बोलते थे तो हमारा कोई भी मैंबर डिस्टर्ब नहीं करता था ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उस समय हमें पांच मिनट से ज्यादा स्पीकर महोदय नहीं बोलने देते थे । मैं तो अनुशासन को मानने वाला आदमी हूं जब वे कहते बैठ जा भाई टाईम नहीं देता, मैं बैठ जाता था। उस समय के मुख्यमंत्री स्पीकर को इशारा कर देते और स्पीकर हमें बैठने के लिए कह देता था। रिकार्ड का सबको मालूम है । कृष्ण पाल जी को भी पता है ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब भी ये बोले उस वक्त किसी ने इनको नहीं टोका ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने याद दिलाया कि उस समय ये अपने समय में से मुझे समय दिलवाते थे । मैं आज भी इनका आभारी रहूंगा यदि ये अपने समय में से कुछ समय मुझे दे दें ।

Mr. Speaker : Mr. Gurjar, please conclude.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ सुझाव ही दूंगा । कोई गलत बात नहीं कहूंगा । जहां-2 कमियां हैं वहां सरकार का ध्यान दिलाऊंगा ।

Mr.Speaker : Now, I must invite the next speaker, Ghanshyam Saraf.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा । अब मैं कानून व्यवस्था का जिक्र करना चाहूंगा । कानून और व्यवस्था का हरियाणा में क्या हाल है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज अपराध और अपराधी दोनों बढ़े हैं। अपराधियों के मन से कानून का भय समाप्त हो गया है। गुड़गांव और फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नरी बनाई गई । वहां ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया जिस पर ज्यादा पैसे भी खर्च हुए । एक-एक आई.पी.एस. की जगह वहां पर 5-5 और 6-6 आई.पी.एस. लगाये गये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इतना खर्च बढ़ जाने के बावजूद भी क्या वहां पर अपराध कम हुए हैं । नहीं, अपराध कम नहीं हुए हैं बल्कि अपराध और भी बढ़े हैं । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ये रिपोर्ट कह रही है । आप देखिए वर्ष 2006-07 में जहां गुड़गांव में पुलिस कमिश्नरी पर जो खर्चा था वह 31,78,44,076/- रुपये था जो कि वर्ष 2009-10 में बढ़कर 97,99,67,298/- रुपये हो गया । ये आंकड़े सरकार द्वारा दिये हुए हैं इसलिए ये गलत नहीं हो सकते । सिर्फ यह खर्चा बढ़ा ऐसी बात नहीं है इसके साथ-साथ क्राईम भी बढ़े । आप देखिए वहां पर क्राईम भी किस तरह से बढ़े हैं । वर्ष 2005 में 4750 मुकदमें दर्ज़ हुए थे जो वर्ष 2006 में बढ़कर 6205 हो गये । इसके साथ ही सम्पत्ति के खिलाफ भी अपराध बढ़े । जहां वर्ष 2005 में सम्पत्ति से सम्बंधित 1993 मुकदमें दर्ज़ हुए वहां वर्ष 2006 में यह संख्या बढ़कर 2827 हो गई । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना खर्च बढ़ जाने के बाद भी क्राईम रेट रुका नहीं अपितु लगातार बढ़ता रहा ।

Mr. Speaker : That means more offences are being registered. That is good. May be no reporting in time, it is a report.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : इसी प्रकार से जहां वर्ष 2007 में 2090 मुकदमें दर्ज़ हुए वहीं वर्ष 2008 में बढ़कर 2472 हो गये । मेरे कहने का यह मतलब है कि अपराध और अपराधी दोनों ही बढ़ रहे हैं । कानून का जो भय अपराधियों के मन में होना चाहिए वह हर हालत में रहना ही चाहिए। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बहुत सैंसटिव हैं । वे सज्जन भी है । उनकी ताकत का भी यही कारण है कि वे नैगेटिव नहीं हैं और बदले की भावना भी उनमें नहीं है लेकिन इसका बुरा प्रभाव यह भी हो रहा है कि अपराध और अपराधी दोनों बढ़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से अवैध कालोनियों के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार वर्ष 2005 से लेकर इस बारे में लगातार सिर्फ सोच रही, सोच रही है और इस प्रकार से मौजूदा सरकार के पिछले 5 साल सिर्फ सोचने में ही निकल गये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, माननीय साथी ने जो मामला उठाया है यह बहुत ही सैंसटिव है इसमें कोई दो राय नहीं । मैं इस बारे में माननीय सदस्य और पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि शुरू में यह मामला कोर्ट के अधीन था जिस वजह से इसमें डिले हुआ । अब सरकार इस बारे में फैसला कर चुकी है और सभी कालोनियों की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जो कालोनियां निर्धारित पैरामीटर्ज़ को पूरा करेंगी हम उनको रैगुलराइज करेंगे ।

Mr. Speaker : Mr. Gurjar, many Members want to speak from the opposition benches. So, please wind up.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने एग्जामिन करने में ही 6 साल निकाल दिये । जब वर्ष 2009 में मौजूदा सरकार सत्तासीन हुई उस समय यह कहा गया था कि तीन महीने के अन्दर सरकार अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत कर देगी । अब तो मौजूदा सरकार को सत्तासीन हुए डेढ़ साल हो गया है । मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश की अनाधिकृत कालोनियों को अधिकृत करने में और कितना समय लगेगा क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो जाये कि जैसे पिछले पांच साल निकल गये वैसे ही ये पांच साल भी न निकल जायें । ऐसा न होने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनके अगली बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने से पहले-पहले यह काम हर हाल में हो जायेगा।

Mr. Speaker : Now, next Member Mr. Ghanshyam will speak.

श्री घनश्याम सर्राफ (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से भिवानी क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में बतलाना चाहता हूँ । सबसे बड़ी समस्या पेयजल आपूर्ति की है। भिवानी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की बहुत कमी है । शहरों में गंदे पानी की पाईप ताजा पानी की पाईप के साथ मिल जाती हैं और लोगों के घरों में गंदा पानी जाता है । दूसरी बात

यह है कि लाईनें छोटी पड़ गई हैं और पानी के कनैकशनों का लोढ़ बढ़ गया है इसलिए मेरा अनुरोध है कि लाईनों को बड़ा किया जाये । गांवों में पीने के पानी के लिए पिछले बजट सत्र में माननीय मंत्री जी को 3 गांवों फूलपुरा, बामला और नौरंगाबाद की समस्या लिखवाई थी और उन तीनों गांवों में मार्च तक पेयजल पूरा करने के लिए कहा गया था लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । हालाँकि यह समस्या 14 गाँवों की है जहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है लेकिन अभी तक उन तीन गांवों में ही कुछ कार्य नहीं हुआ है । इसी तरह से सीवरेज की समस्या भी है। पूरा भिवानी शहर खास तौर से पुराना शहर सीवरेज खराब होने के कारण लबालब पानी से भरा रहता है और गलियाँ टूटी रहती हैं । वहाँ तुरन्त सुधार की आवश्यकता है । इसी तरह से सफाई की समस्या है । पहले जहाँ 1980 में भिवानी म्यूनिसिपल कमेटी में 400 सफाई कर्मचारी होते थे आज उनकी संख्या 270 रह गई है और उनमें से भी 50-80 तो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के घर पर काम करते हैं और पूरे शहर में सफाई नाम की कोई चीज नहीं रही है । आज जरूरत है कि या तो ठेके पर या नियमित कर्मचारी भर्ती करके शहरी सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाये । इसी प्रकार से शहर की म्यूनिसिपल लिमिट में बढ़ोतरी की जाये । पिछली बार जब यह बढाई गई थी, उसको बढ़ाए हुए 30 साल हो गये हैं और शहर की आबादी अब 3-4 गुणा बढ़ गई है । इस समस्या को ध्यान में रखते हुए म्यूनिसिपल लिमिट का एरिया बढ़ाया जाये । इसी प्रकार से सड़कों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा । शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बहुत खस्ता है । 1-2 सड़कें अभी 5-6 महीने पहले ही बनी थी लेकिन उनमें निर्माण सामग्री घटिया लगने के कारण वे टूट चुकी हैं तथा उनके सैम्पल फेल हो गये हैं लेकिन उनके बनाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है । आज गाँव बडाला, मानहेडू की सड़कें और ग्रामीण क्षेत्र की और भी कुछ सड़कें हैं जो कीचड़ से सनी पड़ी हैं तथा उनका कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये । अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के तार बहुत पुराने हो गये हैं तथा वे लटक गये हैं । कई जगह पर खम्बे टूट भी चुके हैं और कई जगह खम्बे गलियों के बीच में भी लगे हुये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस व्यवस्था को भी तुरन्त ठीक किया जाये क्योंकि कई बार पशु इन तारों की चपेट में आकर मर जाते हैं । ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनको ठीक करवाया जाये । इसी प्रकार से छोटे दुकानदारों पर बिजली का मिनीमम रेट चार्ज डबल कर दिया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जितना लोड वे यूज कर रहे हैं उतना ही उनसे चार्ज किया जाए । कहीं पर वे एक पंखा और कहीं पर वे एक ट्यूबलाईट जलाते हैं । शाम के समय ही वे दो या तीन घंटे लाईट का यूज करते हैं इसलिए ऐसे दुकानदारों की चैकिंग करके सरकार यह निर्णय लें तो यह ठीक रहेगा। लघु उद्योग धंधों पर चाहे उनको बिजली मिले या न मिले, 250 रुपये प्रति किलोवाट चार्ज लगाया गया है इसलिए इस बारे में भी सरकार सोच समझकर निर्णय ले तो बहुत अच्छी बात होगी । शिक्षा के क्षेत्र में भिवानी के छात्र अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। पहले जब जे.बी.टी. की परीक्षा हुई तो उसमें सबसे अधिक छात्र भिवानी के पास हुए और मुख्यमंत्री जी ने उन सभी छात्रों को नौकरी भी दे दी जो कि एक बढ़िया बात है ।

श्री अध्यक्ष : क्या आपके कहने का मतलब यह है कि भिवानी में जितने छात्र पास हुए थे उन सबको नौकरी मिल गयी है ?

श्री घनश्याम सर्राफ : जी हाँ सर। यह एक अच्छी बात है और मैं इसके लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं ।

Mr. Speaker : This is what the attitude should be. बहुत अच्छी बात है।

श्री घनश्याम सर्राफ : इसी तरह से एक उच्च तकनीकी संस्थान भी भिवानी में खोला जाना चाहिए यह मेरा सरकार से अनुरोध है क्योंकि वहां के छात्र मेधावी छात्र हैं । इसी तरह से लड़कियों के लिए स्कूल खोलने के बारे में मैंने पिछले सैशन में भी एक क्वैश्चन लगाया था लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है इसलिए सरकार को इस बारे में भी देखना चाहिए और जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए । भिवानी के खिलाड़ियों ने ओलम्पिक खेलों में, एशियाई खेलों में, राष्ट्र मंडल खेलों में और राष्ट्रीय खेलों में भी पूरे हरियाणा में यह सिद्ध करके दिखाया है कि खेल के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी सबसे श्रेष्ठ हैं । आज उन खिलाड़ियों के लिए अगर वहां पर कोई संस्थान बनें और यदि उनको अन्तर्राष्ट्रीय लैवल की ट्रेनिंग या कोचिंग मिले तो भिवानी के खिलाड़ी और भी अच्छा प्रर्दशन करने में सक्षम हो पाएंगे । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी वह अपनी दरियादिली दिखाकर भिवानी को एक संस्थान प्रदान करें । अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहना चाहता हूं । चौधरी बंसीलाल जी के नाम से वहां पर जो सामान्य अस्पताल है उसमें डॉक्टरों की बेहद कमी है । प्रसूति विभाग में वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं है और पूरे अमले को यदि देखा जाए तो उस पूरे अस्पताल में 150 कर्मचारियों के लगभग कमी है । वहां पर कैंसर रोगियों के लिए एक कोबार्ड थैरेपी की मशीन आयी थी लेकिन उसको वहां पर उतारे बगैर कहीं अन्यत्र भेज दिया गया। एक सी.टी.स्कैन की मशीन भी वहां पर लगायी जानी चाहिए ताकि गरीब आदमियों का इलाज आराम से हो पाए, इसके लिए मैं सरकार से डिमांड करता हूं । स्पीकर सर, एक और मेरे यहां पर समस्या है । भिवानी शहर, भिवानी विधान सभा क्षेत्र तथा भिवानी जिले में पिछले दिनों बहुत उद्घाटन हुए। उन उद्घाटनों के द्वारा विधायकों के बोर्ड लगाकर सरकारी तंत्र का कांग्रेसीकरण करने का काम इस सरकार ने किया है जो कि ठीक नहीं है । मेरी इस बारे में शिकायत है । जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आज के जन प्रतिनिधि हैं उनको अवसर देना चाहिए । यदि सरकार फिर भी ऐसा नहीं चाहती कि उनके नाम आए तो अपने ही किसी और मंत्री के नाम उनमें बढ़ा दें। यह बढ़िया रहेगा लेकिन जो भूतपूर्व जन प्रतिनिधि हैं उनके नाम साईनबोर्डो पर नहीं होने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : कविता जी, आप बोलिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के किस सदस्य ने बोलना है, मैं ग्रुप लीडर हूं यह मैंने तय करना है।

Mr. Speaker : I want to hear her.

Smt. Kavita Jain : Sir, Mr. Vij is leader of our party in the House. So, he will speak.

Mr. Speaker : But I want you to speak on Sonepat. I have given you permission to speak.

Smt. Kavita Jain : Sir, he will speak.

Mr. Speaker : You do not want to speak. Let it record that I called her but she did not speak.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : सर, ये बोलना चाहती हैं लेकिन ये मि. अनिल विज के बाद बोलना चाहती हैं ।

Mr. Speaker : Let it record that she does not want to speak.

Smt. Kavita Jain (Sonepat) : Sir, I want to speak on the Budget. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मैं यह भी क्लीयर करना चाहूंगी कि मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए कुछ भी स्टडी नहीं की है। इस समय जो प्वायंट्स मेरे माइंड में हैं वह मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। सर, सबसे पहले जो मेरे हल्के की सबसे ज्वलंत समस्याएं हैं, उनकी ओर आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। मेरे हल्के में सबसे बड़ी समस्या ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की है। हमारे शहर में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जा रही है वह जो 12 साल पहले कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम बनी थी उसी से की जा रही है, तब से अब तक आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने इस बारे में प्रश्न उठाया था कि बढ़ी हुई आबादी को वाटर सप्लाई पूरी करने के लिए कुछ न कुछ प्रौविजन किया जाए और सीवरेज व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाए । कुछ कालोनी तो बहुत ही पुरानी हैं और उनकी सीवरेज व्यवस्था ठप्प पड़ी हुई है। मैं यह विनती करना चाहूंगी कि वहां की सीवरेज व्यवस्था में सुधार किया जाए । मेरे हल्के में ट्रैफिक जाम की बहुत ही ज्वलंत समस्या है। वहां कुछ रोड्स हैं जैसे गीता भवन चौक और मंडी रोड, जिन पर 24 में से 18 घंटे जाम रहता है और इसका मेन कारण बाई-पास का न होना है । आप स्वयं सोनीपत से हैं और आप जानते हैं कि वहां बाई-पास नहीं है मैंने पिछले वर्ष भी विधान सभा के सत्र में प्रश्न काल में इस बात को उठाया था। अध्यक्ष महोदय, खरखौदा तहसील है वहां भी बाई-पास का निर्माण किया गया है लेकिन सोनीपत में नहीं किया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि बाई-पास के निर्माण और आर.ओ.बी के लिए मैंने प्रश्न लगाया था कि मंडी की तरफ रेलवे लाइन है जिसकी वजह से वहां पर 24 में से 20 घंटे ट्रेन गुजरती हैं, इस वजह से जाम की स्थिति रहती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं । बड़ी मुश्किल से आर.ओ.बी. का कंट्रैक्ट पास हुआ है वह आर.ओ.बी. कब तक शुरू हो जाएगा ? इसको टाईम बाऊंड करके

[Smt. Kavita Jain]

जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि इस समस्या से निजात पाई जा सके । इसी तरह से सोनीपत में सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और हमने पता किया है कि वहां पर कूड़े के लिए कोई डंम्पिगं स्टेशन नहीं है ।

Mr. Speaker : You have a wonderful mind of positivity.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं आपने यह क्वैश्चन रेज किया है और यह जीता जागता उदाहरण हैं भ्रष्टाचार का और किस तरह से खरीद-फरोख्त की जा रही है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मिला लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं। (विघ्न) You have a mind of positivity, I must tell you. You are raising the public issues that's why this discussion takes place.

श्रीमती कविता जैन : मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बिना तैयारी के गवर्नर एड्रैस पर बोलने का समय दिया ।

Mr. Speaker : You are not levelling any allegation and you are coming with suggestions. So, I give you 10 more minutes to speak.

श्रीमती कविता जैन: स्पीकर सर, अब मैं सफाई व्यवस्था के बारे में कहना चाहती हूं मैं यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि हमने पब्लिक के लिए काम किया है इसलिए हम पब्लिक की प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं । मैं यह बात इसलिए सरकार की नॉलेज में लाना चाहती हूं कि सरकार क्या-क्या कदम उठाकर हमारे सोनीपत की समस्या दूर करेगी । सादल कलां में एक जमीन है उस जमीन पर केस चल रहा है मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि सरकार इस केस को जल्दी शॉर्ट-आऊट करे ताकि वहां पर कूड़े के लिए एक डम्पिंग स्टेशन बनाया जा सके।

Mr. Speaker : You want a dumping station in my constituency.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, इसी तरह से मैं बिजली की व्यवस्था के बारे में कहना चाहती हूं । इस विधान सभा के पिछले सत्र में भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि वहां बिजली की तारें लटक रही हैं । हाई टैंशन की तारें अवैध कालोनियों पर लटक रही हैं । जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो यह प्रश्न उस समय रेज नहीं किया जाता। तब तो कहते हैं कि आप लोग वोट दो, तब आपको वोट नहीं लेने चाहिएं। बाद में जब वे अपनी बात कहते हैं तो यह कह दिया जाता है कि अवैध कालोनियां हैं इसलिए न सीवर मिलेगा और न ही पानी मिलेगा और न ही बिजली मिलेगी । ये प्वायंट्स वोट के समय रेज करने चाहिएं। अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहती हूं। कल ही मैंने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से डिग्री कालेज के बारे में एक प्रश्न किया था । मैं उनसे फिर से अनुरोध करना चाहूंगी कि सरकारी कालेज में जो स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है वह ऐडिड कालेज के अन्दर नहीं दी जाती । अगर सरकार के समझ हो तो इस दिशा में भी जरूर सोचा जाए। एक बात और मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि सोनीपत में एक आई.आई.टी. संस्थान

जरूर खोला जाए । इसी तरह से मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहना चाहती हूं । हमारे राष्ट्र मण्डल खेल हुए उनमें सोनीपत के बच्चों का बहुत योगदान रहा है । सोनीपत में एक मात्र स्टेडियम सुभाष स्टेडियम हैं उसके अन्दर इन्टरनेशनल लैवल की फैस्लिटी नहीं है । मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे हल्के के बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से सुविधा दी जाए जैसे हॉकी के लिए जो ट्रफ होता है और कुश्ती जैसे दूसरे खेलों के लिए स्टेडियम की सभी सुविधाएं हमारे हल्के में प्रोवाईड की जायें। अब मैं हैल्थ सर्विसिज के बारे में कहना चाहूंगी । मेरे ख्याल से लाखों रुपया सिविल हॉस्पिटल की रेनोवेशन पर खर्च किया गया है । इस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या उन्होंने इस बारे में कोई सर्वे करवाया है कि इतना पैसा करोड़ों रुपया रेनोवेशन पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। अगर वहां पर जाकर ये विजिट करें तो सर्वे करने पर पायेंगे कि सिविल हॉस्पिटल तो जेल की तरह हो गया है वहां पर एक रुपया भी हैल्थ सर्विसेज पर खर्च नहीं हुआ है वह सारा पैसा बिल्डिंग पर खर्च किया गया है। अगर शुक्रवार को किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो वहां पर एक्स रे मशीन को चलाने वाला कोई नहीं है, कहते हैं कि पी.जी.आई. जाओ या सोमवार को आना। शनिवार और इतवार को एक्स-रे की मशीन उपलब्ध नहीं होती है चाहे इन दो दिनों में कोई व्यक्ति मर जाये या कुछ हो जाए। एक्स-रे की मशीन पर शुक्रवार के बाद कोई भी बन्दा नहीं होता यानि डॉक्टरी सेवाएं वहां बिल्कुल नहीं हैं। मैने अपने पिछले एक साल के दौरान जो-जो वहां देखा है उस बारे में बता रही हूं। मैं कोई पहले से पोलीटिकल कैरियर में नहीं थी लेकिन एक साल से जो मैंने सीखा है उसके बेसिज पर मैं अपने हल्के की समस्याएं बता रही हूं । स्पीकर सर, यहां सरकार के द्वारा 100-100 गज के मुफ्त प्लाट देने का ब्यौरा दिया गया । मैं इस बारे में कहना चाहती हूं कि जो शहरी गरीब हैं उनको भी ये 100-100 गज के प्लाट देने का प्रावधान करें । चूंकि मेरा हल्का सोनीपत शहर है । सोनीपत के शहरी गरीब लोगों को भी 100-100 गज के मुफ्त प्लाट देने का प्रावधान किया जाए । (विघ्न)

Mr. Speaker : Let her speak. She is the only female speaker of your party having certain amount of positivity in her mind. Let me record that she has spoken positively on certain issues.

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह बी.पी.एल. कार्डों का भी सर्वे दोबारा करवाया जाए और जो पात्र लोग हैं उन्हें ही बी.पी.एल. कार्ड दिए जाएं । धन्यवाद सर (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कविता जैन जी बहुत बढ़िया बोली हैं तो क्या आप यह आश्वासन दिलाएंगें कि जो इन्होंने कहा है उस पर अमल करेंगें ?

श्री मामू राम (नीलोखेड़ी) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस के पेज नं0 23 पर सरकार के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत बी.पी.एल. विधवाओं के लिए दी जानी वाली राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये की गई है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने भी लिस्ट भेजी हुई है ।

Mr. Speaker : Mr. Arora, you have been in this Chair. You can only send me the list. There are certain Members who are raising hands.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम मैम्बर के बोलने से पहले प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हमने जो लिस्ट दी हुई है कृपया करके उनमें से बुलवाने का कष्ट करें ।

Mr. Speaker : Hon'ble Mr. Arora, when your Member raises a hand I have to look towards him also.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जब हम हाथ खड़ा करते हैं तो आप हमें देखतें नहीं हैं।

Mr. Speaker : Mr. Mamu Ram, please continue.

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1 नवम्बर, 1999 को कन्यादान की स्कीम चलाई थी और उसमें 5100 रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया था । इस मुख्यमंत्री महोदय ने उस राशि को बढ़ाकर 15 हजार और अब 31 हजार रुपये करने का काम किया है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं । इस स्कीम में सभी लाभ पात्रों को दिक्कत आ रही है । जो बी.पी.एल.से सम्बन्धित परिवार हैं चाहे वे शिडयूल्ड कास्ट के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं या जनरल क्लास के हैं । उनको साढे 15 हजार रुपये की राशि शादी से पहले दी जाती है और साढे 15 हजार रुपये की राशि शादी के बाद दी जाती है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि बी.पी.एल. परिवार वालों को मिलने वाली यह रकम 31 हजार रुपये एक मुश्त किश्त के रूप में दी जाए ताकि वे अपनी लड़की के हाथ समय पर पीले कर सकें और उन्होंने जो समान खरीदना है वे भी समय पर खरीद सकें । अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे गरीब आदमी की मदद हो सकेगी । इन परिवारों को इस स्कीम से कितना लाभ हुआ है ? मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 2 परसैंट लाभ हुआ है । जिन लाभपात्रों की शादी रजिस्टर्ड हो जाती है उन्हीं को ही साढ़े 15 हजार रुपये की राशि शादी के बाद दी जाती है और ऐसे लाभपात्र केवल एक दो परसैंट ही हैं । उनको बड़ी दिक्कत आ रही है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस रजिस्टर्ड शब्द को इस स्कीम से हटाया जाए ताकि इस का पूरा लाभ गरीब आदमी को मिल सके । अध्यक्ष महोदय, आप भी और हम भी जितने विधायक यहां बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, हम लोग सब 20-20, 25-25 शादियों में जाते हैं क्या वे सारी शादियां रजिस्टर्ड होती है ? अगर वे सारी शादियां रजिस्टर्ड नहीं होती तो बी.पी.एल. परिवार वालों के लिए यह रजिस्टर्ड वर्ड क्यों लगाया गया है ? मेरा आपसे अनुरोध है कि शादी के रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन हटा दी जाये और शुरू में ही पूरे पैसे दे दिए जायें ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त तालाबों की बात करते हुए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे हल्के नीलोखेड़ी के ज्यादातर गांवों में तालाब ओवर फलो हो रहे हैं और सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है । वहां पर मक्खियां और मच्छर भी पैदा हो गये हैं जिससे बीमारियां फैल

सकती हैं । मैंने प्रशासन से भी प्रार्थना कर ली लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा । मेरे अपने गांव में तालाब ओवर फलो हो रहा है और मेरे घर तक जाने का रास्ता नहीं है । इसके अतिरिक्त माजरा और नीलोखेड़ी आदि कई गांव ऐसे हैं जहां तालाब ओवर फलो हो रहे हैं । इस तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त तरावड़ी के अंदर सितम्बर, 2008 में रेलवे ओवर ब्रिज बनाना शुरू किया गया था लेकिन वह आज तक भी चालू नहीं हुआ है जिसके कारण तरावड़ी मण्डी में जाने के लिए लोगों को बहुत परेशानी होती है इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में कुछ सड़कों की हालत भी बहुत खराब है उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये । वहां तरावड़ी जाना बहुत मुश्किल है और करनाल जाना आसान है क्योंकि तरावड़ी की सड़कें टूटी हुई हैं । तरावड़ी-नीलोखेड़ी सड़क की हालत बहुत खराब है इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी मुरम्मत करवाई जाये । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के नीलोखेड़ी के अंदर एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया । वहां न तो कोई स्कूल मिडल से हाई बनाया गया और न ही कोई स्कूल हाई से 10+2 बनाया गया । इस तरफ भी सरकार विशेष ध्यान दे। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में एक भी सरकारी कालेज नहीं है जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरे हल्के नीलोखेड़ी के अंदर निसिंग, तरावड़ी और नीलोखेड़ी में तीन शहर लगते हैं जिनमें एक भी सरकारी कालेज नहीं है जिसके कारण विशेषकर गरीब बच्चों को अपनी हॉयर एजूकेशन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है । अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी के अंदर पहले पुलिस चौकी होती थी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां दोबारा से पुलिस चौकी बनाई जाये । वहां से पुलिस चौकी हटाने के बाद वहां पोलिटैकनीक में रोज झगड़े और मर्डर होते हैं जिसके कारण वहां की कानून व्यवस्था बहुत खराब है इसलिए वहां पुलिस चौकी दोबारा से बनाई जाये । अध्यक्ष महोदय, नीलोखेड़ी के पास जी.टी. रोड़ पर ही बसें खड़ी होती हैं जिसके कारण वहां बहुत एक्सीडैंट होते हैं । प्रश्नकाल के दौरान मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया था कि तरावड़ी और नीलोखेड़ी में बस स्टैंड नहीं बनाया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि नीलोखेड़ी हल्के के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए किया जा रहा है कि वह हल्का लोक दल का है और रिजर्व हल्का है । अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के की समस्याओं के बारे में सदन को अवगत करवा दिया है इन समस्याओं की तरफ सरकार विशेष ध्यान देकर इनको दूर करवाये । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर एड्रैस पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : अब श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी बोलेंगे ।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने मैंबर्ज को बुलाने के लिए आपको जो सूची भेजी है आप उसी के मुताबिक बुलवायें । अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं होता ।

Mr. Speaker : Alright, his name is there. First of all, you cannot send the list to me. Secondly, if a Member raises his hand, it is for me to decide Mr. Chautala. (Interruption) I always try. (Interruption)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आप हैंड खड़े करने वाले सभी मैंबर्ज को समय देते हो ? यह तरीका गलत है । (विघ्न)

Mr. Speaker : Then why did you give the names. (Interruption)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : This is not to be recorded. Nobody can suggest to the Speaker who will speak. Speaker will decide. Let Mr. Parminder Singh to speak. (Interruption) Whether he is out of that list? If you do not want your MLAs to speak what can I do?

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, हमारे पार्टी लीडर ने सीरियल वाईज लिस्ट बनाकर आपको हैंडओवर की है।

Mr. Speaker : It is not serial wise. (Interruption) If you do not want your MLAs to speak, what can I do? You do not want your MLAs to speak. (Interruption) No. No. मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। I am being fair I want that new-comer should speak. (Interruption)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी तो न्यू-मैंबर हूं । जो मैंबर बोलना नहीं चाहते उनको समय दिया जा रहा है।

Mr. Speaker : Alright, you will also get a chance. But you have objection on his speaking.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, मेरा कोई ऑब्जैक्शन नहीं था।

Mr. Speaker : Mr. Badshami, I am not bound. Hon'ble Member, I am not bound by your list. (Interruption) Mr. Badshami, you want to tell the Speaker of this House that I am bound by this list.

Shri Sher Singh Badshami : Sir, I am not giving any direction. मैं तो सिर्फ रिक्वैस्ट कर रहा था।

Mr. Speaker : You are giving me direction and I do not take directions either from this side or from that side. I do not take directions.

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप ही हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसको कहेंगे ?

Mr. Speaker : Alright, Mr. Dhull you please continue. (Interruption) I have your list. (Interruption) Hon'ble Members, I have your list. Although

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

such list should not be given. (Interruption) Your Member is speaking. (Interruption) अधिकार है लेकिन यह अधिकार नहीं है कि आप मुझे लिस्ट देंगे।

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, हमारी पार्टी के नेता ने आपको सीरियल वाईज़ लिस्ट दी है हम यह चाहते हैं कि आप उसी के अनुसार हमारी पार्टी के सदस्यों को बोलने के लिए अलाऊ करें । (विघ्न)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बता दें कि हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय मिलेगा या नहीं ?

Mr. Speaker : If, you don't want that your M.L.A. is to speak then what can I do? Is your Speaker so weak that you can dictate him? (Interruption) मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूं । I am being fair I want that a new-comer should speak first.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं भी तो नया मैम्बर हूं।

Mr. Speaker : Alright, you will also get a chance. Have you any objection on his speaking?

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मेरा कोई ऑब्जैक्शन नहीं है । मैं तो यह चाहता हूं कि हमने जो आपको लिस्ट दी है आप उसको फौलो करें । (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Member, I am not bound by your list.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी लिस्ट के साथ बाऊंड हों ।

Mr. Speaker : Mr. Barshami, you want to tell the Speaker of this House that I am bound by this list.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, हमने तो अपनी लिस्ट दी है क्योंकि लिस्ट देने का हमारा भी अधिकार बनता है ।

Mr. Speaker : Alright, Mr. Dhull, please continue.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपके भी अधिकार हैं । हम तो यह कह रहे हैं कि हाऊस का टाईम बढ़ा लें ताकि सभी मैंबर्स बोल सकें।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have your list although such a list should not be given. A Hon'ble Member from the opposition is going to speak because when the discussion started ever-since opposition is speaking. (Interruption) आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मुझे लिस्ट दें । (शोर एवं व्यवधान) Am I such a weak person that you can dictate me?

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सिर्फ यह बता दें कि हमें टाईम मिलेगा या नहीं ? (विघ्न)

Mr. Speaker : Alright, Mr. Dhull do you want to speak? (Interruption) Hon'ble Member, you will speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, परमिन्दर जी के बाद आप श्री अजय चौटाला जी का नम्बर लगा दें ।

Mr. Speaker : First of all, it is a question propriety. If your Member raises his hand and he is a new comer and his name is also there. चौटाला जी, श्री परमिन्दर ढुल का नाम आपने ही दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : How can you tell? (Interruption) Mr. Arora, can you tell me to decide? You have been in this Chair.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम तो आपसे रिक्वैस्ट ही कर रहे हैं ।

Mr. Speaker : Alright, your request has been heard. Now, let Mr. Parminder Dhull to start. (Interruption) चौटाला जी, परमिन्दर ढुल का नाम भी आपने ही दिया है । (Interruption) Everybody please sit down. I have given time to everyone. (Interruption) Hon'ble Members, please resume your seats.

श्री परमिन्दर सिंह ढुल (जुलाना) : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मैं भी सदन के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए इस मौके पर सम्पूर्ण मातृ-शक्ति को बधाई देता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में सबसे पहले महामहिम ने सारे राज्य में मंगल की कामना की है लेकिन उसका पूरा अवलोकन करने पर ऐसा लगता है कि प्रदेश में आज अमंगल की स्थिति है और खास तौर पर हमारे इलाके में क्योंकि उसके बारे में इस दस्तावेज में कुछ नहीं कहा गया है । अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के पैरा नम्बर 6, पेज नम्बर 3 में प्रजातांत्रिक प्रणाली का काफी गुणगान किया गया है लेकिन जीन्द जिला परिषद् के चुनाव में जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक प्रणाली का हनन हुआ उसका गवाह सारा जीन्द जिला है । अध्यक्ष महोदय, जो खाद्यान्न उत्पादन घटा है उससे मेरा जुलाना हल्का भी अछूता नहीं रहा है । जुलाना क्षेत्र के अन्दर पिछले बुआई सीज़न के समय बीज नहीं मिला, खाद डालने के समय खाद नहीं मिली । घंटों लम्बी-लम्बी लाईनों में खड़े होकर सरकारी संरक्षण में खाद और बीज़ के साथ अनचाही वस्तुएं भी खरीदनी पड़ी । बार-बार प्रशासन को इस समस्या के समाधान के बारे में अनुरोध करने पर भी इस समस्या का कोई कारगर समाधान नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से

सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाये और किसानों को बिजाई के समय खाद और बीज की उपलब्धता पूर्ण तौर पर सुनिश्चित की जाये । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 8 पर बाढ़ के बारे में भी जिक्र किया गया है । मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा कि मेरे जुलाना हल्के के अन्दर सैंकड़ों एकड़ ज़मीन पर अभी भी बाढ़ का पानी खड़ा है, जिसके बारे में लोगों ने वहां प्रशासन से मिलकर भी अपनी इस समस्या से अवगत कराया जो कि 07 फरवरी, 2011 के दैनिक भास्कर अखबार में छपा है कि 350 एकड़ ज़मीन पर अभी भी बाढ़ का पानी खड़ा है और यह पानी इसलिए खड़ा है क्योंकि कोई भी ड्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और किसी भी ड्रेन की रिपेयर का काम भी नहीं हो रहा है। इस अखबार में यह भी कहा गया है कि जो 04 मार्च, 2011 को भयंकर बारिश हुई उसके चलते 10 गांवों की फसल पूर्ण रूप से तबाह हो गई है, यह आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी ड्रेनों की सफाई न होने के कारण हमारी बाढ़ की समस्या का निपटान नहीं हो पा रहा है और इस बात से माननीय मंत्री जी अवगत हैं । इसकी सफाई न होने का क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं सिंचाई का जिक्र करना चाहूँगा। मेरा जुलाना हल्का मुख्यत: नहरी पानी से ज्यादा सिंचित है नीचे का पानी हमारे इलाके में नहीं है। हमारे यहाँ नहरी पानी जे.डी.3 और जे.डी.4 दो मुख्य चैनल हैं जिनके द्वारा हमारे आधे हलके में सिंचाई की जा रही है । इसी प्रकार से करसोला माईनर, रामकला माईनर, किला जफरगढ़ माईनर तथा बराड़ खेड़ा सैक्शन इन चारों से पूरे प्रयत्नों के बावजूद भी किसानों को टेल तक पानी नहीं मिलता । उन टेलों पर पानी तभी पहुंच पाता है जब दूसरे इलाके में भारी बारिश हो वर्ना टेल पर पानी नहीं पहुंचता । अध्यक्ष महोदय, इसका कारण क्या है कि जीन्द की जो वाटर सर्विस डिवीजन है उसमें 2 लाख 22 हजार एकड़ का अकेला डिवीजन है और बाकी हरियाणा में बहुत से छोटे-छोटे कई डिवीजन काम कर रहे हैं । अगर जीन्द के इस वाटर सर्विस डिवीजन के दो हिस्से कर दिये जायें तो काम चल सकता है । एक तो सुन्दर ब्रांच सिस्टम अलग कर दिया जाये और दूसरा हांसी ब्रांच सिस्टम अलग कर दिया जाये । इससे 1 लाख 8 हजार एकड़ तो जुलाना में आ जायेगा तथा 1 लाख 14 हजार एकड़ जीन्द में रह जायेगा । जिससे ऑफिसर व्यवस्था भी ठीक हो जायेगी और इससे हमें पानी भी मिल जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की समस्या है । हमारे क्षेत्र में जमीन के नीचे का पानी न होने की वजह से हम नहरी पानी पर आश्रित हैं । नहरी पानी न मिलने के कारण यह व्यवस्था 80 प्रतिशत तक ठप्प पड़ी है । उनमें न पानी आ रहा है, न नालियाँ बनी हुई हैं और जो टंकियाँ दी गई हैं उनमें टूटियों के कनैक्शन नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर खेल के बारे में बहुत प्रचार हुआ और खेल का ढिंढोरा भी पीटा गया । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक भरत सिंह मैमोरियल स्कूल है, जिसकी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ आज के दिन राई स्पोर्टस स्कूल से भी ज्यादा हैं । अगर राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर देखा जायें तो उसके मैडल ज्यादा हैं लेकिन भेदभाव के चलते कि उनके सम्बन्ध इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं, इसलिए उनको स्पोर्ट्स नर्सरी की जो हरियाणा सरकार अनुदान राशि देती थी वह राजनीतिक द्वेष भावना के चलते बंद कर दी गई । वहाँ पर जो विंग थी वह विंग भी बंद कर दी गई जबकि अगर उनकी तुलना की जाये तो जो सरकारी सहायता प्राप्त स्पोर्ट्स

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

स्कूल हैं उनसे ज्यादा उपलब्धियाँ हैं । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जननायक चौधरी देवीलाल 1990 में जब वे भारत के उप-प्रधानमंत्री थे उन्होंने जुलाना में औद्योगिक विकास कुंज का एक तौहफा दिया था । उन्होंने औद्योगिक विकास कुंज की स्थापना की थी लेकिन हरियाणा में 1992-93 में एक उप-चुनाव हुआ । उसके चलते वह जुलाना का तौहफा पंचकूला जिले में स्थापित कर दिया गया । उसके बाद में चौधरी बंसीलाल जी भी मुख्य मंत्री बने थे और उन्होंने भी यह विश्वास दिलाया था कि आपका यह हिस्सा हम वापिस लायेंगे लेकिन वह बरवाला से सरक कर साहा में चला गया । आज के आदरणीय मुख्य मंत्री जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उस समय जुलाना हल्के के 20-22 गांवों में गये थे और उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि यह आपका औद्योगिक विकास कुंज दोबारा जुलाना में स्थापित किया जायेगा लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछड़े वर्गों और हरिजनों के बारे में बड़ा प्रचार किया गया लेकिन जुलाना में 1992 में बस स्टैंड बनाने के लिए वार्ड नं. 2, 4 और 5 की हमारे दलित भाईयों की जमीन ली गई थी। सरकार ने यह वायदा किया था कि उसके बदले में जमीन देंगे या पैसा देंगे । 1962 की हदबंदी के अनुसार 172 परिवार 5-5 मरले के मालिक हैं लेकिन सरकार ने आज यह कह दिया कि न ही तो वे मालिक हैं और न ही उनको मुआवजा दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की ज्यादती ठीक नहीं है । उधर जुलाना में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है कि हमारे जुलाना के साथ न्याय करके दलित भाईयों के साथ न्याय किया जाए । जुलाना में पीने के पानी की और कुछ नयी सड़कों को बनाकर वहां की सड़कों की व्यवस्था भी ठीक करवायी जाए । मैंने कल भी कहा था तो माननीय मंत्री जी ने एक दो सड़कों को बनाने के बारे में कहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका पुन: धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद ।

14.00 बजे

श्री शेर सिंह बड़शामी (लाडवा) : स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

Mr. Speaker : You were only loosing patience otherwise you were listed to speak.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी तो उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । अभी 4 मार्च, 2011 को राज्यपाल महोदय ने सदन के अंदर अपना अभिभाषण दिया था । अभिभाषण के अंदर सरकार की कार्यशैली और सरकार की उपलब्धियाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है लेकिन जो उपलब्धियाँ दर्शायी गयी हैं, वे वास्तविकता से दूर हैं । उनको तोड़ मरोड़कर दर्शानें का काम किया गया है। मैं कुछ एक बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इन मुद्दों पर आकर्षित करने का प्रयास करूंगा । सबसे पहले ही प्वायंट पर कहा गया है कि मेरी सरकार की विश्वसनीयता एवं सराहनीय उपलब्धियों के लिए हरियाणा के विवेकशील लोगों ने इसे नया जनादेश दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले दिनों जो चुनाव हरियाणा में सम्पन्न हुए थे उनमें कांग्रेस पार्टी को 90 सीटों में से केवल मात्र 40 सीटों पर जिताने

का काम हरियाणा की जनता ने किया था । इसके बाद कुछ और सदस्य मिलाकर इनकी संख्या 45 तक पहुंच जाती है लेकिन मैं इस देश की पार्लियामैंट्री कंवैंशन के आधार पर, इस देश के भिन्न-भिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर और दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज की पार्लियामैंट्री कंवैंशन के आधार पर यह कह सकता हूं कि जो राजनैतिक दल अपनी पार्टी के सदस्यों से 50 परसैंट का आंकड़ा पार नहीं कर पाए तो वह माइनोरिटी की गवर्नमैंट कहलाती है जो हमारी मौजूदा सरकार है क्योंकि यह सरकार 50 परसैंट का आंकड़ा आज भी पार नहीं कर रही है । इसको देशी भाषा में हम जुगाड़ की सरकार भी कह देते हैं । यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह मैं तथ्यों के आधार पर कहने का प्रयास कर रहा हूं।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे काबिल साथी ने सरकार की वैधता पर प्रश्नचिन्ह उठाया है । मैं उनकी जानकारी के लिए और आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 40 साथी कांग्रेस के हैं, जो सात निर्दलीय साथी हैं उन्होंने बगैर शर्त समर्थन सरकार को दिया है और हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस पार्टी के अंदर बाकायदा मर्जर हुआ है । खुद बड़शामी जी ने, चौधरी अजय सिंह जी ने और दूसरे साथियों ने इस मर्जर को चुनौती दे रखी है और यह मामला आपके सामने विचाराधीन है । इसके अलावा एक जो हमारे बी.एस.पी. के साथी हैं उन्होंने भी बगैर शर्त सरकार को समर्थन दिया है इसलिए इनका यह कहना कि यह अल्पमत की सरकार है, सरासर गलत है ।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, at the time of Confidence Vote how many Members were with you?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, at the time of Confidence Vote there were 40 Congress MLAs, 7 Independent MLAs and 1 BSP MLA who had extended in writing unconditional support to the Government.

Mr. Speaker : It means you were 48 Members.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, 48 Members had extended support at that time. So, my learned friend is factually incorrect.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कह रहा था, मंत्री जी ने उससे हटकर बताया है । मैं यह कह रहा था कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों की संख्या आज भी 50 परसैंट का आंकड़ा पार नहीं करती इसलिए यह गवर्नमैंट आज भी पार्लियामैंट्री कंवैंशन के हिसाब से माईनोरिटी की गवर्नमैंट कहलाएगी । यदि दूसरे राजनैतिक दलों के सहयोग से कोई सरकार बनती है तो वह कोएलेशन की गवर्नमैंट कहलाती है ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1999 में जब 22 एम.एल.एज. से चौधरी बंसीलाल जी की सरकार नाजायज तरीके से तोड़कर बना ली थी तो क्या वह करैक्ट थी ?

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं । आज भी यह सरकार 45 या 50 का आंकड़ा जरूर पार कर रही है लेकिन जब कभी भी इस सरकार को विश्वास मत लेना होगा तो उस समय भी यह आंकड़ा पार नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, यदि अपना इस्तीफा देकर वोट डालेंगे तो कास्टिंग वोट के हिसाब से चाहे यह सरकार विश्वास मत जीत जाए अन्यथा तो अपनी पार्टी के हिसाब से विश्वास मत जीतने की पोजीशन में आज की मौजूदा सरकार नहीं है, जिसका ये निरंतर ढिंढोरा पीट रहे हैं।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, they should bring Vote of No Confidence against the Government.

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मौजूदा सरकार इस बात का निरंतर ढिंढोरा पीट रही है कि जनता ने हमें जनादेश दिया है। सर, मैं बताना चाहूंगा कि जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया है । जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया है । भिन्न-भिन्न लोगों को जोड़कर जुगाड़ की सरकार बनाकर (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is Governors' Address. Is this subject contained in the Governors' Address?

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, यह सरकार का ही सारा मामला है जो कि गवर्नर महोदय द्वारा यहां पर पढ़ा जाता है ।

Mr. Speaker: Mr. Badshami, you are a lawyer yourself. आप एक वकील हो। इनके खिलाफ आप नो कांफीडैंस मोशन ले आओ।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, they should bring Vote of No Confidence against the Government.

श्री शेर सिंह बड़शामी : वह भी ले आएंगे, उसमें समय लगता है। जब उचित मौका आएगा तो ले आएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप कंक्लूड करें। आपका समय होने वाला है Only six minutes are left. I want Mr. Chautala to be the next speaker. So, you have to finish in four minutes so that I can give him ten minutes and after that Chief Minister's reply will come.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही बोलूंगा । जहां तक सड़कों का सवाल है। इस अभिभाषण में दर्शाया गया है कि हरियाणा प्रदेश की सड़कें पूरे समयबद्ध तरीके से मरम्मत कर दी गई है। यह भी कहा गया है कि यमुनानगर लाडवा और करनाल को चार मार्गीय बनाया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चार मार्गीय तो बनना दूर की बात है, ऐसे हालात हैं कि उसकी रोड़ी भी दिखाई नहीं देती है। मुख्यमंत्री महोदय लाडवा में किसी शादी में या समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं तो

वे हैलीकॉप्टर से जाते हैं । यदि ये वहां सड़क मार्ग से जाएं तो सड़कों की हालत कुछ सुधर सकती है। जिला कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की सारी सड़कें टूट चुकी हैं । जो हालात पहले बिहार के थे वे आज हमारे प्रदेश के हो गए हैं । सिंचाई के बारे में इस अभिभाषण में दर्शाया गया है और कहा गया है कि हमने एस.वाई.एल. और बी.एम.एल.हांसी बुटाना नहर के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं । मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पूरी तरह से अंकित किया था कि यदि जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया तो हम एस.वाई.एल. का निर्माण सबसे पहलें करेंगे। जनता ने कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया लेकिन एस.वाई.एल. निर्माण पर मौजूदा सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया । सुप्रीम कोर्ट से फैसला 15 जनवरी, 2002 को हुआ था उसके बाद फिर पंजाब ने उस पर रिव्यू पेटीशयन डाल दी थी। जून, 2004 के निर्णय के बाद पंजाब सरकार ने हाउस में टर्मिनेशन ऐक्ट पास किया, उसके बाद केन्द्र सरकार आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चली गई । बार- बार हरियाणा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एस.वाई.एल. कैनाल का मामला न्यायालय में विचाराधीन है । आज मैं इस सदन को खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. से संबंधित कोई भी मामला इस देश के किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। केवल मात्र एक रैफरैंस है और उसको किसी भी केस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 142 और 143 के तहत सरकार कोई भी परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से मांग सकती है । (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर ।

श्री शेर सिंह बड़शामी : कल भी इस सदन में यह तय हुआ था कि इन दोनों नहरों के निर्माण के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव डाल देना चाहिए । जहां तक हांसी बुटाना नहर का सवाल है। मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर भी प्रस्ताव लाना चाहिए । जहां तक एस.वाई.एल. के निर्माण कार्य का सवाल है उसके बारे में मेरा कहना है कि रैफरैंस केन्द्र सरकार ने डाला है, उसके बारे में यहां से प्रस्ताव पारित करें और वह रैफरैंस वापस लें। आपको पूरी पॉवर है । (विघ्न)

Mr. Speaker : OK, your time is over please sit down.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, सरकार जान बूझकर नहर का निर्माण नहीं करना चाहती और लोगों को बहकाने का काम करती है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, unfortunately, my learned friend either does not understand or does not want to understand what is a presidential reference? सर, अब तो ये बोल लिए है। मैंने इन को डिस्टर्ब नहीं किया। जब तक ये बोलते रहे मैं सुनता रहा। (विघ्न) कई बार यहां अगर कोई काबिल साथी बोल रहा हो तो रिक्वैस्ट की जा सकती है।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अगर मंत्री जी गलत बात कहेंगे तो उसका जबाव जरूर दिया जाएगा।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I took your permission and you permitted me. Sir, my learned friend either does not understand or perhaps does not want to understand that what is the sanctity of a presidential reference?

Mr. Speaker: Mr. Barshami, do you understand that?

Shri Sher Singh Barshami : Sir, I know that.

Mr. Speaker : What do you understand by presidential reference?

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, प्रेजिडैंशियल रैफरैंस जो है अंडर आर्टीकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने के लिए लिए डाला जा सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई परामर्श दे उसके बावजूद भी सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती और जब चाहे सरकार उसको वापिस ले सकती है।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, what do you understand by this?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, under the Indian Constitution, the final opinion of the Supreme Court of India Constitution Bench is sought by Government of India under Article 143. That reference has the sanctity of not only of the judgement of the highest court of the land, it is a reference made consciously by Government of India through President of India on an issue involving an important public policy or public matter. My learned friend is saying that any private matter can be referred. No. It is a public policy or a public matter that's why this is called presidential reference. In last 64 years there may be only less than a dozen references they may have been sought. That is the sanctity. But Baba Sahab Ambedkar and Pt. Jawahar Lal Nehru gave 2 presidential references. And here when Punjab Assembly passed a legislation, which was knownest in the eyes of the law, the Government of India headed by the Prime Minister Dr. Man Mohan Singh, on the request of Haryana Government made a reference saying that a Constitution Bench, a five Judges Bench of the Supreme Court should look at the issue and should say whether or not the Punjab Assembly had a right to pass a legislation terminating agreements which went even beyond their territory. There cannot be something more sacrosanct than that. Unfortunately, my learned friend is making a mockery of a presidential reference that is really sad.

श्री शेर सिंह बड़शामी : सर, जो मंत्री जी ने बताया है वह केवल भाषण देने की बात कही गई है। (विघ्न) उनका मेरे को जबाव तो देने दो। मैं पंजाब ऐक्ट पर भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि पंजाब ऐक्ट बनाया और फिर रैफरैंस पर भी बताऊंगा।

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Speaker Sir, he cannot mislead the House. He cannot say that the matter is not in the Court. The matter is in the Court.

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Speaker Sir, after it has been referred to a Constitutional Bench, when it is a subjudice matter, how can he even talk about it?

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir, the matter was referred by His Excellency regarding the Punjab Termination of Act, which was passed by the Punjab Government.

Mr. Speaker : Mr. Illyas, please do not raise your hand time and again. I wanted Mr. Chautala to speak. But you are raising your hand time and again. If you do not want him to speak, then you can speak. I have already mentioned that he will speak but you are still raising your hand. (Interruption) Do you not want to speak him? (Interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो टर्मिनेशन ऐक्ट पास हुआ उस समय हरियाणा में आदरणीय चौटाला साहब की गवर्नमैंट थी । इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । उस समय केन्द्र में हमारी कांग्रेस की गवर्नमैंट थी और हम सब जाकर वहां मिले । हमारी कांग्रेस सरकार के कहने पर प्रैजीडैंशियल रैफरैंस दिया गया । इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया बल्कि इन्होंने तो मामले को लटकाने की कोशिश की । इनका यह कहना कि हम सीरियस नहीं हैं तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने कई बार इसकी एग्जीक्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। हमने मार्च, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बारे में मैंशन किया, जुलाई, 2007 में मैंशन किया और 2008 को मैंशन किया। इसके लिए कंस्टीच्यूशनल बैंच कांस्टीच्यूट हो चुका है । हम बार-बार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम अपने हितों के लिए बैस्ट एडवोकेट्स लगा रहे हैं । ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लम्बित नहीं है । यह टोटली हाउस को मिसलीड कर रहे हैं । ये पढ़े लिखे हैं इनको इस प्रकार की बात हाऊस में नहीं कहनी चाहिए।

Mr. Speaker : Now, Shri Ajay Singh Chautala may speak please.

श्री शमशेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded here. I have already requested Mr. Chautala to speak. So, please sit down.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

डॉ0 अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको जवाब दे देने दो । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I have requested Shri Chautala to speak please. (Interruption) Mr. Chautala will speak.

डॉ0 अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं लेकिन एक मिनट कोई बात तो खत्म करे।

Mr. Speaker : No, I want you to speak. I have already called your name. (Interruption) No, I want to hear you. (Interruption) Are you ready to listen to me please. Nobody from the Treasury Benches has spoken so far. This is probably happening for the first time in this House. Till now today, nobody has spoken from Treasury Benches. Only Members from Opposition Benches are speaking. So, Mr. Chautala please stand up and speak.

डॉ0 अजय सिंह चौटाला (डबवाली) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद आपने मुझे 4 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मेरे से पूर्व इस महान सदन में बहुत से वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बातें और अपने विचार बड़े विस्तार से रखे हैं । सभी सदस्यों ने अपनी समस्याओं को भी उजागर किया है । मैं उन बातों को पुन: दोहरा कर इस सदन का समय जाया नहीं करना चाहूंगा परंतु कुछ मुद्दे इस अभिभाषण का ही अंश है जिनके बारे में मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा । सरकार ने अभिभाषण के जरिए अपनी अनेक उपलब्धियों का व्याख्यान करवाया है । अध्यक्ष महोदय, सरकार के मुखिया, सदन के नेता पिछले 6 वर्षों से लगातार बिजली के मामले को लेकर बड़े-बड़े दावे और बड़ी-बड़ी बातें पब्लिक के बीच में तो करते ही रहे हैं, अनेक बार अपनी बातों से इन्होंने लोगों को ***** का काम किया है।

Mr. Speaker : Please remove the word ******

डॉ0 अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया है। अब तो हद इससे भी आगे हो गई है कि महामहिम राज्यपाल जी से भी अभिभाषण के जरिए उस गरिमामयी पद का भी ध्यान नहीं रखा गया, उनसे भी गलत ब्यानी करवाई गई । इस अभिभाषण में बिजली के मामले को लेकर कहा गया कि सभी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में बेहतरीन प्रगति हो रही है । खेदड़, हिसार में 1200 मैगावाट की राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना की दोनों इकाइयां क्रमश: 38 माह और 44 माह की एक रिकार्ड अवधि में अप्रैल, 2010 और अक्तूबर, 2010 में चालू हुई । अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ 2.3.2011 के दैनिक भास्कर अखबार में खबर छपी है कि "खेदड़ प्लांट की दूसरी यूनिट का ट्रायल निर्धारित समय में हुई एक साल की देरी हस्तांतरण की तैयारियां शुरू ।" इसमें अभियंता के.सी. गर्ग के अनुसार पावर प्लांट में बिजली के

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

उत्पादन के लिए कोयला इंडोनेशिया से अगले दो महीने में आना शुरू हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो कोयला आये बिना ही शुरू भी कर दी । अगर शुरू कर दी है तो वह बिजली कहां जा रही है । इस तरीके से एक नहीं अनेकों जगहों पर गलत ब्यानी खुद मुख्यमंत्री जी ने बार-बार की है । मुख्यमंत्री जी ने बार-बार यह भी कहा है कि दो साल के अंदर हम प्रदेश में बिजली की कमी पूरी कर देंगे । यह बात मुख्यमंत्री जी जहां पब्लिक मंचों पर कहते हैं वहीं इस हाऊस में भी अनेकों बार इन्होंने ऐसा कहा है । अब ये दो साल इनके कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बता दें । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यमुनानगर के बिजली संयंत्र के बारे में कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर 480 करोड़ रुपये के घाटे का उल्लेख हुआ है। दूसरी तरफ सरकार गोल्ड मैडल लेने की बात करती है। इसके बारे में वहां के एक इंजीनियर्स के ग्रुप ने लिखा भी है कि यह जो गोल्ड मैडल है इसको वापिस लिया जाये । अब ये इस तरह की दोहरी बातें लगातार करते हैं । सदन को मिसलीड कौन करते हैं मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में इसके बारे में भी बता दें । अध्यक्ष महोदय, जहां तक लॉ एंड आर्डर की बात है इस बारे में भी सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं । जबकि हकीकत यह है कि हरियाणा प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है यह मैं नहीं कह रहा, सरकार के स्वयं के आंकड़े कह रहे हैं । पिछले दिनों भिवानी जिले में लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं । वहां बच्चों का अपहरण हो रहा है और लोगों की भैंसे चोरी हो रही हैं । बार-बार ये बातें वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में लाई जाती हैं तो वे कहते हैं कि क्लू मिल गया है हम कार्यवाही कर रहे हैं परंतु न तो आज तक जिस बच्चे का अपहरण हुआ है उसका कोई पता चला है, न मर्डर्ज का पता चला है और न ही जो भैंसें चोरी हुई हैं जिनमें 200 के करीब मुकदमे भी दर्ज हुए हैं उनका पता चला है । अध्यक्ष महोदय, एक मामला तो यहां तक भी हुआ कि प्रशासनिक अधिकारियों को बाकायदा ध्यान में लाया गया कि ट्रक में लोड करके भैंसों को चोरी करके ले जा रहे हैं । उस ट्रक का एक ए.एस.आई. पीछा भी कर रहा था और उसने आगे थाने में भी सूचित किया उसके बावजूद भी प्रशासन चोरों को नहीं पकड़ पाया । आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, ये छोटी-छोटी घटनाएं हैं। अनेकों ऐसे ईशू हैं जिनके बारे में स्वयं मुख्यमंत्री जी जाकर कह कर आये कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करवाऊंगा और इंसाफ मिलेगा लेकिन किसी भी घटना में कार्यवाही नहीं हुई तथा न ही किसी दोषी को सजा मिली। ऐसे किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह सब लिखवाया गया है, लिखा गया है । दूसरे मुद्दों पर मेरे साथी बोल चुके हैं मैं रिपीटीशन नहीं करूंगा और सदन का ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा किसी नये सदस्य को आप समय देंगे तो ज्यादा अच्छा है लेकिन जो बातें मैंने उठाई हैं इनको मुख्यमंत्री जी जरूर स्पष्ट कर दें । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

Mr. Speaker : Now, Mr. Naresh will speak.

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी सभी माताओं और बहनों को बधाई और शुभ-कामनायें देता हूं।

[श्री नरेश कुमार बादली]

स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि ढांचागत विकास में सभी विभागों में हर वर्ग, जाति और क्षेत्र का विकास हुआ जिसके परिणामस्वरूप जननायक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ पुन: हरियाणा में सत्तासीन हुई । इसके लिए भी मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं । हमारी सरकार ने 36 बिरादरी को साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के विकास के कार्यों की झड़ी लगाई है और आम आदमी, दबे, पिछड़े, गरीबी रेखा से नीचे की जनता सभी को उत्साहित करने के लिए अनेकों ऐसी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से पहले हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह ध्यान रखा कि हर वर्ग के गरीब से गरीब साथी को इस योजना का लाभ पहुंचेगा । आज हरियाणा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में विकास का पर्याय बन चुका है । अब हमारी सरकार की नीतियों का अनुसरण दूसरे राज्यों में भी किया जाता है । अगर कहीं भी चुनाव होता है या रैलियां होती हैं चाहे वह नेता भाजपा का हो या दूसरे राज्यों में किसी अन्य पार्टी का नेता हो और चाहे कांग्रेस पार्टी का ही कोई नेता क्यों न हो उसको यह कहने के लिए मज़बूर होना पड़ता है कि आप मुझे वोट दो, आप मुझे सत्तासीन करो मैं आपसे यह वायदा करता हूं और मैं यह कसम खाता हूं कि हरियाणा के जनप्रिय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की नीतियों पर चलूंगा और हरियाणा प्रदेश की तर्ज़ पर ही अपने क्षेत्र का और अपने प्रान्त का विकास करूंगा । मैं इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूँ। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य था कि जब वर्ष 2005 से पहले एक लूट-खसूट और भय-भ्रष्टाचार की सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों और मज़दूरों की आंखों में धूल झोंककर वोट प्राप्त करके सत्तासीन होने में कामयाब हुई थी । आज वही लोग किसान हितैषी होने का बड़ा-बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं और मुनादी करवाते हैं । स्पीकर सर, जब विपक्ष के साथियों की सरकार के समय में भूमि अधिग्रहण हुआ करती थी तो 2001 से 2005 के बीच में उसकी मुआवज़ा राशि 2.60 लाख रखी जाती थी । यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं यह बात रिकार्डिड है । अपने पास से कुछ कहने की मेरी आदत नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप जो भी बोलें वह सिर्फ गवर्नर एड्रैस पर ही बोलें । (शोर एवं व्यवधान) Naresh Ji, please wait a minute. (Interruption)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have to make an announcement.

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, भिवानी का जिक्र आया था, I want to say something about the incident which Mr. Chautala has told.

Mr. Speaker : You are a Minister. (Interruption) Hon'ble Members, please bear with me. Please no discussions. It is 2.30 P.M. The House was to adjourn at 2.30 P.M. Since the Members have to participate on Governor's Address. It is very important. A fruitful discussion is taking place. Keeping in view, although the Hon'ble Chief Minister, the Leader

of this House was to reply on the debate at 2.00 P.M. I extended time till 2.30. Now, I extend the time for half an hour more. (Interruption) A lot of new Members are to participate and for that everybody has to cooperate with me. Otherwise, many of new Members will not get an opportunity to speak which is not good in democracy and the senior-leaders are also requested to kindly allow the first-timers or the new-comers to kindly participate in such a debate which is of such paramount importance.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting be extended for half an hour?

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The time of the Sitting is extended for half an hour.

Now Mr. Naresh, when you say something, speak with specifics whose Government was at that time because I do not know certain things.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री नरेश कुमार बादली : सर, मैं माफी चाहूँगा, मैं समझ नहीं सका कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बोलें स्पेसिफिक बोलें, नाम लेकर बोलें ऐसा नहीं कि कौन था क्या था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : ठीक है सर ।

चौ.मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रैशर नरेश जी को भी है और ब्लड प्रैशर मुझे भी है । इसलिए अगला टाईम बोलने के लिए आप मुझे दें ।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने माना है कि नये सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाये तो मेरा अनुरोध है कि समय को 5 बजे तक बढ़ा लिया जाये ताकि और सदस्यों को भी मौका मिल जाये ।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे एक साथी चौ. मोहम्मद इलियास को ब्लड प्रैशर है इसलिए उसको पहले चैक करवा लिया जाये । यह बहुत चिंता का विषय है । वह हमारे माननीय सदस्य हैं ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अधिग्रहण नीति के बारे में बोलना चाहूँगा । हमारी सरकार से पहले इस हरियाणा प्रदेश में जो सरकार थी उसने हरियाणा के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले में जो मुआवजा राशि दी वह थी 2 लाख 60 हजार रुपये । इस मामले में हम भुक्तभोगी हैं क्योंकि बादली विधान सभा क्षेत्र में भी जमीन अधिग्रहण की गई थी। कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रैस हाईवे सबसे ज्यादा हमारे बादली विधान सभा क्षेत्र से निकलता है । उसके बाद जैसे ही चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार आई तो यह रिकॉर्ड की बात है कि इन्होंने मुआवजा राशि को बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दिया जो हम लोगों ने प्राप्त किया है । मेरे पास इसका सबूत है और इसको निकलवा कर देखा जा सकता है । (इस समय मेजें थपथपाई गई) ये जो भूमि अधिग्रहण कर रहे थे वह किस काम के लिए कर रहे थे ? बार-बार यह बात उठाई जाती है कि भूमि अधिग्रहण जनहित में की जाती है लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो गुड़गाँव के पास बादली के साथ लगती सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था । उस जमीन पर ये क्या करना चाहते थे ? ये दुनिया का सबसे बड़ा जुआघर यानि कि कैसिनो बनाना चाहते थे । कल चौटाला साहब हमारे एम.पी. के बारे में कह रहे थे यह उनको शोभा नहीं देता लेकिन आज हमें गर्व है तथा फख्र है कि हमारे एम.पी. जो देश में सबसे ज्यादा मतों से जीते थे वे आज वहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस स्थापित करवा रहे हैं । (इस समय मेजें थपथपाई गई) इसके लिए हमें फख्र है, गर्व है । अब ये बार-बार कानून की दुहाई देते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था तो हुड्डा साहब ने लागू की है । जो महानगर हैं वहां पर अपराधियों पर कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है और आधुनिक व्हीकल्ज पुलिस को मुहैया करवाए जा रहे हैं । इसके अलावा फोर्स को चुस्त दुरूस्त बनाने के लिए और भी अनेक योजनाएं लागू की जा रही है । हमारे साथी बार-बार कानून व्यवस्था की दुहाई देते हैं । मैं अखबारों की खबर तो इनके सामने बाद में रखूंगा । मैं पहले कानून व्यवस्था पर प्रकाश डालना चाहता हूं । चौटाला साहब के शासन के समय में कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरूस्त थी कि एक किसान जब अपने खेत में से अपने ही ट्रैक्टर से मिट्टी लेने जाता था और मजदूर के बजाए वह खुद मिट्टी खोदकर अपनी ट्राली में भरता था तो इनके * * वहां पर पहुंच जाते थे और उसको मिट्टी लाने से रोका जाता था । उस समय * * लिया जाता था ।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाएं।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : नरेश जी, आप बैठिए । आप अपनी भाषा में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें । आप अपनी भाषा में रस पैदा करें । बात को कहने का एक ढंग होता है ।

श्री नरेश कुमार बादली : ठीक है सर। मेरे कहने का भाव यह नहीं था बल्कि मेरे कहने का भाव यह था कि भू-माफिया और शरारती तत्वों को उस समय संरक्षण दिया जाता था। उस समय जेलों का भी दुरुपयोग किया जाता था । * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकार्ड न की जाए ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए मेरे से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं । उस समय जो विरोधी पार्टी के नेता थे, जो जनता की सम्पूर्ण भाव से सेवा करना चाहते थे मैं उनकी बात बता रहा हूं । मैं पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आनन्द सिंह दांगी जैसे हमारे महान नेता को भी उस समय प्रतिद्वंदिता की वजह से झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया था । पूरे हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे संसार के अंदर हरियाणा प्रदेश की उस समय बदनामी हुई थी जब * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. अब राजपाल भूखड़ी बोलेंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राज पाल भूखड़ी (सढौरा) (अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

Mr. Speaker : Mr. Kali Ram please sit down. (Interruption) Nothing is to be recorded. (Noise & interruption) Hon'ble Members you are creating the fuss in the House. (Interruption)

श्री राम पाल माजरा : सर, हमारे सभी सदस्य बैठ जाएंगे, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे बोलने का समय दें।

Mr. Speaker : Ram Pal ji, as far as giving you the time is concerned let me decided but at the same time I see that your members are not listening to me. If they resume the seats I will have time to allot. But if they do not resume their seats what will I do? If you do not want to cooperate with me (Interruption)

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए परमीशन दे दी है, क्या मैं बोलूं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने परमीशन नहीं दी है। I just said cooperate with me. If you cooperate with me the valuable time of the House will not be lost. I have to make an observation here. O.K. I have asked into.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. आप क्या बोल रहे हैं नरेश जी, आप काफी देर से इस कागज को लहरा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या ले रहे हो आप ऐसा।

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, ** ** **

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए। अब राजपाल भूखड़ी जी बोलेंगे।

श्री राज पाल भूखड़ी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज महिला सशक्तिकरण दिवस है। इस अवसर पर मैं अपनी मातृशक्ति को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे से कोई सदस्य पूछ ही नहीं रहा है सब बोल रहे हैं । मेरे से कोई नहीं पूछ रहा है जो भी सदस्य मेरे से पूछे बगैर बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए । Nothing is to be recorded. Any Hon'ble Member, who has spoken without my permission his statement, will not be recorded. Mr. Sangwan, you are a Minister, you can reply even outside your department. But at the same time, any Minister of this Government can speak on any issue which is not a subject. As a Minister you can speak but with my permission. O.K.

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस है मैं इस दिवस पर अपनी मातृ शक्ति को बधाई देता हूं । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ बातें कहना चाहता हूं । पिछले छः वर्षों में हरियाणा विकास का एक नया प्रतीक बन गया है । राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों के वित्तीय दबाव को पीछे छोड़ते हुए मन्दी से उबर चुकने में सक्षम रही है । सन् 2010 और 2011 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 9 प्रतिशत की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 7.2 प्रतिशत की वृद्धि की दर से बढ़ने की संभावना है । सर, वर्ष 2010-2011 में राजस्व प्राप्तियां 23.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है जोकि वर्ष 2009-2010 में यह दर 13.8 प्रतिशत औसत से थी । इससे लगता है कि हमारा राज्य तरक्की कर रहा है । सर, अगर मैं कृषि क्षेत्र की बात करूं । हमारी सरकार ने एक सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक की अध्यक्षता में किसान आयोग का गठन किया है । यह आयोग हरियाणा में कृषि की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगा और राज्य में मुख्य कृषि पद्धतियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और सहभागिता बढाने की ओर उपाय सुझायेगा । यह प्रतियोगी और सार्वजनिक नीतियों में तालमेल बैठाने की सिफारिश करेगा, यह ग्रामीण क्षेत्र में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उपाय सुझायेगा । इससे राज्य का हर किसान तरक्की करेगा, मैं यह उम्मीद करता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉग करता हूं। वहां से विधायक हूं । मेरा जो क्षेत्र है यमुनानगर जिला में गन्ने और पापुलर की खेती मुख्य रूप से होती है । यमुनानगर के लोगों की जीविका का सबसे बड़ा साधन गन्ना और पापुलर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने गन्ने के जो रेट दिए हैं वे

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

220 रुपये, 215 रुपये और 210 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिए हैं, जोकि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके लिए मैं सरकार के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा । यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि 1999 से लेकर 2005 के बीच के समय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी का शासनकाल था उस समय में सरकार ने किसानों को 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की कीमत निर्धारित की थी लेकिन किसानों को 87 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पेमेंट की गई थी । आज हमारे किसान तरक्की कर रहे हैं लेकिन पिछली सरकार के समय में हमारे किसानों के साथ बहुत धोखा हुआ था और उनका नुकसान हुआ था । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो क्षेत्र है उसमें पॉपुलर की और गन्ने की खेती होती है। पिछली सरकार में मिल मालिक से पैसा मांगने जाने पर किसानों से अभद्र व्यवहार किया जाता था । किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिलता था । उसको पैसा मांगने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी । किसान को अपनी फसल का समय पर पैसा भी नहीं मिलता था और न ही उसको अपनी फसल का ठीक रेट मिलता था । अब हमारी सरकार गन्ने के उचित मूल्य दे रही है । हमारे जिले का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का किसान आज प्रगति कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं पॉपुलर की बात करूं तो यमुनानगर में पॉपुलर की खेती पूरे देश में सबसे ज्यादा होती है । उपाध्यक्ष महोदय भी यहां बैठे हैं। इनके एरिया में पॉपुलर की खेती बहुत ज्यादा होती है । आज पॉपुलर का रेट 1100 , 1200 और 1250 रुपये प्रति किवंटल मिल रहा है । 1999-2000 के बीच का समय जब ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल था उस समय पॉपुलर का रेट 150 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था । उस समय किसान की बहुत दुर्गति हुई । उस समय किसानों ने पॉपुलर लगाना बन्द कर दिया था। अब लोगों में ऐसा अहसास हुआ है कि हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब पॉपुलर का क्या रेट मिल रहा है ?

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस समय पॉपुलर के रेट 1250 रुपये प्रति क्विंटल मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष : उस समय पॉपुलर का क्या रेट था ?

श्री राजपाल भूखड़ी : सर, उस समय 150 रुपये प्रति क्विंटल पॉपुलर कर रेट था।

श्री अध्यक्ष : आप किस समय की बात कर रहे हैं ?

श्री राजपाल भूखड़ी : सर, यह 1999 से 2005 की बात है जब ओम प्रकाश चौटाला का शासनकाल था । (शोर एवं व्यवधान)

डा0 अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज जो बाकी चीजों के दाम बढ़ गए हैं उनके बारे में भी आप इनसे पूछ लें ।

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं ।

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसे विधायक जी कह रहे थे कि लोकदल की सरकार में पॉपुलर के रेट 150 रुपये प्रति क्विंटल थे तो मैं कहना चाहूंगा कि गवर्नमैंट कभी भी ये रेट डिसाइड नहीं करती । ये रेट डिमांड और सप्लाई के रेट हैं ।

श्री अध्यक्ष : उस समय क्या रेट थे ?

श्री दिलबाग सिंह : उस समय 165 रुपये प्रति क्विंटल पॉपुलर के रेट थे ।

श्री अध्यक्ष : आज क्या रेट हैं ?

श्री दिलबाग सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज 1000 रुपये से 1200 रुपये प्रति क्विंटल पॉपुलर के रेट हैं और ये रेट गवर्नमैंट डिसाइड नहीं करती । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं गेहूं और धान के भी रेट बताना चाहता हूं ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, *******

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, ये डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो मैं आंकड़ों की ही बात कर रहा हूं । मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : राजपाल जी, आप झूठ जैसे शब्द इस्तेमाल न करें । उन्होंने ये रेट मान लिए हैं ।

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, आज पॉपुलर और सफेदे के पत्ते 150 रुपये से 200 रुपये प्रति क्विंटल बिकते हैं जबकि उस समय पॉपुलर का तना 150 रुपये से 200 रुपये प्रति क्विंटल बिकता था । यह कितना बड़ा अंतर है । आज हमारी सरकार तरक्की कर रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं लेकिन आज ये लोग किसानों की बात करते हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस समय डीजल का क्या भाव था और दूसरी चीजों का क्या भाव था यह भी कम्पेयर करना चाहिए ।

Mr. Speaker : Mr. Surjewala ji, please tell me what were the prices of diesel or petrol in the year 1999?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का भी जवाब दूंगा उससे पहले एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं। Can I make humble request to you? सर, राजपाल जी नये सदस्य हैं इनको बीच में नहीं टोकना चाहिए । इनकी तरफ कई सदस्य बोले हैं । अजय चौटाला जी बोले हमारी तरफ से उन्हें किसी ने नहीं टोका परंतु राजपाल जी के बीच-बीच में ये लोग रनिंग कॉमेंटरी कर रहे हैं । राजपाल जी एक्चूअल बात बता रहे हैं उसमें भी कोई दर्द है क्या ? उस पर भी ये कॉमेंटरी कर रहे हैं । राजपाल जी बता रहे हैं कि अपने आपको किसान पक्ष की सरकार कहने वाली उस समय किसानों को पॉपुलर 150 रुपये क्विंटल बिकवाती थी और आज पॉपुलर 1000 रुपये से 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा है जबकि आज के दिन पॉपुलर के पत्ते ही 150 रुपये क्विंटल बिक रहे हैं । (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Mr. Speaker: Mr. Surjewala ji, I have pointedly asked about a point.

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I have given these figures in the House earlier. These figures are available with me. I will supply tomorrow these figures to the Hon'ble Speaker and Hon'ble Members.

Mr. Speaker : Krishan Pal ji, you want to say something about the sugar rate?

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस समय चीनी के क्या रेट थे और आज क्या रेट हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह बताया जाये कि उस समय चीनी के क्या रेट थे और गन्ने के क्या रेट थे दोनों बातें बतायें ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, पॉपुलर की बात छोड़िये इनके समय में कपास का रेट भी 1500 रुपये क्विंटल था और आज कपास 6000 रुपये क्विंटल बिक रही है । (शोर एवं व्यवधान) उस समय किसान की कपास लुटती थी । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Who is speaking without my permission not to be recorded.

श्री राम किशन फौजी : उस समय मण्डियों में किसान दुखी होते थे और उनका गेहूं मण्डियों में लुटता था । (शोर एवं व्यवधान) सर, किसान मण्डियों में हड़ताल करते थे उनका गेहूं बिकता नहीं था । (शोर एवं व्यवधान) इनके समय में बारदाना नहीं था । ये कपास के भाव के बारे में बतायें कि आज कपास का क्या भाव है । इनके समय में कपास 1500 और 2000 रुपये खरीदी जा सकती थी । जब किसान रोता था तो ये खुश होते थे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, * * *

राव बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, किसान खुश तब होता है जब उसे अच्छा भाव मिलता है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा मुझे ये लोग क्यों रोक रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सही बात करूंगा कि नारायणगढ़ के अंदर जो शूगर मिल है उसके अंदर किसानों ने जो गन्ना डाला था उसके पैसे पिछली सरकार के समय से नहीं मिले थे । उनके

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

[श्री राजपाल भूखड़ी]
जो लीडर जींद से थे वे यहां भी आये थे और उन्होंने बताया था कि किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा । मैं सच्चाई की बात करूंगा कि हमारे भाई चौधरी राम किशन जी विधायक बने और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करके किसानों के पैसे दिलवाये ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Member as discussion is going on. Very few members have spoken from treasury benches and Hon'ble Chief Minister has to give reply, So, is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended up to half an hour?

Voices : Yes, Sir.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for half an hour.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनराम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री राजपाल भूखड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भाई राम किशन जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की कि हमारे किसान भाई बड़े दुखी हैं, परेशान हैं । उन्होंने गन्ना मिल में डाल दिया और तीन-चार साल से पैसा नहीं मिला है । तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों का 3-4 साल का पैसा नारायणगढ़ शूगर मिल से दिलवाया जिस पर सभी किसान भाईयों ने राहत महसूस की । इस बात को पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है । (विघ्न)

15.00 बजे

Mr. Speaker: Don't indulge in insinuation. If you want to say something, say specific.

श्री राम किशन : स्पीकर सर, मैं इस बारे में अपने आपको राजपाल जी के साथ जोड़ते हुए एक बात और सदन की जानकारी के बताना चाहता हूं कि 1999-2005 तक श्री चौटाला जी की सरकार थी उस समय नारायणगढ़ शूगर मिल द्वारा किसानों की पेमैंट ही नहीं रोकी गई थी बल्कि उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमें भी बनाये गये थे । हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने न केवल किसानों को उनकी रुकी हुई पेमैंट दिलवाई बल्कि उन पर किये गये देशद्रोह के मुकदमों को भी वापिस करवाया ।

Mr. Speaker : Smt. Anita Yadav Ji, do you want to raise a point of order?

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । जब 1999-2001 के दौरान श्री चौटाला जी की सरकार थी उस समय के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं* * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Mr. Rajpal, please continue.

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें गन्ने और पॉपुलर का उत्पादन होता है । उसमें लोगों को बहुत भारी फायदा हुआ है। किसानों ने भी बहुत तरक्की की है। इसके लिए मैं अपनी सरकार के मुखिया की सराहना करता हूं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो 2010 में बाढ़ आई थी उससे पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ था जिससे पूरे प्रदेश में 5.08 लाख एकड़ क्षेत्र में विभिन्न फसलें खराब हुई थी । बाढ से निपटने के लिए हमारी सरकार ने किसानों को 257.60 करोड़ रुपये दिये हैं जो कि सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जिला यमुनानगर बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ । हमारे जिले में अगर बाढ़ के दौरान किसी की भी मृत्यु हुई तो सम्बंधित परिवारों को तुरन्त आवश्यक सहायता और मुआवज़ा दिया गया । यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम था । वहां पर अधिकारियों ने भी अच्छा काम किया। सरकार ने भी अच्छे निर्णय लिये । राहत मान-दण्डों में परिवर्तन करके मुआवज़ा राशि को भी बढ़ाया गया जो कि देश में सभी राज्यों से ज्यादा है । सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो सिंचाई के मामले में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने वाली दादुपुर-नलवी नहर का निर्माण पूर्ण होने वाला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना से यमुना नदी के फालतू पानी का प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए और भूमिगत जलस्तर को ऊपर उठाने के लिए होगा । इसके लिए भी मैं अपनी सरकार की सराहना करता हूं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारायणगढ़ में यह घोषणा की थी कि हथनी कुण्ड बैराज़ से लेकर बिलासपुर, सढौरा, नारायणगढ़ तक एक नहर बनाई जायेगी । मैं उम्मीद करता हूं कि इस नहर परियोजना पर भी बहुत जल्दी ही काम शुरू होगा ताकि सम्बंधित क्षेत्र को इस परियोजना से होने वाला लाभ जल्दी से जल्दी मिल सके क्योंकि इस परियोजना के शुरू होने से सढौरा, नारायणगढ़ और मुलाना क्षेत्र को बहुत अधिक लाभ होगा और हमारा भूमिगत जलस्तर भी ऊपर उठेगा । इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं । अगर मैं कृषि के उत्पादन की बात करूं तो पिछले 40 साल का इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो पायेंगे कि पिछले 40 साल के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने बिजली का कोई कारखाना नहीं लगाया था । अगर किसी ने लगाया था तो वह चौधरी बंसी लाल जी ने एक कारखाना लगाया था उनके अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी भी कोई बिजली का कारखाना हरियाणा प्रदेश में नहीं लगाया था । हमारी सरकार ने खेदड़, झाड़ली और यमुनानगर में 5000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का निर्णय लिया और इसमें से हमारे काफी कारखानों ने काम करना शुरू कर दिया है और जो बाकी रह गये हैं उम्मीद है कि वे भी जल्दी ही बिजली का उत्पादन शुरू कर देंगे । यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम है । आज विपक्ष के हमारे साथी यह कहते हैं कि हमारा राज्य आज बहुत पीछे है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में तरक्की की यह रफ्तार और भी गति पकड़ेगी । बिजली की अगर मैं और बात करूं तो 243 नये सब-स्टेशनों का निर्माण किया गया, 740 सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 3305 किलोमीटर लम्बी

[श्री राजपाल भूखड़ी]

लाईनों का नवीनीकरण किया गया है । यह भी एक सराहनीय कदम है । अगर मैं इस प्रदेश में जो गरीब लोग रहते हैं जो बी.पी.एल. के लोग हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो आज जो हमारे गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं हमारी सरकार उनको वजीफा देती है । वजीफा इसलिए देती है कि वे पढ़ना-लिखना सीखें तथा शिक्षा में गुणवत्ता आये और हर गरीब आदमी भी शिक्षा ग्रहण कर सके । स्पीकर सर, आने वाले समय में गरीब से गरीब और मजदूर का बच्चा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेगा ऐसी हमारी सरकार की नीतियां हैं । मैं हरियाणा सरकार की इन नीतियों की सराहना करता हूँ । इसी प्रकार से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2.36 लाख परिवारों में से 1.77 लाख परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली के कनैक्शन दिये गये हैं जो कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है । इसी प्रकार से मनरेगा स्कीम के तहत जो गरीब लोग काम करते हैं उनके लिए हमारी सरकार में उनको मिलने वाली दैनिक मजदूरी पूरे देश में सबसे ज्यादा 179 रुपये का प्रतिदिन भुगतान किया जाता है जो कि देश में सबसे ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरी अपने हलके की भी कुछ बातें मैं इस सदन के सामने रखना चाहूँगा । पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है आज प्रदेश में बड़े-बड़े कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि मेरे हल्के में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है इसलिए वहाँ पर एक सरकारी कॉलेज खोलने की कृपा करें । पिछले 32 वर्षों में पहली बार मेरे हल्के सढौरा से मुझे कांग्रेस का सदस्य चुनकर इस विधान सभा में पहुंचने का मौका मिला है । स्पीकर सर, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपके वचनों में भी ताकत है । जब चुनाव प्रचार के दौरान आप सढौरा आये थे तो आपने एक जनसभा में यह कहा था कि अबकि बार कांग्रेस का ही एम.एल.ए. बनेगा और कोई नहीं बनेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ । इसी प्रकार से शिक्षा की बात करें तो 2010 में हमारी सरकार ने 13 हजार से अधिक अध्यापकों की भर्ती की है क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते थे तो यही सुनने को मिलता था कि अध्यापक कम हैं । हमारे विपक्ष के साथी भी कहते थे कि स्कूलों में अध्यापक कम हैं । आज की सरकार की एक बहुत अच्छी सोच है तथा इसके अच्छे परिणाम आयेंगे । इसी प्रकार अगर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात की जाये तो हमारी सरकार ने बी.पी.एल. व विधवाओं के लिए विवाह शगुन योजना की राशि 15 हजार से बढ़ाकर 31 हजार रुपये की है । इस मामले में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि यह राशि थोड़ी देरी से मिलती है । इस बारे में हमारे विपक्ष के भी कुछ सदस्यों ने प्रार्थना की है कि यह राशि शादी से कम से कम 15 दिन पहले तो मिल ही जानी चाहिए और जो सर्टिफिकेट का मामला है उसमें भी कुछ रियायत दी जाये । चाहे वह सरपंच महोदय से सर्टिफाइड करवाया जाये, चाहे किसी तहसीलदार महोदय से करवाकर उसमें कुछ सुधार लाया जाये । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वैल्फेयर ऑफिसर्ज कम हैं । अम्बाला वाले के पास यमुनानगर का चार्ज है । इसी प्रकार से एक जिले वाले को दूसरे जिले का चार्ज दिया गया है । इसलिए इनकी भर्ती करने का काम किया जाये क्योंकि सोशल वैल्फेयर विभाग में काफी लोगों को काम पड़ता है । सर, मैं थोड़ी-सी बात यमुनानगर की सड़कों के बारे में भी

कहना चाहूँगा । स्पीकर सर, पिछली बार सदन में मैंने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपने यमुनानगर की सड़कों की बात रखी थी और हमारी सरकार ने तुरन्त फैसला लिया तथा हमारी प्रिंसिपल सैक्रेटरी बी.एण्ड आर. यमुनानगर गई और पूरा अमला चीफ इंजीनियर आदि यमुनानगर गये तथा यमुनानगर की सड़कों की रिपेयर के लिए 16 करोड़ रुपया दिया गया । अप्रैल-मई तक सड़कों के सारे छोटे-मोटे गड्ढे भर दिये गये लेकिन मैं एक रिक्वैस्ट और करना चाहता हूं। हमारे यहाँ की सड़कों में अभी भी कुछ कमी है, कुछ दिक्कतें हैं इसलिए उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब मैं राजमार्ग की बात कर रहा हूं । बड़शामी साहब ने भी इस बारे में चर्चा की थी । जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो करनाल से वाया लाडवा, इन्द्री और यमुनानगर जो रोड आती है यह यमुनानगर को दिल्ली से जोड़ती है। हमारी सरकार के समय में तो इस पर पोट होल भरे गए हैं पैच वर्क लगाया गया है लेकिन पिछली सरकारों में इस पर कोई काम नहीं हुआ था । अगर हमारी सरकार इस रोड को फोर लेन बनाती है तो इससे यमुनानगर से दिल्ली के सम्पर्क में बहुत बड़ा लाभ होगा । अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून व्यवस्था की बात करूंगा । हमारी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रशंसनीय है । अगर हम 1991 से लेकर 2005 के बीच की बात करें तो उस समय हमारे जैसे शरीफ लोगों के ऊपर भी मुकदमें दर्ज करवा दिए जाते थे । हमें पांच-पांच, छ:-छ: साल कोर्ट में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी थी लेकिन माननीय कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया है । उस समय 20-20 मोटर साईकिलों पर स्कूलों में जत्थे जाया करते थे, सड़कों पर चौकों पर जत्थे जाया करते थे इसलिए इनको लॉ एंड आर्डर की बात नहीं करनी चाहिए । अगर इनके समय में लॉ एंड आर्डर अच्छा रहता तब तो ये बात कर सकते थे । अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है पूरे प्रदेश में हर आदमी शांति से सो सकता है और अपने काम पर रात को या दिन को जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : अब बलबीर पाल शाह बोलेंगे ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी तरफ से भी किसी के बोलने की गुंजाइश है या नहीं ।

Mr. Speaker: Majra ji, from your side 14 members have already participated in the debate whereas on other side he is the 4th speaker.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी तरफ से किसी के बोलने की बात है तब तो हम यहां पर बैठें नहीं तो जाएं । आप उस तरफ से किसी को भी बुलवाएं लेकिन हमारी तरफ से भी आपको किसी को बुलवाना चाहिए । आप उनको 10 को बुलवाएं इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है । हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जबाव सुनेंगे और जबाव सुनकर अपनी सारी बात कहकर जाएंगे । आप बताएं कि आपने हमें बोलने का मौका देना है या नहीं । आप हमारी तरफ भी अपनी नजरे इनायत करें ।

Mr. Speaker : Majra ji, you are a learned man. You have great knowledge of economics. I want you to speak on Budget.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी के लीडर ने मुझे गवर्नर ऐड्रैस पर बोलने के लिए कहा है और आपने भी मुझे तीन बार कहा है कि मैं आपको इस पर बोलने का समय दूंगा।

Mr. Speaker : Mr. Majra ji, last time I was sitting there and your suggestions on budget were wonderful.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, नहीं सर, हमारी तरफ से बड़े लर्नड फ्रैंड बजट पर भी बोलेंगे लेकिन मैं तो गवर्नर ऐड्रैस पर ही बोलना चाहता था । मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं कि आप पुन: मेरे बारे में सोच लें । (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा रिक्वैस्ट माजरा जी ने करी है आप उनको बोलने का समय दे दें । आप चाहें तो टाईम और बढ़ा दें अपने घर की ही बात है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Arora ji, very senior members of your party have spoken in this House. Shri Om Prakash Chautala ji, spoken, Shri Ajay Singh Chautala and Shri Sher Singh Barshmi have already participated in the debate. (Interruption). You can not complaint. No-No. (Interruption).

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप मुझे बोलने का समय दे दें ।

Mr. Speaker : It is matter of personal choice for me that you will speak on budget. It is a very appreciation for you. Mr. Majra ji, you please give me list of your friends in the House.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपसे रिक्वैस्ट है कि मुझे बोलने का समय दें।

Mr. Speaker : I said that give me the list of your friends in the House. Next speaker, Mr. Balbir Pal Shah. (Interruption)

Shri Balbir Pal Shah : Hon'ble Speaker Sir, when the opposition benches were disturbing and speaking, I think, I was the only person who did not interfere. (Interruption)

Mr. Speaker: Hon'ble Members when I want you people to speak those who came to this House first time. Your Hon'ble leader told me that you should elect the speaker from the list. When I started doing that then objections are different. (Noise and interruption). Alright then Majra ji has spoken in this House for 10-15 years and those who have not spoken even once they should not speak if that is the intension of Mr. Majra?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा और कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी की भावनाएं आहत हों । (विघ्न) अगर कोई माननीय सदस्य लगातार 20 वर्षों से चुनकर आ रहे हों तो इसका मतलब यह तो नहीं कि उनके तर्जुबे का फायदा न उठाया जाए । मैं यह नहीं कहता कि नये मैम्बर्ज को न बुलाएं।

Mr. Speaker : Mr. Majra you are a very significant contributor. (विघ्न) हो तो ऐसा ही कुछ रहा है। मैं इधर से शुरू करता हूं तो आप उधर से कहते हैं । (विघ्न) I insist that you should speak on budget.

Shri Balbir Pal Shah : Speaker Sir, I am very thankful to you and the whole House.

श्री राम पाल माजरा : सर, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे बजट पर बोलने का अवसर देंगे। मैंने सोच रखा था कि मैं और हमारी पार्टी सी.एम. साहब का जवाब सुनकर जाएगी।

Mr. Speaker : आपने यह फैसला कैसे कर लिया कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा। आप दोनों फैसले स्वयं मत लो। I do not decide that I do not let you speak.

Shri Balbir Pal Shah (Panipat) : Speaker Sir, first of all, I congratulate you that you have been elected unanimously Speaker of this House. I never speak before I see the things are excellent, par excellent. In coming time, I think you will be the one whose name will be written in golden words. Secondly, I congratulate the leader of the House Ch. Bhupinder Singh Hooda and all the members who unanimously accepted you to grace this Chair. Generally, I speak a very little and I don't want to waste the time of the House but my opposition benches they have always tried to interfere. Speaker Sir, you have seen that I am sitting from the whole time from the starting of this session but I have never interfered and never spoken anything. They should learn the art of speaking and listening. One thing, I should say with very confidence that our leader Ch. Bhupinder Singh Hooda when took over as the Chief Minister of this August House and what he did in the last six years, I think that is also a history. He is a man of determination, confidence, commitment, intelligent, diligent, untiring and conviction also. Now, I have to say something about my town. I am not going beyond my city. There are so many problems in Panipat that I want to remind the Hon'ble Chief Minister. These problems should be solved immediately. Secondly, as far as previous budgets are concerned and this budget is concerned, I congratulate the legislators and our worthy Finance Minister specially, bureaucrats who have given a new dimension to the budget. (Noise and Interruption) Our Haryana Pradesh step by step, day by day is becoming idle for other States in India. I must contribute to those people, respect them who have given such a magnificent, efficient Government and I should say Ch. Birender Singh, former Finance Minister is not here but the implementation of the budget and our manifesto were unique and our leader, Ch. Bhupinder Singh Hooda has gone beyond that. He has done his works very honestly and given very certain Government. When a man works there is a saying that works create works. Now the expectation of the people is that they want more because they have seen past now, in future they want more. So, I request the Hon'ble Chief Minister and whole of his cabinet to give better results than the previous one. Now, I come to say something about my constituency. I have to say certain things for development. There was a promise given to the Panipat people that on GT road fly-over, there will be a parking place that has not created so far. Secondly, Drain No.1 which is very important in Panipat because it has passed throughout way and the open drain should be opened and re-

[Smt. Balbir Pal Shah]

constructed. Thirdly, one another assurance was given by the Hon'ble Chief Minister that canal based water supply project for Panipat will be taken in hand. These are being delayed. I do not know what is the reason? Again, I will also remind the Hon'ble Chief Minister that construction of ROB at Jatal Railway crossing that should be taken in hand as early as possible because what I feel is that traffic in Panipat is growing in such a way that it is very difficult to control for the people of Panipat. They have not been enjoying this opportunity. The people come from outside they prefer, have to go to Karnal, they are happy. But living at Panipat they are not happy. I must tell the Hon'ble Chief Minister through yourgoodself. Then there is a small problem in railway phatak, the money has been deposited but no initiataive have been taken by the Central Railway and it is still pending. So, I will request the Hon'ble Chief Minister to intervene and this project may be taken into hand as early as possible. Then there is solid waste management - the wastage in Panipat and the sewerage in Panipat. All the sewerage has been blocked and when drain comes, Mr. Jain knows better that what happened in his house.

Mr. Speaker : What happened in his house?

Shri Balbir Pal Shah : The sewerage system should be properly maintained and I thank Ch. Randeep Singh Surjewala, he has cooperated very well but still I find that the solution has not solved up due to some technical problems. Again the city is growing the need of the hour.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, since the Hon'ble Chief Minister has to reply after the last speech on the Governor's Address, the time of the House is to be furthermore extended. Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for half an hour?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting of the House is extended for half an hour.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

Shri Balbir Pal Shah : Sir, the another problem with Panipat is, if Mr. Jain would hear this, he would have complimented me, that storm water sewerage system should be adopted in Panipat channel and it should be made so that the house of Minister should not sink in the water. As the Panipat city is growing, one thing I mentioned that Panipat is earning thousands of crores of foreign currency in exports but the development made

in Panipat so far is not sufficient. I won't blame previous Governments but I can say certainly that Ch. Bhupinder Singh Hooda has tried his best and given huge funds to modernize and to clean the city and he has also given an assurance that Panipat will be not less than Gurgaon. I give my thanks to the Hon'ble Chief Minister as the growth of the Panipat is coming, the population has expanded and it will be raised, I should say, unlimited. Transport Nagar was made by Chautala Government and there was only 25 plots for the transporters. But at least 150 more plots should be given to the transporters so that the hazard in the city should not be created because they have made their offices on small roads and due to that some time traffic is blocked. As far as the existing system of sewerage treatment plant is concerned, this was announced, I think in Ch. Bhajan Lal's Government in 1994 under Yamuna Action Plan. That also needs the augmentation of the sewerage plant and there is a demand for two more plants at Barsat Road and Industrial area that is the prime requirement. I would request the Hon'ble Chief Minister that he should take up it on priority. Again the Panipat has been declared as a Corporation. I would only request that 10 crores of rupees' special grant be given to the Panipat in addition to the previous grant given and I conclude my speech. I think for this time it is sufficient but next time you will allow me to speak for more time.

Mr. Speaker : Surely. Promise is a promise.

Shri Balbir Pal Shah : Thank you, Sir.

Mr. Speaker : Mr. Bansal, I know you want to speak but can you speak on the Budget? There is a provision to send your speech in writing. You are a senior advocate and you can send your speech in writing.

Shri Devender Kumar Bansal : Sir, I want to narrate the things if you give me a little time.

Mr. Speaker : Alright.

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल (पंचकूला) : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं । इसके साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने 6 सालों के मुख्यमंत्रित्वकाल में हरियाणा को हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो प्रगतिशील बनाया है। इसी वजह से आज हरियाणा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नम्बर एक प्रांत बन गया है । मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । खेलों के अन्दर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से हरियाणा का नाम न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में स्थापित किया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी पर डिपैंड करते हैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों कदम हमारी खेती को और ज्यादा प्रोग्रैसिव बनाने के लिए उठाये

[श्री देवेन्द्र कुमार बंसल]

हैं । इसके अन्दर स्वायल हैल्थ कार्ड भी इश्यू हुए हैं और करीब 10 लाख लोगों को फायदा हुआ। इससे हमारी scientific use of fertilizers का जो प्रोसैस प्रमोट होगा उससे हमारी कृषि को भी बहुत लाभ पहुंचेगा । गन्ने के लिए हमारी सरकार ने अगेती फसल के लिए 220 रुपये प्रति क्विंटल, मध्यम फसल के लिए 215 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती फसल के लिए 210 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मूल्य दिया जो कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है । इसके साथ-साथ जो हमारे किसानों की मार्किट सरप्लस लैंड थी उसको भी मुख्यमंत्री जी ने रिलीज करने का प्रावधान किया जिससे लगभग 1.60 लाख एकड़ लैंड रिलीज़ हुई और इससे करीब 24 हज़ार किसानों को लाभ पहुंचा। इसके लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और उनकी सराहना भी करते हैं । ग्रामीण विकास के तहत महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अन्दर जो 100-100 गज के प्लॉट्स दिये गये हैं उससे करीब 3.40 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है । इसी प्रकार से इंदिरा विकास योजना के तहत गरीब लोगों को मकानों का भी आबंटन किया गया जिसके अन्दर 10 हज़ार मकान बनाकर अलॉट किये जा चुके हैं और 10 हज़ार मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब हम तीन महीने पहले पंचकूला में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत लोगों को प्लॉट्स का कब्ज़ा दिलवाने गये तो उस समय अनेकों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे उन्होंने कहा कि उन्होंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि उन जैसे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट्स पंचकूला जैसे शहर में जहां पर इस प्रकार के एक प्लॉट की कीमत 30-30 लाख से लेकर 40-40 लाख तक है, सरकार की तरफ से नि:शुल्क दिये जायेंगे। इससे उन लोगों में कितनी खुशी थी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था ।

Mr. Speaker : I would like to know from the Leader of the House is this plot allotment scheme unique to this State in the Country or not? Is it happening anywhere else?

Shri Devender Kumar Bansal : Sir, it is only in Haryana State. इसी प्रकार से इंदिरा आवास योजना के तहत तकरीबन 10 हज़ार मकानों का निर्माण हो चुका है और 10 हज़ार मकान का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.00 करोड़ रुपये दिये जिसमें से हम आधी रकम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और वह काम भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जायेगा । इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं ।

Mr. Speaker: Thank you. You have a big draft to read and I think you should give it to me. Members, Hon'ble Chief Minister has to go for a function after this for International Women's Day. So, before he speaks, Mr. Majra will be the last speaker on the Governor's Address.

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जब पहली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे और हमारे वित्त मंत्री जी बजट का जवाब दे रहे थे तो हमारे मुख्य मंत्री जी हौंसले से लबरेज थे और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो लाईनों में जवाब दिया था वह मैंने उसी दिन लिखा था । इन्होंने कहा था कि :-

जिन्दगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है ।
अभी तो नापी है मुट्ठीभर जमीन हमने,
आगे सारा आस्मां बाकी है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो-चार मुख्य बातों पर ही बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसके बाद मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है । अध्यक्ष महोदय, जब किसी प्रदेश की स्थिति का पता लगाना हो तो उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पता लगायें क्योंकि अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसका इंडिकेटर अच्छा है । अगर उसकी शिक्षा की स्थिति अच्छी है तो उसका इंडिकेटर अच्छा है और अगर उसकी हैल्थ की स्थिति अच्छी है तो इंडिकेटर अच्छा है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वे 12.97 लाख हैं और हरियाणा प्रदेश में यह जो यूनिट है इसके ऊपर 10 प्वाइंट वाले 57.39 लाख हैं और कुल हरियाणा प्रदेश के राशन कार्ड में दर्ज हैं वे 25643305 व्यक्ति हैं यानि हरियाणा प्रदेश की कुल आबादी की 20 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है । इसके बावजूद भी सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय सबसे ज्यादा है । ये प्रतिव्यक्ति आय कहीं से निकालें लेकिन बी.पी.एल. कार्ड के हिसाब से हरियाणा की 20 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रह रही है । ये इंडिकेटर यह कह रहा है कि हरियाणा के लोगों की आर्थिक स्थिति सुखद नहीं है । इसी प्रकार से शिक्षा के बारे में कहा जाता है लेकिन इंडिया ऐजूकेशन इन्डैक्स रैंक प्राइमरी और उपर के मामले में 2008-09 में हरियाणा चौथे स्थान पर था और 2009-10 में यह11वें स्थान पर आ गया है यानि 7 रैंक नीचे चला गया है। इससे साफ लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, एक छोटी बात और है कि केवल प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2009 में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की थी और इस मिशन के लिए करनाल जिले को चुना गया था तथा धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई थी। इसके लिये 2011 तक 1 करोड़ पुरुषों और 6 करोड़ महिलाओं को शिक्षित करने का उद्देश्य रखा गया था । स्पीकर सर, करनाल जिले को ही टेकअप नहीं किया गया बल्कि इसके ऊपर 11 करोड़ रुपये की राशि सारे हरियाणा की मंजूर की गई और जो एक जिले को सैम्पल के तौर पर लिया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि उसमें एक भी आदमी या औरत शिक्षित नहीं किये गये और उस मिशन की यह स्थिति है । प्रदेश में सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2000 से लेकर 2005 की अवधि में 20 रैडक्रॉस सोसायटीज हैं और उनमें 2.86 करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च कर दिये जो इन सोसायटीज की परिधि में ही नहीं थे । यह कैग की रिपोर्ट है । स्पीकर सर, कुछ लोन ले लिया गया । एस.डी.एम. और सिटी मजिस्ट्रेट के लिए ए.सी. गाड़ियाँ तथा टेलीफोन खरीद लिये । अध्यक्ष महोदय, रैड क्रॉस सोसायटी गरीब आदमियों की मदद करने के लिए होती हैं, बाढ़ पीड़ितों इत्यादि के लिए ये खर्च

[श्री रामपाल माजरा]

करती हैं । रिपोर्ट तो यहाँ तक भी आई है कि उसमें से किसी को लोन दे दिया और न ही तो उसका ब्याज आया है और न ही लोन वापिस आया है । इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जहाँ तक स्कूल खोलने का प्रश्न है हमारे गवर्नर एड्रैस में कहा गया है कि किसान मॉडल स्कूल खोलेंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी कहूँगा कि सैम्पल के तौर पर खोलिए अदरवाइज ऐजूसेट की तरह स्थिति पैदा न हो जाए । पिछड़े हुए 36 ब्लाक में माडल स्कूल सैंटर गवर्नमैंट से मंजूर हुए है इसलिए उनको भी लोकेशनवाइज देख लें । कहीं ऐसा न हो कि वे इसी तरह किसी भी जगह खोल दिए जाएं और वह वायबल न हों ।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, you have to conclude because you have already taken 7 minutes to speak.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, फारैस्ट का एरिया कैसे बढ़ेगा ? आपके सामने ही संजीव चतुर्वेदी, डी.एफ.ओ. जैसे बहुत ईमानदार अफसर का मामला रहा है । उनको प्रैशराइज किया गया कि आप प्राईवेट लैण्ड के अंदर हर्बल पार्क बनाए लेकिन उन्होंने जबाव दे दिया । उसके बाद मामला आपके सामने है कि किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया । प्रैसीडैन्ट ऑफ इंडिया ने उनको रिलीफ दिया । उन्होंने तो सरकार का पैसा बचाने के लिए यह कहा था कि मैं प्राईवेट जमीन पर हर्बल पार्क नहीं बनाऊंगा । वे शायद इस सदन के सदस्य भी हैं जिन्होंने अपनी जमीन पर हर्बल पार्क बनाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं इस प्रकार से हर्बल पार्क नहीं बनाऊंगा । स्पीकर सर, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन की कैसी स्थिति है ? रोडवेज का किराया बढ़ाया गया लेकिन किराया बढ़ाने के बावजूद भी आज 220 करोड़ रुपये के घाटे में रोडवेज है ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इनका किस बात के लिए प्वायंट ऑफ आर्डर है । मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया है ।

Mr. Speaker : Are you withdrawing your allegation, Mr. Majra?

श्री रामपाल माजरा : मैंने विदड्रा नहीं किया है ।

Mr. Speaker : Since you cannot name anybody, you cannot talk.

श्री रामपाल माजरा : फिर तो जो प्वायंट आफ आर्डर दे रहे हैं उसकी दाढ़ी में तिनका है ।

Shri Randeep Singh Surjewala : I may be permitted to explain.

Mr. Speaker : I have permitted him to clarify, Mr. Majra. In future if you want to level any allegation on any member then please tell me so that I know what are you talking.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझसे नाम पूछना ही चाहते हैं तो क्या आपने अखबार नहीं पढ़े होंगे ? क्या आपने प्रैजीडैन्ट ऑफ इंडिया द्वारा कांस्टीच्यूट की गयी उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी जिसके अंदर यह कहा गया है कि संजीव चतुर्वेदी एक अच्छे अधिकारी हैं ? अब मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि श्री गिल्लाखेड़ा ने अपनी जमीन पर हर्बल पार्क बनाने के लिए उन पर दबाव दिया था।

Mr. Speaker : Shri Prahlad Singh Gillakhera is coming up with point of order. I allow him to speak.

श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया । अभी हमारे आदरणीय साथी ने हर्बल पार्क बनाने के लिए कहा है। आप सब जानते हैं कि गिल्लाखेड़ा के अंदर हर्बल पार्क बनाया गया। आज यह संजीव चतुर्वेदी की बात करते हैं लेकिन उनका रिकार्ड भी इन सबको पता है कि उस व्यक्ति की हिस्ट्री क्या है । उसकी हिस्ट्री भी अखबारों में आयी हैं । सारी बातें रिकार्ड में हैं । चूंकि वह पार्क गिल्लाखेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है इसलिए मैं क्लैरीफाई करना चाहता हूं कि उसके अंदर कोई इररैगुलरटी नहीं हुई है । आज भी सारी की सारी बातें आन रिकार्ड हैं । मैं चेलैंज करता हूं कि वह हर्बल पार्क हरियाणा के सबसे अच्छे हर्बल पार्क्स में से एक है और पंचायत की लैंड में है । उसमें सारी कानूनी कार्यवाही पूरी की गयी हैं । गांव के लोग उस वक्त की हुड्डा सरकार के और फारैस्ट मिनिस्टर श्रीमती चौधरी के इसके लिए बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने उस गांव में एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया । मैं सारे हाउस के अंदर बड़े दावे के साथ कहता हूं कि एक कमेटी बनाएं जो कम से कम वहां पर जाकर यह देख कर आए कि जो वहां पर हर्बल पार्क बना है वह किस तरह से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है और अब वह किस स्थिति में है । आज उस जमीन पर अधिकार फारैस्ट डिपार्टमैंट का है, हरियाणा सरकार का है । पंचायत ने भी लिखित में लिखकर दिया है । सैक्शन 38 के अंदर वह जमीन फारैस्ट डिपार्टमैंट को दी हुई है and now it is the property of Forest Department and they are maintaining it.

Mr. Speaker : You mean to say the Forest Department owns it now.

Shri Prahlad Singh Gillakhera : Now, it is the property of Forest Department.

Mr. Speaker : Are they maintaining it ?

Shri Prahlad Singh Gillakhera : Yes Sir.

Excise & Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir, I would like to clarify on this as it relates to the time when I was a Forest Minister.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, इनकी तो इसमें कोई बात नहीं है । इसका मतलब इन्होंने सिफारिश की होगी। (विघ्न) क्या इस पर इनको प्वायंट ऑफ आर्डर मिल सकता है ?

Smt. Kiran Chaudhary : Since the name of the Minister has also been mentioned. So, I have a right to put my viewpoint on the floor of the House. I want your ruling here. (Interruption)

Mr. Speaker : You want to hear my ruling. (Interruption)

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, I would like to clarify what Shri Majra has said and it is my right to clarify.

Mr. Speaker : He is not blaming you. He says he has nothing said against a Minister.

Smt. Kiran Chaudhary: It is not a question to say Sir, I just want to place certain facts on the floor of this august House. I just want to put certain facts to it on record.

Mr. Speaker : But he is not blaming you.

Smt. Kiran Chaudhary: I never said, 'He is blaming me'. But I want to put certain facts on the floor of this House to put it on record.

Mr. Speaker : Alright, my ruling is since Mr. Gillakhera has mentioned your name. You may give an explanation.

Smt. Kiran Chaudhary : Thank you, Sir, I would like to be very specific about it. This is a part of the pilot project which was done by the Forest Department. As you know, Sir, Haryana has a forest area cover of 7.62 hectares. So, we wanted to increase the forest cover. We are in agrarian State and being an agrarian State it is very difficult for more forest to be brought in. So, different kinds of things were brought in like trees outside forests and herbal parks because there are certain things which were being completely finished of.

Mr. Speaker : Is there any herbal park anywhere?

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, one herbal park in each district and there is 22 herbal parks in whole Haryana.

Mr. Speaker : I heard there is a herbal park in the name of Chaudhary Devi Lal. Is it right ?

Smt. Kiran Chaudhary : Yes, Sir. About the Gillakhera Herbal Park, people wanted a herbal park to be established on that land. We found out that land there did not belong to the Forest Department but it was Shamlat Deh land and the Central Empowered Committee of the Supreme Court has ruled that it is Shamlat Deh Land. But the Forest Department did work on that land as a result of which today it is one of the best herbal parks. Sir, I would like to put it on record that this is the first instance where something has been done but the entire facts have been twisted in such a wrong manner. This land has been given to the Forest Department in perpetuity. There is no loss of any kind. We are trying to increase the Forest cover but the people here come out to misrepresent the facts. This is what the actual thing is being brought forward.

Mr. Speaker : I know, it is beautiful Herbal Park. This is my observation.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था । गिल्लाखेड़ा चौधरी ख्याली राम जी का गांव है और वे इनके परदादा थे । ये इसके मालिक थे, इनकी जमीन थी । (विघ्न) ये वैसे ही खड़े हो गए ।

श्रीमती किरण चौधरी : बात ये है कि it is a Shamlat Deh Land and that can be used for the purpose of Forest.

श्री राम पाल माजरा : शामलात देह लैंड एक व्यक्ति के परपज के लिए यूज नहीं की जा सकती। कॉमन परपज के लिए यूज की जा सकती है।

Mr. Speaker : I have been a lawyer for the last 30 years. I know this is a Shamlat Deh Land.

श्री राम पाल माजरा : हर्बल पार्क किसका है ?

Mr. Speaker : As I have been a lawyer for 30 years, I know that Shamlat Land belongs to Panchayat and if it has been transferred to Forest Department, it is open to everybody and I think if it is in perpetuity that Forest Department is the owner and now Mr. Majra you enlighten me more on that.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, 2007 में पार्क बना और 2009 में लैंड ट्रांसफर हो गई। स्पीकर सर, पार्क पहले बनता है फिर कॉमन पर्पज के लिए ट्रांसफर हो जाती है।

Mr. Speaker : It is good if a developed park is transferred. Instead of transferring just a land you are transferring a park, that is good.

श्री रामपाल माजरा : इस बीच में यह हुआ कि झगड़ा पड़ गया और इन्होंने जवाब दे दिया और यह पार्क बीच में आ गया । दूसरा ये यह कहते हैं कि फोरेस्ट की हम बहुत भारी कवरेज बढ़ा रहे हैं वन का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं । इनका झज्जर में पैसा आया था उसका मिस यूज हो गया, फिर पैसा आया हिसार में उसका मिस यूज हो गया इन्क्वायरी चल रही है । स्पीकर सर, इतना ही नहीं मैं आपके ध्यान में इस बात को भी लाना चाहता हूं कि इस सरकार ने एच.सी.एस. अधिकारियों को मनोनीत करना था उनकी उम्र 55 साल कर दी गई जब कि 55 साल तो रिटायरमेंट की उम्र होती है उसके बाद तो तीन साल की एक्सटैंशन दी जाती है ।

Mr. Speaker : Is it the part of the Governor's Address.

श्री रामपाल माजरा : जो एच.सी.एस. ज्यूडिशिएल एग्जीक्यूटिव अधिकारियों की सिलैक्शन हुई वह भी अण्डर स्कैनर है ।

Mr. Speaker : That is with the Court. No comments on that.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, श्री रामपाल माजरा को बोलते हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और इन्होंने गर्वनर एड्रैस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

Mr. Speaker : Restrict yourself Mr. Majra.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, चार ड्रग्स इन्सपैक्टर्ज की भर्ती की गई जिनमें से दो के सर्टीफिकेट्स फर्जी पाए गए । इसी प्रकार 200 लैब टैक्नीशियंज की नियुक्तियां की गई जिनमें से 43 के प्रमाण पत्र फाल्स पाये गये । इसी प्रकार से एम.पी.एच. डब्ल्यू. की 700 की नियुक्तियां की गई जिनमें से 39 के प्रमाण पत्र फाल्स पाये गये और उनको लगातार अपॉइंटमैंट दी जा रही है । स्टाफ नर्स की भर्ती होनी थी सर्विस रूल्ज की प्रवाह न करते हुए सोनू कौशिक पुत्र रवि, रविदत्त पुत्र राजा, पी.एच.सी. नंगल चौधरी में और बढ़वाल में स्टाफ नर्स जैण्ट्स को लगा दिया और ये कहते हैं कि आज इण्टरनेशनल वुमैन डे है ।

Education Minister (Smt. Geeta Bhukal Matanhale) : Speaker Sir, Staff Nurse can be the man also. स्टाफ नर्स मेल भी हो सकता है ।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने नाम दिए हैं उनके बारे में पता करके जवाब दे देंगे ।

Mr. Speaker : Mr. Majra, I have heard of Male Nurses also.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, 400 करोड़ रुपया उस नहर पर बहा दिया गया और उसकी कोई मन्जूरी नहीं ली गई ।

Mr. Speaker : Mr. Majra, your time is over. (Interruption) Mr. Majra, please resume your seat. (Interruption) I have already given you more than 10 minutes. I would not like you walk out today. (Interruption) Your 10 minutes are over.

श्री रामपाल माजरा: नरेगा में अम्बाला में 25 करोड़ रुपये खा गये दो ए.डी.सीज. ने रिपोर्ट दी है वहां पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया । अगर आप मुझे बोलने का समय नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूं । (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Hon'ble Chief Minister will give his reply please. Hon'ble Chief Minister Sahib, you may please begin with a dinner invitation please.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting be extended for half an hour.

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : OK, the time of the Sitting is extended for half an hour.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, 4 मार्च, 2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा उनका धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । उसके लिए हम उनके आभारी हैं । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में अनेक बातों का उल्लेख किया है और उन बातों का उल्लेख किया है जिससे प्रदेश के लोगों की और आम आदमी की प्रगति हुई है, प्रदेश की प्रगति हुई है और उन्नति हुई है । अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश में उन्नति के नाम पर जाना गया है । सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और निर्णयों की इस अभिभाषण में चर्चा की गई है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी । मैंने सभी साथियों की बात गौर से सुनी । ओम प्रकाश चौटाला विपक्ष के नेता और हमारे दूसरे साथियों ने जो जो बातें कही हैं मैंने उनको गौर से सुना है । ओम प्रकाश चौटाला का लम्बा राजनीतिक तजुर्बा है और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मुझे उम्मीद थी कि वे कोई अच्छे सुझाव देंगें जो प्रदेश के हित में होंगें और प्रदेश के विकास के हक में होंगें । वे काफी समय तक बोलते रहे । जिस प्रकार से उन्होंने बेबुनियादी बातें कही उससे मुझे निराशा हुई । मैं उम्मीद करता था कि ओम प्रकाश चौटाला जी कोई रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव सुझाव देंगें ताकि प्रदेश का फायदा होगा। मैं इस बात को भली-भांति समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें जरूरी होती हैं । विपक्ष में हम भी रहे हैं । मैं भी विपक्ष का नेता रहा हूं । ओम प्रकाश चौटाला और बी.जे.पी. की भी सरकार रही है । बहुत से रचनात्मक सुझाव उस समय हमने दिए । विपक्ष का काम विरोध करना है, ऐसी नीति कभी भी हमारी नहीं रही । अध्यक्ष महोदय, मैं कल से देख रहा हूं कि केवल बेबुनियादी बातों की चर्चा इन्होंने की । उनका इस प्रकार की बातें करना केवल एक चीज को दर्शाता है कि वे प्रैस में बने रहें । उन्हें इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिए। बेबुनियादी मुद्दों को कहकर ज्यादा दिन तक प्रैस में भी नहीं बना रहा जा सकता । मुझे उम्मीद है कि ये आगे रचनात्मक सुझाव देंगें । उन्होंने कई मुद्दे उठाए । उन्होंने फाइनैंशियल मैनेजमैंट की बात कही । ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा और हमारे बी.जे.पी. के अध्यक्ष कृष्ण पाल गुर्जर जी ने भी कहा है और रामपाल माजरा जी ने भी कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखा जाता है । इन्होंने चर्चा की कि आज 45 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हरियाणा प्रदेश पर है । मैं कुछ आंकड़े सदन के पटल पर रखना चाहता हूं उसके बाद आप चर्चा करें कि किसी स्टेट की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होती है और कैसे कमजोर होती है । 2000-2001 में राज्य पर 13851 करोड़ रुपये का कर्जा था । इनकी सरकार यानि जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, 2004-05 में यह कर्जा बढ़कर 23319 करोड़ हो गया यानि 68 परसैंट बढ़ौतरी हुई । इसके मुकाबले में 2005-06 में जब हमारी सरकार आई तो यह कर्जा 26268 करोड़ था । वर्ष 2009-10 में यह कर्जा बढ़कर 39230 करोड़ हो गया जो कि 49 परसैंट बढ़ौतरी है । इनकी सरकार में 68 परसैंट वृद्धि हुई और हमारे समय में 49 परसैंट वृद्धि हुई । अध्यक्ष महोदय, 2010-11 के बजट ऐस्टीमेट्स के मुताबिक 44515 करोड़ रुपये का कर्जा है जोकि स्टेट डोमैस्टिक प्रोडक्ट का 17 परसैंट है ।

16.00 बजे

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

13 वें फाइनांस कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक 22.4 परसैंट तक आप कर्जा ले सकते हैं जबकि हमारा 17 परसैंट है । अध्यक्ष महोदय, मैं कृष्ण पाल गुर्जर जी को बताना चाहता हूं कि गुजरात में यह कर्जा स्टेट डोमैस्टिक प्रोडक्ट का 34 परसैंट है जबकि हमारे प्रदेश का 17 परसैंट है । 13वें फाइनांस कमीशन में 22.4 परसैंट तक की इजाजत है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000-05 के दौरान इनकी सरकार के समय में कुल 26 हजार 73 करोड़ रुपये का कर्जा लिया गया जबकि हमारी सरकार के समय में वर्ष 2005-10 के दौरान 18548 करोड़ रुपये कर्जा लिया जो कि इनके मुकाबले 7525 करोड़ रुपये कम है । इन्होंने जो 26 हजार 73 करोड़ रुपये कर्जा उठाया उस पर केवल 8308 करोड़ रुपये कैपीटल एक्सपैंडीचर किया और हमने जो वर्ष 2005-10 के दौरान 18548 करोड़ रुपये कर्जा उठाया उस पर हमने 17125 करोड़ रुपये कैपीटल एक्सपैंडीचर किया है । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास की गति का पता जो बजट होता है उसके प्लांड एक्सपैंडीचर से आंका जाता है । इन्होंने वर्ष 2004-05 के दौरान प्लांड एक्सपैंडीचर 2108 करोड़ रूपये किया जो कि अब वर्ष 2011-12 में 13200 करोड़ रुपये हो गया है । इसका मतलब हमारा प्लांड एक्सपैंडीचर 6 गुणा ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति तब है जब हमने 2006 में छठे पे कमीशन का पूरा खर्चा वहन किया है । इसके अलावा जिस समय हमने सत्ता संभाली थी उस समय प्रदेश का प्लांड बजट 2250 करोड़ रुपये था जो हमारे प्लानिंग कमीशन में प्लांन साईज 20358 करोड़ रुपये है । अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े देने के बाद शायद यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि राज्य की वित्तीय स्थिति कब मजबूत हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण नीति के बारे में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने, रामपाल माजरा जी ने, कृष्णपाल गुर्जर जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने बार-बार कहा है । मैं यह तथ्य की बात बता रहा हूं कि इनके समय में वर्ष 1999 से 2005 के दौरान जब चौटाला साहब और भाजपा की सांझी सरकार थी उस समय कृष्णपाल जी इधर बैठते थे तब किसानों की जो भी भूमि ऐक्वायर की गई उसका औसतन मुआवजा 5 लाख रूपये प्रति एकड़ बनता है लेकिन हमारे समय में जो भी भूमि ऐक्वायर हुई है उसकी औसत 19.80 लाख रुपये प्रति एकड़ बनती है।

Mr. Speaker : Hon'ble Chief Minister are you talking about the state average?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Yes, State average.

Mr. Speaker : But in Gannuar Constituency it was less than Rs. 2 lacs.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : जनाब मैं उसी पर आ रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रोजैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिससे पता चल जायेगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में किस तरह से किसानों को बरबादी का मुकाबला करना पड़ा और किस तरह से किसानों को लूटा गया । के.एम.पी. बनाने का फैसला हमारे से पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने किया था । ये दस्तावेज हमारे पास हैं । के.एम.पी. के लिए 3450 एकड़ जमीन एक्वायर हुई है और the

Council of Ministers in Cabinet Meeting held on 7.9.2004 has taken following decisions in this matter. The proposal was approved with following modification that the Cost of land acquisition is expected Rs.170 to Rs.180 crore for 3450 acres of land. इसका मतलब 3450 एकड़ ज़मीन की जो ऐक्चुअल कॉस्ट आंकी गई थी वह 170 और 180 करोड़ रुपये के बीच में आंकी गई । इसके बाद जो दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें इनके सभी ऑफिसर गये उस ज़मीन की कीमत 167 करोड़ रूपये आंकी गई । इसके बाद हमारी सरकार आई । उतनी ही ज़मीन और उतने ही किसान लेकिन हमने यह फैसला कर दिया कि जो फ्लोर रेट पूरे हरियाणा में है हम उससे कम यह ज़मीन हरगिज नहीं देंगे । इस प्रोजैक्ट में 50 प्रतिशत दिल्ली सरकार का शेयर था, 25 प्रतिशत हरियाणा का शेयर था और 25 प्रतिशत ही उत्तर प्रदेश सरकार का शेयर था । उस समय हमने यह कह दिया कि जो हमारा फ्लोर रेट है उससे कम भाव में हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे । उस समय दिल्ली में भी इस बात के लिए काफी दबाव पड़ा । हमने कहा कि हम अपने किसानों को इस प्रकार से लुटने नहीं देंगे । स्पीकर सर, इस प्रकार से हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप उतने ही किसानों को उतनी ही ज़मीन जिसका विपक्ष के साथियों के समय में 167 करोड़ रुपये कम्पनसेशन दिया जा रहा था उसी ज़मीन के लिए हमारी सरकार ने 721 करोड़ 13 लाख रुपये दिये। इस प्रकार से एक प्रोजैक्ट में 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का लाभ किसानों को हुआ। इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदा हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के किसानों के हितों के लिए कितनी सजग है और कितनी किसान हितैषी है। अभी कृष्ण पाल गुर्जर जी कह रहे थे, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछले सत्र के दौरान मैंने 07 सितम्बर, 2010 को कहा था और मैं आज भी इस बात की घोषणा करता हूं कि सदन के किसी भी सदस्य द्वारा जो भी सुझाव किसानों के हित में दिया जायेगा मैं उसका स्वागत करूंगा क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के हित मुझे सर्वप्रिय हैं । किसानों के हित की दिशा में अपनी नीतियों और योजनाओं में पहले भी हमने इम्प्रूवमैंट की है और आगे भी करेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

Shri Bhupinder Singh Hooda : I am not yielding.

Mr. Speaker : Mr. Abhay Chautala, have you sought my permission? No. No interruption please. Let him continue please. Hon'ble Chief Minister please continue.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : किसानों के हित में अगर कोई भी अच्छा सुझाव होगा उसको हम वैलकम करेंगे क्योंकि हम सही अर्थों में किसान के हितैषी हैं । मैंने पिछले सैशन में भी कहा था कि हम आगे भी इसमें और इम्प्रूवमैंट करेंगे । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जो बेहतरीन ऐक्वीजीशन नीति लेकर आये हैं वह केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन नीति है और उसमें हमने फ्लोर रेट 22 लाख से लेकर 72 लाख रुपये तक फिक्स किया है ।

Mr. Speaker : Abhey ji, please don't disturb the proceedings of the House.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हमने फ्लोर रेट फिक्स किया है ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि please don't make any running commentary. You can't make any observation. Please resume your seat.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हरियाणा सरकार के मंत्री यह कह रहे हैं कि सरकार की यह पॉलिसी गलत है ।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Chief Minister, please continue. Ram Pal Majra please take your seat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, एक बात और मैं सदन के पटल पर कहना चाहता हूं कि अगर मेरा कोई भी मंत्री हमारी इस पॉलिसी को गलत कह दे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । विपक्ष के साथी ऐसी बातें कहकर पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं । मेरे किसी भी मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, मैंने हमेशा यह कहा है कि हमारी यह पॉलिसी बहुत बढ़िया है और आगे मैंने यह कहा है कि इसमें और सुधार की भी गुंजाईश है । यही बात सी.एम. साहब भी कह रहे हैं ।

Mr. Speaker : Chief Minister, please continue. Ram Pal Majra please take your seat.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात तो पहले ही कह रहा हूं कि कैप्टन अजय सिंह तो मेरे मंत्री हैं, मेरे साथी हैं, मैं तो यह कहने लग रहा हूं कि अगर विपक्ष की तरफ से भी कोई बेहतर सुझाव आयेगा तो मैं उसको भी अमल में लाने का पूरा प्रयास करूंगा । सुझाव देना मेरे साथियों का कर्त्तव्य बनता है । I always welcome good suggestions in the interest of farmers because I am son of a farmer.

Mr. Speaker : Chautala ji, you can give good suggestion if you have one, otherwise you can't. Please don't interrupt. Mr. Chief Minister please continue.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं । विपक्ष के साथी अपने आप फैसला कर सकते हैं और उन किसानों से भी इस बारे में पूछ सकते हैं । इसके साथ-साथ हमने 33 वर्ष तक के लिए 21 हज़ार रुपये प्रति वर्ष एन्युटी के तौर पर भी रखे है जिसमें

750 रूपये प्रति वर्ष का इन्क्रीज भी रखा है। यह स्टेट में पहली बार हुआ है । मैं वे प्वायंट्स बता रहा हूं जिनका हमने प्रावधान किया है । इस बारे में कृष्ण पाल गुर्जर जी बात कर रहे थे । मैं उन्हें यह सलाह देना चाहता हूं कि वे पॉलिसी को पहले अच्छी तरह पढ़ लिया करें। इसके साथ ही हम देश में पहली बार जमीन की कीमत पर 30 प्रतिशत के बराबर किसानों को दो लिटीगेशन अलाऊंसिज भी दे रहे हैं । ज़मीन के प्रत्येक मालिक को रियायती प्लॉट देने की भी सरकार की योजना है । इसके साथ ही कमर्शियल साईट अथवा इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स देने का भी हमारी पॉलिसी में प्रावधान है । सरकारी स्कीमों के लिए जिस किसान की 70 प्रतिशत से ज्यादा जमीन या कम से कम 2 एकड़ जमीन ऐक्वायर होगी उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जायेगी । ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या जिनकी जमीन एक्वायर हो गई उनको भी नौकरी देंगे ।

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है । आपके जिस नेता की आप खुद ही पीठ थपथपा कर प्रशंसा कर रहे हैं जब ये गाँवों के किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो उनको मुआवजा दे रहे हैं लेकिन 50 प्रतिशत भूमिहीन लोग भी हैं जो उस ज़मीन की खेती पर निर्भर रहते हैं क्या उनके लिए भी आपके पास कोई स्कीम है । उनके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे निवेदन है कि पहले हमारी पॉलिसी को पढ़ लें । हमने उनके लिए भी प्रावधान कर रखे हैं लेकिन ये पहले पॉलिसी पढ़ लें । (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Chautala ji, when you were in power did you make such type of provision in your acquisition policy? (Interruption).

डॉ. अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर पॉलिसी में चैंजिज आते रहते हैं और आपने सुझाव माँगा था इसलिए मैंने सुझाव दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Whether you had made such a provision or not? You are a very important component of your party. Did you make such type of provision? (Interruption).

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, ये कोई भी सुझाव देंगे I will always welcome. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अजय सिंह चौटाला : जब सुझाव दे रहे हैं तो आप बोलने की बात कह रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) पॉलिसी में संशोधन नहीं होते क्या?

Mr. Speaker : That means there was no provision. Let the Chief Minister continue. (Interruption).

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : जो आपने बात कही है उसका प्रावधान हमने 14 नम्बर स्कीम में किया हुआ है। I will always welcome और कोई भी इस तरह का सुझाव हो तो आप दे देना । (शोर एवं व्यवधान) Scheme for landless persons and artisans dependent upon agriculture operation over acquired land यह हमने प्रोवाइड किया है । There is another category of landless people in the rural setup who have traditionally been associated with the land owning families. These comprises of the land-less workers engaged in agriculture operation for generations under the Jajmani Custom and rural artisans i.e. blacksmith, carpenters, potters, masons, barbers etc. which together constitute the village society. It is a well-recognized fact. There is an association between land owners and the families of land-less persons in above category for generations and such associations are well known in the village setup. The Government is fully conscious of the adverse impact caused by acquisition of land of non-agricultural purposes of these dependent categories of the people. It has, therefore, been decided to lay a special focus on creation and up-gradation of skill sets of these people, their dependents to improve their employability in the organized sector. The Government has decided to take some measures for rehabilitation and resettlement of these persons. First, the Government would impart free technical education to dependents of these categories of these people in the Government-run Industrial Training Institutes and Polytechnics. Second, HSIIDC, HUDA and HSAMB would set apart a fund equal to one percent of the compensation amount for creating education skill sets among the dependents of land-oustees, owners and affected landless persons. HSIIDC would stipulate a condition for allottees for industrial plot to give preference to these people in employment, in industrial projects. Wherever land is acquired for private developers there would be required to make arrangements for creation and up-gradation of skill sets of the affected persons and preference in employment of affected persons, their dependents in project to set up such plan. इससे बेहतर अगर कोई सुझाव हो तो आप दे देना । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Don't interrupt the House please. (Interruption)

श्री रामपाल माजरा : अगर कोई अच्छी बातें हैं तो ये पौलिसी में शामिल कर लें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अभी नहीं, आप बाद में अपने सुझाव लिखकर दे दें ।

Mr. Speaker : Mr. Majra ji, You are interrupting. Did you seek my permission to speak ? (Interruption)

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, I am not yielding. He cannot stand like this. (Interruption) आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा ।

Mr. Speaker : No, you may kindly continue. Mr. Majra ji, you are a good parliamentarian. Alright let him complete. You know the tradition of this House. You will have enough opportunity to speak. (Interruption).

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दूसरा सवाल किसानों के हित के बारे में उठाया था । अध्यक्ष महोदय, 2008 में केन्द्रीय बजट में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और डाक्टर मनमोहन सिंह जी की यू.पी.ए. सरकार ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा किसान हितैषी फैसला किया और 72 हजार करोड़ रुपये का एक कलम से किसानों का कर्जा माफ किया । दुनिया में किसी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया और इसका लाभ 4 करोड़ 72 हजार किसानों को मिला । (विघ्न) हरियाणा के 7 लाख 15 हजार किसानों को 2136 करोड़ रुपयों का लाभ उस स्कीम से हुआ है । इन्होंने किसानों की फसलों की एम.एस.पी. के बारे में भी कहा ।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुन लें ।

Mr. Speaker : Majra ji, you cannot speak without my permission.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, किसान की और बेहतरी कैसे हो, किसान का आर्थिक आधार कैसे मजबूत हो क्योंकि किसान की जोत बहुत छोटी होती जा रही है, इस तरफ हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 2005 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय क्रॉप लोन के लिए किसान कोओपरेटिव बैंक से यदि कर्जा लेता था तो उसको यह कर्जा लेने के लिए 11 फीसदी की दर से ब्याज देना पड़ता था लेकिन हमारी सरकार आने के बाद आज क्रॉप लोन पर यह ब्याज चार फीसदी है । (शोर एवं व्यवधान)

वॉक–आऊट

Mr. Speaker : I will not let you walk out. (interruption) Are you making strategy to walk out? (Interruption).

डा0 अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये गलत ब्यानी कर रहे हैं । किसानों को तो कर्जा नहीं मिल रहा है । ये गलत ब्यानी कर रहे हैं और हाउस को मिसलीड कर रहे हैं । हम यहां पर झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो किसान समय पर कर्जा वापस दे देते हैं उनको चार फीसदी ब्याज लगता है ।

डॉ0 अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किसानों को तो लोन ही नहीं मिल रहा है। सारे किसान मारे-मारे फिर रहे हैं उनको लोन का एक पैसा नहीं मिल रहा है।

Mr. Speaker : Mr. Chautala ji, I am responsible for any false statement in the House. (Interruption) Smile on your face means you will walk out. (Interruption).

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार और श्री विशन लाल सैनी हाउस की बैल में आ गए और जोर जोर से बोलकर अध्यक्ष महोदय को कुछ कागज देने का प्रयास करने लगे।)

Mr. Speaker : Please go to your seat. (Interruption). Panwar Sahib, please sit down. Let him finish first. (Interruption). Alright I will see. पंवार साहब, आप पहले अपनी सीट पर जाएं। You can't pass the papers like this. Can you pass the papers like this to the Speaker? (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप इनके कागज देख तो लें । वे बैठ जाएंगे ।

Mr. Speaker : There is a procedure of the House. Can you come to me like this and pass the papers. (Interruption) You can't do this. There is a procedure of the House. (Interruption). You kindly adopt the procedure. Please do not disturb the House. (Interruption). I know you have gone to decide for walkout.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर दे दें ।

Mr. Speaker : Panwar Sahib, please take your seat. Let Mr. Chief Minister finish his reply.

डॉ0 अजय सिंह चौटाला : स्पीकर साहब, यह कोई तरीका नहीं है । आप हमारे एम.एल.ए. को तो धमका रहे हैं जबकि उस तरफ से खड़े करके उनको बोलने दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Chautala ji, please sit down. Go to your seat. (Interruption). आप लॉबी में गए थे क्या करके आए हैं। (विघ्न) Nothing is to be recorded here.

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, इन्होंने वाक-आउट करना है और इस बारे में ये गैलरी में जाकर सलाह करके आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Spepaker : There has been a very healthy discussion. In which you have participated. (Interruption) You all have participated but (Interruption) this is not fair that you want to walk out. It is not fair. (Interruption) It is not the law. It is not the procedure. Alright, can anybody pass papers like this to the speaker. (Interruption). No. No. don't rush to the well. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इनका यह क्या तरीका है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please go back to your seats. Go back to your seats, please. (Interruption) Mr. Saini go back to your seat. (Noise and interruption). Mr. Saini go back to your seat. (Noise and interruption). Hon'ble Members, is it decided. (Noise and interruption).

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रेट ऑफ इंट्रस्ट 4 परसैंट की दर से नहीं है बल्कि आज भी यह 11 और 14 प्रतिशत की दर से किसान से वसूल किया जा रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सदन में गलतबयानी कर रहे हैं । रेट ऑफ इंट्रेस्ट 4 परसैंट की दर से बता रहे हैं । जबकि यह रिकार्ड की बात है कि आज भी किसान से 11 और 14 प्रतिशत की दर से इंट्रस्ट लिया जा रहा है। हम आपको रिकार्ड दिखा सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रेट ऑफ इंट्रस्ट के मुद्दे पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है । अगर इस मुद्दे पर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम वाक-आउट करेंगे।

Mr. Speaker: Abhey ji, Hon'ble Members, go to your seats. You cannot throw papers into Speaker's face and I am not the Speaker on whose face you can throw any paper. (Interruption) Alright if you are preparing grounds for walking out. It is anticipated. आपका ऐक्शन एंटीसिपेटेड है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इन्होंने जाना है, इन्होंने फैसला किया है। अखबार में खबर बन गई है और इन्होंने अंदर जाकर ये निर्णय कर लिया था कि ये जाने वाले हैं । (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

Mr. Speaker : Ajay ji, are you walking out ? (Noise and Interruption) बैठिए-बैठिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रेट ऑफ इंट्रस्ट के मुद्दे पर सदन में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाक-आऊट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य एवं शिरोमणि अकाली दल के सदस्य श्री चरणजीत सिंह नारे लगाते हुए सदन से वॉक-आऊट कर गए ।)

Mr. Speaker : Why have they walked out and for what purpose?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो अपने आपको कहते हैं उनकी हर सैशन के अंदर ये रिवायत बन चुकी है। (विघ्न) अब आप अंदर हैं कि बाहर हैं, कम से कम एक निर्णय तो कर लीजिए ।

Mr. Speaker : Honourable Minister, I find no reason that any body should walk- out this House.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है और आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि सदन में लोकदल के सदस्यों के पास कोई माल मसाला नहीं है, न कोई सुझाव है, न कोई आलोचना करने को है । आपने दो दिन का समय दिया और उसमें इनके नेता ढाई घंटे बोले और ढाई घंटे की अवधि में उन्होंने ढाई सुझाव भी नहीं दिये। उसके बावजूद उनकी पार्टी के अध्यक्ष को उनके नेता के पुत्र को और माजरा जी को भी आपने बोलने के लिए पूरा समय दिया और भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग समय बोलने के लिए दिया ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, we are extending time of the sitting of the House again for half an hour because Hon'ble Chief Minister is to give reply and I will record your feelings, please. Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House is extended for half an hour ?

Voices: Yes, Sir.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, with the sense of the House the time of the sitting of the House is extended for half an hour.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर उनको ये लगता था कि इंट्रैस्ट सबवैंशन है (विघ्न) उसे 11 प्रतिशत से घटाकर

4 प्रतिशत पर लेकर आए थे । अब केन्द्रीय सरकार ने पूरे देश में आज हरियाणा की तर्ज पर किया है । आज श्रीमती सोनिया गान्धी जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की सरकार ने यह निर्णय लिया है । इन्होंने क्यों नहीं कहा उनके नेता जब बोल रहे थे तो अगर उन्होंने कहीं कोई दिक्कत थी तो वे बताते । पिछले छः साल हो गये । मैं एक बात रिकार्ड पर लाना चाहता हूं कि श्री ओमप्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी के किसी सदस्य ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, किसी मन्त्री को और किसी विधायक को या किसी सरकार के अधिकारी को लिखकर नहीं दिया कि कहीं चार प्रतिशत से ज्यादा ब्याज किसानों से चार्ज किया जा रहा है । मैं यह बात बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं । अगर चार प्रतिशत से एक रुपया भी अधिक किसी किसान से ब्याज लिया जायेगा तो जो अधिकारी ब्याज लेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे ।

Mr. Speaker : To my observation, members have walked out without any reason.

Shri B.B. Batra : Speaker Sir, this matter was referred by the Leader of Opposition regarding the dispute of the Punjab National Bank, Yamunanagar. This point does not relate to the cooperative bank. In spite of that request letter has been referred to RBI for inquiry whether this bank is charging more interests or not. He should reprimand for this letter.

Mr. Speaker : C.M Sahib, please continue your speech.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई को सुनना नहीं चाहते क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी ने सही बात कही है । मैं तो हरियाणा सरकार के सहकारी बैंकों की बात कर रहा था । मैं नेशनलाईज्ड बैंकों की बात नहीं कर रहा था । हमारे कोआप्रेटिव बैंकों में हमने फैसला लिया है कि जो किसान समय पर अपना लोन देते हैं उनसे चार प्रतिशत तक ब्याज लेगें । मैं माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने भी जो केन्द्रीय बजट पेश किया है उसमें पूरे देश के किसानों के लिए चार प्रतिशत ब्याज कर दिया है जिसे हरियाणा सरकार ने पहले ही कर दिया है। मैं आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री जी का और श्रीमती सोनिया गान्धी जी का । जब चीफ मिनिस्टर्ज की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे उस समय सारे देश के मुख्यमंत्री जी वहां पर आये थे । उस समय उन्होंने किसानों के sustainable agricultural products के बारे में चीफ मिनिस्टर्ज का एक वर्किंग ग्रुप बनाया था। मेरे को इस वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष मनोनित किया गया था और मेरे साथ पंजाब, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे । उसने रिपोर्ट दी कि हरियाणा की तर्ज पर आज केन्द्रीय सरकार ने भी किसानों के लिए चार प्रतिशत ब्याज दिया है । श्रीमती सोनिया गान्धी के नेतृत्व में और डाक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह चार प्रतिशत ब्याज उसी किसान से लिया जायेगा जो समय पर अपना कर्जा चुका देगा । उसको अब पूरे देश में कर दिया गया है। क्रेडिट फलो फारमर्ज में एक लाख करोड़ रुपये का

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
इजाफा हुआ है जो पहले 3 करोड़ 75 लाख रूपये था वह अब 4 करोड़ 75 लाख रुपये हो गया है जिसमें एक लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Mr. Vij, I am not taking notice of you. Point of order is a different thing.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं

Mr. Speaker : I spare you for address but you will not speak. (Interruption) Are you speaking with my permission? You please resume your seat. Please, I am on my legs. (Interruption)

Sh. Anil Vij : Speaker Sir, please give me permission to speak.

Mr. Speaker : You should kindly restrict yourself that whenever you want to speak raise your hand but you did not do that.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I have raised my hand.

Mr. Speaker : No, earlier when you wanted to speak you did not do that.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, now I have raised my hand.

Mr. Speaker : No, not earlier.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, now I have raised my hand.

Mr. Speaker : Mr. Anil Vij please, if you have respect for the Chair, raise your hand first.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I have full respect for the Chair.

Mr. Speaker : As and when you started speaking, you did not raise your hand. You started speaking without raising your hand. (Interruption) No interruption please. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा केन्द्र में जो बजट पेश किया गया है उसमें प्रणव जी ने एक नई बात कही है कि किसानों को जो फर्टीलाइजर पर सबसिडी दी जाती है वह डायरैक्ट दी जाएगी । (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी चीजों पर रियायतें दी हैं । (शोर एवं व्यवधान) जो डिजिज फ्री सीड्स हैं उसके सर्टिफिकेशन वगैरह पर सर्विस टैक्स में भी एग्जम्पट किया है । (शोर एवं व्यवधान) इस प्रकार से केन्द्रीय बजट में बहुत सी रियायतें किसानों को दी गई हैं उसके लिए हम उनका अभार व्यक्त करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij , you are very senior member please do not speak without the permission of the Chair.

श्री अनिल विज : आप हमारी तरफ देखते नहीं । (शोर एवं व्यवधान) मैंने हाथ खड़ा किया था । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : You did not raise your hand.

श्री अनिल विज : मैंने हाथ खड़ा किया था । (शोर एवं व्यवधान) I have raised my hand.

Mr. Speaker : Now, you are raising your hand but at that point of time you did not. That is not good. You always stand up on your seat and start to speak. Yes, Mr. Gurjar, what do you want to speak ?

Shri Krishan Pal Gurjar : Speaker Sir,. . . . . (Interruption)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, you have allowed Mr. Gurjar, but why you have not allowed me to speak ?

Mr. Speaker : I will not allow you because you did not ask me earlier.

Shri Anil Vij : Speaker Sir, I have asked you. I have raised my hand.

Mr. Speaker : Now you are asking me this time. (Interruption)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि विज जी इस हाउस के बहुत सीनियर सदस्य हैं । हमने अपनी बात कही और उन्होंने हमारी बात सुनी । हम भी मुख्यमंत्री महोदय जी की बात को इमानदारी से सुनना चाहते हैं । हम भागना नहीं चाहते । मुख्यमंत्री जी जो रिप्लाई देना चाहते हैं उसको पूरी तरह से हम सुनना चाहते हैं इसलिए कोई इतना सीनियर सदस्य बीच में कोई प्वांयट आफ आर्डर मांग रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उनको सुनना चाहते हैं । जब उन्होंने हमें सुना है तो हम भी इनको सुनना चाहते हैं । हम भागना नहीं चाहते इसलिए मेरा निवेदन है कि जब विज साहब ने एक सवाल पूछने के लिए कहा है तो उनको मौका दे दिया जाना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

Mr. Speaker : Mr. Gurjar you are heading this party in the State. Mr. Vij is a very senior member of this House. Probably जितनी मेरी उम्र है इतने सालों से ये हाउस में हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बोलने के लिए परमीशन ऑफ दि चेयर रिक्वायर्ड नहीं है ।

श्री अनिल विज : मैंने परमीशन मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष : उस समय आपने परमीशन नहीं मांगी थी इसलिए आपको परमीशन नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अब तो ये परमीशन मांग रहे हैं इसलिए आप इन्हें एक मिनट का समय दे देंगे तो क्या हो जाएगा ? फिर आप कहेंगे कि हम चौटाला के पीछे भाग गए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अब परमीशन मांग रहा हूं । मैंने केवल एक शब्द ही तो पूछना है ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप उनके पीछे भगाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप उनके पीछे नहीं भागते बल्कि जब जब भी आप भागे हो तब तब आप पछताए हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अब आप देख रहे हैं कि मेरा हाथ खड़ा है । (शोर एवं व्यवधान) आप मुझे बोलने नहीं दे रहे । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Alright, Mr. Vij.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने अभी कहा है कि जो किसान समय पर अपना ऋण जमा करा देंगे उनको 4 परसैंट ब्याज पर ऋण दिया जाएगा । इस बात का ढिंढोरा भी पीटा गया, केन्द्र में भी ढिंढोरा पीटा गया । अपने प्रदेश में कितने किसान हैं या कितने परसैंट किसान हैं जो समय पर ऋण जमा करवा पाते हैं और जिनको 4 परसैंट पर ब्याज का लाभ मिल पाता है । किसान तो साहूकारों के चक्कर में फंसा हुआ है । किसान तो नैशनैलाइज्ड बैंकों के चक्कर में फंसा हुआ है ।

Mr. Speaker : You are started making a speech. (Interruption) As per rule on a point of order you can't ask a question. Here is the rule book. No, you can't ask question. (Interruption) Here is the holy book of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly, you may read it.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसमें फरदर एक्सप्लेनेशन चाहता हूं । मैं कोई एक्स्ट्रा क्वैश्चन नहीं कर रहा ।

Mr. Speaker : O.K. next time I will allow you on a point of order. Do you promise next time you will not ask a question on a point or order. (Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, विज साहब हमारे पुराने साथी हैं । ये पहले भी मेरे साथ विधायक रहे हैं । ये ठीक आदमी हैं । अध्यक्ष महोदय, कृष्णपाल गुर्जर जी कह रहे थे कि

आप उनको जो साथी चले गये उनके साथ जाने को मजबूर कर रहे हो । अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इन्होंने उनके साथ रहकर देख लिया उनकी तासीर है कि जो दल उनका साथ देता है बाद में उसका भोजन बनाकर खाते हैं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : ये लोग बड़ी जल्दी बाहर जाते हैं और जल्दी ही वापिस आ जाते हैं इस बारे में मैं आपको एक शेयर सुनाना चाहता हूं :-

शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप,
महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विज साहब का सवाल है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हम जो क्रोप लोन 4 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को देते हैं उसकी 60 से 65 प्रतिशत रिकवरी हो जाती है । अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट में भी बहुत सारी किसान हितैषी चीजें हैं उसके लिए मैं यू.पी.ए. सरकार का आभारी हूं लेकिन कल विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को कृषि के बारे में तोड़-मरोड़कर पेश किया । माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह चिंता जाहिर की है कि कृषि का प्रोडैक्शन स्थिर हो गया है या कुछ कम हो गया है जो सरकूलेशन प्वायंट पर पहुंच गया है और उसके उन्होंने कुछ कारण भी दिए हैं । चाहे सोयल हैल्थ खराब होने की बात है, चाहे पानी का लैवल नीचे जाने की बात है लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको तोड़ मरोड़ कर अपने भाषण में प्रस्तुत किया । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चौटाला जी के शासन के दौरान गेहूं की उत्पादकता 4165 किलो प्रति हैक्टेयर थी जो हमारे समय में बढ़कर 4614 किलो प्रति हैक्टेयर हो गई । आज हमारा प्रदेश गेहूं की उत्पादकता के मामले में नम्बर एक पर है, पंजाब से भी आगे है । इसी तरह से 1999-2000 में गेहूं का उत्पादन हरियाणा में 96.50 लाख मिट्रिक टन था जो 2008-09 में बढ़कर 113.60 मिट्रिक टन हो गया है । इसी तरह से इनके समय में धान की उत्पादकता 2385 किलो प्रति हैक्टेयर थी जो हमारे समय में बढ़कर 3008 किलो प्रति हैक्टेयर हो गई है । इसी तरह से सरसों की उत्पादकता 5.9 लाख मिट्रिक टन से बढ़कर हमारे समय में 8.4 लाख मिट्रिक टन हो गई है जो कि 25 प्रतिशत अधिक है । अध्यक्ष महोदय, गेहूं और सरसों की उत्पादकता में हरियाणा पूरे देश में पहले नम्बर पर है । जहां तक एम.एस.पी. का सवाल है 27 मई, 2004 को यू.पी.ए. सरकार केन्द्र में सत्ता में आई थी उस समय गेहूं का भाव 630 रूपये प्रति क्विंटल था जिसमें 4-5 साल में हमारी सरकार ने 490 रूपये प्रति क्विंटल का ईजाफा किया है । इनकी सरकार के समय में गेहूं का रेट पांच साल में 580 रूपये से बढ़ाकर 630 रुपये किया गया था । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 4-5 साल के अंदर गेहूं का भाव 490 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है और इनकी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान केवल 50 रुपये प्रति क्विंटल ही बढ़ाया गया था । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से धान की एम.एस.पी. भी हमारी सरकार के समय में बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके विपरीत विपक्ष के साथियों की सरकार के समय में नहीं के बराबर बढ़ोतरी हुई । इसी प्रकार से गन्ने की बात भी सदन में आई। गन्ने का भाव भी हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा दे रही है । वर्ष 2003-04 में गन्ने का

[भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल था और आज 2010-11 के दौरान वह बढ़कर 220 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है यानि इस प्रकार से देखा जाये तो गन्ने के मूल्य में 100 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा रोहतक शूगर मिल का भी जिक्र किया गया। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि रोहतक शूगर मिल की कैपेसिटी प्रतिदिन 3500 टन गन्ना पीड़ने की है जबकि प्रदेश की अन्य शूगर मिलों के मामले में यह फीगर 2500 टन प्रतिदिन है । रोहतक शूगर मिल से पहले जितनी भी शूगर मिल्स हरियाणा में स्थापित की गई वे या तो पंचायत से मुफ्त ज़मीन लेकर लगाई गई अथवा लोगों से अगर शूगर मिल लगाने के लिए ज़मीन ली भी गई तो उस ज़मीन का नहीं के बराबर ही भाव दिया गया लेकिन रोहतक शूगर मिल के लिए हमने 26 करोड़ 96 लाख रूपये किसानों की ज़मीन की कीमत दी है और 44 करोड़ रुपये को-जैनरेशन पर लगाये जिसकी आज के दिन 8 प्रतिशत रिकवरी है और इस समय यह शूगर मिल 85 प्रतिशत कैपेसिटी पर काम कर रही है । शुरू-शुरू में जो टीचिंग प्रॉब्लम होती है वह हो गई । इसी प्रकार से हमारी सरकार नेचुरल कलैमिटी फण्ड में भी केन्द्र सरकार से बढ़कर हिस्सा देती है । अभी जो प्रदेश में फ्लड आया उसमें किसानों को 257 करोड़ रुपये मुआवज़े के तौर पर दिये गये । इसके साथ-साथ सिंचाई के सम्बंध में यहां पर हांसी-बुटाना लिंक नहर का जिक्र भी किया गया । हांसी-बुटाना नहर का जहां तक संबंध है उसका कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है और उसको केवल भाखड़ा से जोड़ने का काम ही बाकी रह गया है। इस नहर पर 392 करोड़ रुपये की लागत आई है और इसकी कैपेसिटी 2000 क्युसिक है । यह नहर दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। इस नहर का निर्माण दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी था । पूरे प्रदेश में नहरी पानी के न्यायोचित बंटवारे के लिए भी इस नहर का निर्माण जरूरी था । बहुत से लोगों ने इस नहर के निर्माण का विरोध भी किया। हरियाणा को मौजूदा समय में 1.62 एम.ए.एफ. पानी मिलता है । इसमें से 0.8 एम.ए.एफ. पानी इस नहर के माध्यम से दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में जायेगा ताकि दक्षिणी हरियाणा में भी पानी अंतिम छोर तक पहुंच सके । यह बात बिल्कुल बेबुनियाद, गलत और असत्य है कि टैक्नीकली यह नहर नॉन-वॉयबल है । यह नहर पूर्ण रूप से वॉयबल है । आई.आई.टी., रूड़की और सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा इस नहर का निरीक्षण किया गया है । उन्होंने भी इस बात को माना है कि यह नहर प्रत्येक दृष्टिकोण से फिजीबल भी है और वॉयबल भी है । इस मामले में मैं एक और जानकारी इस पूरे सदन को देना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नहर के निर्माण का विरोध नहीं किया गया है बल्कि केवल पंक्चर करने पर ही स्टे दिया गया है । मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही यह स्टे भी वैकेट हो जायेगा और जैसा कल हमारे सिंचाई मंत्री जी ने भी कहा था कि दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर तक वहां की जनता के हक के पानी की एक-एक बूंद वहां हरियाणा सरकार पहुंचाकर रहेगी । इसी प्रकार से हमारी और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जैसे दादुपुर-नलवी, ओटू झील, और एस.वाई.एल. इत्यादि । एस.वाई.एल. के बारे में जो यहां बात की गई उसके बारे में हमारे मंत्री जी ने बताया कि यह बात गलत है और बेबुनियाद है कि हरियाणा सरकार एस.वाई.एल. के निर्माण के प्रति सीरियस नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. के निर्माण को लेकर हमारी सरकार पूर्ण रूप

से सीरियस है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं । वर्ष 2011 में हमने एक और एक्वीजीशन दायर की है ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी इसका फैसला करे और जो 04.06.2004 को फैसला हुआ था वह लागू करवाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं । बाढ़ के बारे में भी इस सदन में जिक्र हुआ था । बाढ़ की रोकथाम के लिए अगले दो सालों के लिए हमने 251 स्कीम्ज़ बनाई हैं जिन पर 644 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इस बार जो 2 लाख एकड़ भूमि पर वाटर फ्लड आया था उसमें से अभी भी तीन हज़ार एकड़ के करीब ऐसा रकबा है जिसका पानी अभी तक नहीं निकल सका है । इसका भी हम कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे और कोई न कोई ऐसी स्कीम अवश्य बनायेंगे जिससे कि आगे कभी इस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न न हों । अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई । श्री अजय चौटाला जी ने इसकी चर्चा की जो कि इस समय सदन में उपस्थित नहीं है । इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का सवाल है यह प्लांट 95 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर कार्य कर रहा है । इस सम्बन्ध में किसी इंजीनियर का नाम लिया गया । उन्होंने कहा कि जो गोल्ड मैडल दिया गया है वह तो केन्द्र सरकार ने दिया है । किसी इंजीनियर की चिट्ठी का जिक्र किया, उनको यह तथ्य नहीं मालूम कि वह कौनसा इंजीनियर था, कहाँ का था? वह पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का है और उन्होंने ईर्ष्यावश यह बात कही है कि उनको गोल्ड मैडल नहीं देना चाहिए था । हमारे किसी इंजीनियर ने यह नहीं लिखा है क्योंकि पंजाब में कोई भी प्रोजैक्ट इतने कम समय में तैयार नहीं हुआ है । इसी प्रकार से राजीव गाँधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ के बारे में जो इन्होंने चर्चा की, उस पर 3775 करोड़ रुपये की लागत आई है और आज भी उसकी दोनों यूनिट 1000 से लेकर 1100 मैगावाट तक बिजली पैदा कर रही हैं । इसकी पहली यूनिट 10 अप्रैल, 2010 में चालू हो गई और उससे 600 मैगावाट का उत्पादन शुरू हुआ लेकिन उसका कमर्शियल पीरियड 24.8.2010 का था । उन्होंने जिस बात का जिक्र किया था उनको पता नहीं था कि कमर्शियल पीरियड अलग होता है और इसके अलग पैरामीटर होते हैं । उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन 24.8.2010 को शुरू हो गई । दूसरी यूनिट जो 1 अक्तूबर, 2010 को 600 मैगावाट के लिए लगाई थी, उसका कमर्शियल ऑप्रेशन 1 मार्च, 2011 में शुरू हुआ है । आज भी वे दोनों यूनिट 1000 से लेकर 1100 मैगावाट बिजली पैदा कर रही हैं । इंदिरा गाँधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झाड़ली 1500 मैगावाट का है तथा उस पर 7892 करोड़ रुपये की लागत आई है तथा वह भी जल्दी ही उत्पादन शुरू कर देगा तथा कार्य जोरों पर चल रहा है । इस परियोजना में 500 मैगावाट की पहली इकाई 1 नवम्बर, 2010 को चालू हो चुकी है तथा दूसरी और तीसरी इकाइयाँ भी जल्दी ही आने वाली हैं । इसके अतिरिक्त, झज्जर में महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना झाड़ली 1320 मैगावाट का 10 जनवरी, 2009 को निर्माण शुरू हुआ है और दिसम्बर, 2011 तक बिजली का उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है । इसके अलावा 1724 मैगावाट बिजली की 25 साल के लिए खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्ष 2012 तक यह बिजली हमें मिलनी शुरू हो जायेगी । इसी प्रकार से फरीदाबाद के बारे में बताया गया कि यूनिट बंद पड़ी हैं । अध्यक्ष महोदय, ये तीनों यूनिट इसलिए बंद पड़ी हैं क्योंकि वे बहुत पुरानी हो चुकी हैं और प्रदूषण ज्यादा फैला रही थी । इसलिए वर्ष 2008 से 2010 के बीच इनको बंद करना उचित समझा गया

[भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

था । ये तीनों इंकाइयाँ 165 मैगावाट की थी । अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि 2008-2009 में 300-300 मैगावाट की दो यूनिट खेदड़ में लगाई जा रही हैं और उनमें से एक ने उत्पादन शुरू कर दिया था । इसलिए फरीदाबाद की तीनों इकाइयों को हमने जानबूझ कर बंद किया था क्योंकि उन पर खर्चा भी ज्यादा आ रहा था और वातावरण को भी ज्यादा प्रदूषित कर रही थी । इन 6 वर्षों में हमने इनकल्यूसिव डिवैल्पमैंट की है । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा एक बहुत अनिवार्य चीज है । आप अगले 5-7 साल में देखेंगे कि हरियाणा एक शिक्षा का हब बनेगा । उससे पहले चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार रही और हमारे एक और मुख्य मंत्री थे वे भी बहुत देर तक मुख्य मंत्री रहे । उससे पहले चौ. बंसी लाल शुरू में मुख्य मंत्री रहे । इन्होंने दो यूनिवर्सिटीज, एक चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने और एक चौधरी भजनलाल ने बनवाई थी । एक तो चौ. ओमप्रकाश चौटाला ने अपने गृह जिले सिरसा में अपने स्व0 पिता चौधरी देवी लाल के नाम से बनाई । कोई बात नहीं हमारे बुजुर्ग थे, बना दी । इसी प्रकार से चौधरी भजनलाल ने यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई, अपने गृह जिले में । किसके नाम से बनाई ? अपने गुरू के नाम से । हमारी देखो, अध्यक्ष महोदय, करनाल में कल्पना चावला के नाम से मैडीकल कॉलेज बन रहा है । उससे आगे आप सोनीपत में देखिए, भगत फूल सिंह के नाम से महिला यूनिवर्सिटी बनी है तथा चौधरी छोटू राम के नाम से साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है ।

Mr. Speaker : Hon'ble C.M., is there any medical institute in Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidhayala Khanpur Kalan for Women also?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Yes, Sir Medical College is being constructed there.

Mr. Speaker : Then why it is not mentioned?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, वह भी बन रहा हैं तथा उस पर 300 करोड़ रूपये लग रहे हैं, मैं मैडीकल कॉलेज पर भी आऊंगा । मैं बता रहा हूँ कि सोनीपत में आपके जिले में राजीव गाँधी एजूकेशन सिटी आ रही है । भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी बन गई, मैडिकल कॉलेज बन रहा है, मुरथल में चौधरी छोटूराम के नाम से साइंटिफिक यूनिवर्सिटी बनी है । ये सब हमारे समय में बनी हैं । इसके बाद आप फरीदाबाद में चले जायें वहाँ पर वाई.एम.सी.ए. की जगह यूनिवर्सिटी हमने बनाई है । उसके बाद आप गुड़गाँव चले जायें वहाँ पर हिन्दुस्तान की सबसे पहली डिफैन्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है । उससे आगे रेवाड़ी में दूसरा सैनिक स्कूल बनने जा रहा है । एक सबसे बड़ी सैंट्रल यूनिवर्सिटी कई सौ एकड़ में महेन्द्रगढ़ में बनाने जा रहे हैं । हिसार में तो दो यूनिवर्सिटीज पहले ही थीं लेकिन हम एक और नयी यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय के नाम से वैटेनरी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के नाम सिरसा में जो यूनिवर्सिटी है उसमें केवल वे चार कमरे बनाकर गए थे लेकिन आज आप जाकर देखें हमने वहां पर काफी रूपया लगाया है । झज्जर में एम्ज आ रहा है, रोहतक में आई.आई.एम. आ रहा है और मैडीकल

यूनिवर्सिटी बनी है । अम्बाला में मुलाना में एक यूनिवर्सिटी पहले से ही है और एक और आ रही है, कैथल में भी एक यूनिवर्सिटी आ रही है, मेवात में एक मैडीकल कालेज बन रहा है, सोनीपत में एक जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है । इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में इन्होंने तो केवल एक ही यूनिवर्सिटी बनायी थी और वह भी अपने जिले में चौधरी देवीलाल जी के नाम से बनायी थी लेकिन इसके अलावा अगर उन्होंने कोई और यूनिवर्सिटी या इंस्टीच्यूशन बनाए हों तो मैं जिम्मेवार हूं ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, हमने इनकी सारी बातें देख ली इसलिए इनका कोई मुकाबला ही नहीं है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अनुसूचित जाति और समाज कल्याण के विभाग का 2004-05 में बजट 402 करोड़ रुपये था लेकिन 2010-11 में इस बजट को बढ़ाकर 1581 करोड़ रुपये किया गया है । बुढ़ापा पैंशन का बजट 2004-05 में 259 करोड़ रुपये था जिसको 2010-11 मे बढ़ाकर 908 करोड़ रुपये किया गया है । जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो उस समय प्लांड बजट का एक्सपैंडीचर 2100 कुछ का था लेकिन आज डेढ़ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बजट की तो हम लोगों को पेंशन ही दे रहे हैं । इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग का बजट 2003-04 में केवल 47.40 करोड़ रुपये था जोकि 2011-12 में बढ़कर 346.12 करोड़ रुपये हो गया है । इसी प्रकार से सभी अनुसूचित जातियों के परिवारों को, बी.सी.ए. के परिवारों को, बी.पी.एल. के परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट्स देने का कार्य किया गया है। अब तक 3.4 लाख परिवारों को प्लाट्स दिए जा चुके हैं तथा औरों को भी हम दे रहे हैं । अनुसूचित जातियों के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को सौ रुपये से लेकर चार सौ रुपये तक वजीफा हम दे रहे हैं । अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 280 करोड़ रुपये का एक पैकेज भी हमने लागू किया है । इसी प्रकार से सरकारी पोलेटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित बच्चों की ट्यूशन फीस का खर्चा भी सरकार वहन कर रही है । इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम में अनुसूचित जातियों के आठ लाख परिवारों को मुफ्त कनैक्शन दिये जाएंगे । 31 जनवरी, 2010 तक 5 लाख 13 हजार कनैक्शन दिए जा चुके हैं । इसके साथ ही 200 लीटर की पानी की टंकी भी साथ में उनको दे रहे हैं । इसी तरह से मनरेगा की स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में सरकार कड़ी निगरानी रख रही है लेकिन उनमें कुछ शिकायतें आयी हैं और कुछ अनियमितताएं पायी गयी हैं । अम्बाला में कुछ अनियमितताएं नोटिस में आयी हैं लेकिन हमने उनकी जांच करने के लिऐ आदेश दे दिए हैं । उनकी जांच विजीलैन्स कर रही है । दूसरे जिलों से भी अनियमितताएं ध्यान में आयी हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की गयी है और की जाएगी ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the Sitting be extended till the business of the House is concluded.

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The time of the Sitting of the House is extended till the business of the House is concluded.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भण)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोगों को रोजगार देने के लिए है। आज मनरेगा स्कीम के तहत 3 लाख 80 हजार खाते खुल चुके हैं। इस स्कीम में हरियाणा में जो मजदूरी दी जाती है वह देश में सबसे अधिक दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में मनरेगा स्कीम के तहत 179 रुपये सबसे अधिक हमारे यहां पर दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शिक्षा के बारे में जिक्र किया । शिक्षा और स्वास्थ्य दो प्राइमरी ऐसी चीजें हैं जो समाज को उठाने का कार्य करती हैं। मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इसकी तुलना करना चाहता हूं । शिक्षा का कुल बजट 2004-05 में 1507 करोड़ रुपये था, आज 2010-11 में 5742 करोड़ रुपये का बजट दिया है और इस प्रकार इसमें 380 गुना वृद्धि हुई है। जैसा मैंने कहा कि बी.पी.एल. परिवारों के 19 हजार बच्चों को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा वजीफा दिया जा रहा है । हैल्थ की मद में 2004-05 में 292 करोड़ रुपये का बजट था जो कि आज के दिन वर्ष 2010-11 में बढ़कर 1619 करोड़ रुपये हो गया है। 3 मैडीकल कालेज भी नये बनाए जा रहे हैं । इसी प्रकार से महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया। महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं । बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम किया है । इंडस्ट्रीज में पर कैपिटा इन्कम के मामले में हिंदुस्तान में हरियाणा 14वें नंबर पर हुआ करता था और आज एक नंबर पर है । पर कैपिटा इन्कम के मामले में भी गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है । विपक्ष के नेता को इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को बधाई देनी चाहिए थी। एस.ई.जेड के मामले में कहा गया कि एस.ई.जेड के लिए 76 हजार एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि केवल रिलायंस के साथ एम.ओ.यू. हुआ है उसके अलावा एक इंच जमीन भी इसके लिए ऐक्वायर नहीं की गई है । मैंने कल भी सदन में कहा था कि यदि इसके अलावा एक इंच जमीन भी दी गई हो तो या तो ये इस्तीफा दे देंगे या मैं दे दूंगा । लेकिन उनकी बिना तथ्यों के बात करने की आदत है । विपक्ष के नेता मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं, वृद्ध हो गए हैं, 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र हो गई है। वृद्धावस्था के बाद सन्यास अवस्था होती है । (विघ्न) मेरे को इस बारे में मालूम है और वे बैठे होते तो मैं उनको ये बात कहता । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, वे सन्यास तो नहीं लेंगे, ये मेरे को मालूम है । वे पिछली बार जब हाउस में थे तो ये कहा करते थे कि जब तक यहां रहूंगा तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा। वे दूसरों की छाती पर मूंग दलते हैं। सारी उम्र के लिए यहां बैठने की सोचते होंगे। वे सन्यास तो नहीं लेंगे। इस बारे में मैं एक बात सुनाना चाहूंगा । एक दांतों का डाक्टर था वह कहने लगा कि मैं दांतों का बहुत ही अच्छा डाक्टर हूं, किसी के दांत दर्द करते हों तो उसकी तकलीफ लाजिमी दूर कर दूंगा। उस डॉक्टर ने एक दवाई की शीशी रखी हुई थी । वह क्या करता कि जब कोई दांत दर्द वाला उनके पास आता तो उसकी आंख में दवाई डाल देता। दवाई के रूप में उसने पानी में लाल मिर्च घोल रखी थी ,

17.00 बजे

उससे यह होता था कि मरीज दांत का दर्द तो भूल जाता था और आंख का शुरू हो जाता था । इनके समय में किसानों के साथ कुठाराघात हुआ था और लोग उसे भूलेंगे नहीं । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और मैंने यह बात पिछले सदन में भी कही थी कि वे सन्यास तो नहीं लेंगे लेकिन उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि-

सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है
न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब उनकी उम्र हो गई है अब उनको अपने बच्चों को तो आगे करना ही चाहिए ।

Mr. Speaker : Distance to God is a long distance. He cannot walk it probably.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं अपने बारे में एक ही बात कहता हूँ।

हम नहीं कहते कि इस जमाने को जन्नत बना दिया है हमने,
मगर कुछ खार जरूर कम हुए हैं गुजरे हैं जिधर से हम।
मुँह जो बात कहे वही पत्थर की लकीर,
शामों सहर के साथ नहीं बदलते हैं हम।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सी.एम. साहब, हम आपके शायराने और गालिबाने अंदाज से तो आज पहली बार मुखातिब हुए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैंने तो इनको पिछली बार भी सुनाया था।

Mr. Speaker : Hon'ble Members we have some business to transact after the reply by the Hon'ble Chief Minister.

Mr. Speaker : Question is-

"That an address be presented to the Governor in the following terms:-

That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 4th March, 2011 at 2.00 P.M."

The motion was carried.

Mr. Speaker : We will send a Motion of Thanks to the Hon'ble Governor.

वर्ष 2010-2011 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will kindly present the Supplementary Estimates (Second Instalment)-2010-2011.

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment)-2010-2011.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Now, Rao Dharampal, Chairperson Committee on Estimates will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment)-2010-2011.

Rao Dharampal (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment)-2010-2011.

वर्ष 2010-2011 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on the Demands for Supplementary Estimates (Second Instalment) 2010-2011 will take place. As per the past practice and in order to save the time of the House, the demands on the order paper (No.1 to 6, 8 to 30, 32 to 44 and 46) will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise discussion.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 5,35,08,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 12,53,47,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of Demand No. 2- Governor and Council of Ministers.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ 2,63,70,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 3- General Administration**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **129,62,21,316/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 4- Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **8,62,59,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **774,85,43,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **149,95,79,000/-** for revenue expenditure and ₹ **1,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 8- Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **123,68,56,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 9- Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **22,39,45,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 10- Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **29,93,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 11- Sports and Youth Services.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,16,19,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 12- Art & Culture.**

[श्री अध्यक्ष]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **200,74,98,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 13- Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,32,45,000/-** for revenue expenditure and ₹ **353,01,56,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 14- Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **212,24,96,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 15- Local Government.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,23,93,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 16- Labour.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,74,70,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 17- Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **13,14,22,000/-** for revenue expenditure and ₹ **85,83,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 18- Industrial Training.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **71,12,76,398/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 19- Welfare of SCs & BCs.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **136,87,43,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 20- Social Security and Welfare.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **5,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 21- Women and Child Development**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **9,72,71,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 22- Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **371,53,19,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 23- Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **71,76,18,000/-** for revenue expenditure and ₹ **68,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 24- Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,17,79,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 25- Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **40,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 26- Mines & Geology.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **113,94,32,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 27- Agriculture.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **38,79,42,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 28- Animal Husbandry and Dairy Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,71,99,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 29- Fisheries.**

[श्री अध्यक्ष]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **12,12,88,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 30- Forest & Wild Life.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **100,01,78,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 32- Rural & Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **4,31,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 33- Co-operation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **108,00,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 34- Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 35- Tourism.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **199,42,93,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 36- Home.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,50,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 37- Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **102,59,11,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 38- Public Health and Water Supply.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,06,33,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 39- Information and Publicity.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **237,28,23,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 40- Power.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,10,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 41- Electronics and IT.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **52,68,64,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 42- Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **10,66,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 43- Prisons.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **39,78,000/-** for revenue expenditure and ₹ **30,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 44- Printing and Stationery.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **190,00,00,000/-** for raising the corpus of Haryana Contingency Fund be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for unseen expenditure and new services in respect of **Demand No. 46- Contingency Fund.**

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker : Now, the demands will be put to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **5,35,08,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 1- Vidhan Sabha.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **12,53,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year

[श्री अध्यक्ष]

ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 2- Governor and Council of Ministers.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,63,70,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 3- General Administration**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **129,62,21,316/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 4- Revenue.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **8,62,59,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 5-Excise & Taxation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **774,85,43,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **149,95,79,000/-** for revenue expenditure and ₹ **1,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 8- Buildings & Roads.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **123,68,56,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 9- Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **22,39,45,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 10- Technical Education.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **29,93,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 11- Sports and Youth Services.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,16,19,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 12- Art & Culture.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **200,74,98,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 13- Health.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,32,45,000/-** for revenue expenditure and ₹ **353,01,56,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 14- Urban Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **212,24,96,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 15- Local Government.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,23,93,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 16- Labour.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,74,70,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 17- Employment.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **13,14,22,000/-** for revenue expenditure and ₹ **85,83,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 18- Industrial Training.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **71,12,76,398/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 19- Welfare of SCs & BCs.**

[श्री अध्यक्ष]

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **136,87,43,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 20- Social Security and Welfare**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **5,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 21- Women and Child Development**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **9,72,71,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 22- Welfare of Ex-Servicemen.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **371,53,19,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 23- Food & Supplies.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **71,76,18,000/-** for revenue expenditure and ₹ **68,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 24- Irrigation.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **1,17,79,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 25- Industries.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **40,16,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 26- Mines & Geology.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **113,94,32,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 27- Agriculture**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **38,79,42,000/-** for

revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 28- Animal Husbandry and Dairy Development**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,71,99,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 29- Fisheries**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **12,12,88,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 30- Forest & Wild Life.**

(The motion was carried)

Mr. Speaker : Question is :-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **100,01,78,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 32- Rural & Community Development.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **4,31,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 33- Co-operation**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **108,00,39,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 34- Transport.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **20,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 35- Tourism**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **199,42,93,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 36- Home**.

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,50,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

[श्री अध्यक्ष]

charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 37- Elections.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **102,59,11,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 38- Public Health and Water Supply.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **2,06,33,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 39- Information and Publicity.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **237,28,23,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 40- Power.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **3,10,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 41- Electronics and IT.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **52,68,64,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 42- Administration of Justice.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **10,66,25,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 43- Prisons.**

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **39,78,000/-** for revenue expenditure and ₹ **30,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2011 in respect of **Demand No. 44- Printing and Stationery.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is :-

That a Supplementary sum not exceeding ₹ **190,00,00,000/-** for raising the corpus of Haryana Contingency Fund be granted to the Governor to defray charges that will come in the course

of payment for unseen expenditure and new services in respect of **Demand No. 46- Contingency Fund.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have the pleasure to inform you that this has been the longest marathon Sitting of the House so far. We started at 10.30 A.M. and now it is 5.10 P.M.

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, एक रिक्वैस्ट है। आज डबल सीटिंग हो गई । जब भी कभी इस तरह करो तो दोपहर के खाने का इंतजाम कर दिया करो। सारे मैंबर्स भूखे हैं।

Mr. Speaker : Alright, we will take care of that. Parliamentary Affairs Minister is instructed to kindly take care of this.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, we will take care of. It has already been suggested by Dangi Sahib, Shri Venod Sharma and by our Learned Senior Ministers also. We will take care of in future.

Mr. Speaker : Alright.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 10.30 A.M. tomorrow, the 9th March, 2011. Thank you Members.

*17.10 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 10.30 A.M. on Wednesday, the 9th March, 2011).

48757—HVS—H.G.P., Chd.